राष्ट्रीय संस्करण

अनुच्छेद 370 पर निर्णय थोपने की जगह सहमति से चाहता था ›› 4

वर्ष 8 अंक 58

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, मंगलवार, 6 अगस्त, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

बांग्लादेश में तख्तापलट

हसीना इस्तीफा देकर भारत पहुंचीं, पड़ोसी देश में अराजक माहौल

मार्च के आह्वान के बाद ढाका पहुंचे छात्रों ने किया राजधानी पर कब्जा

पीएम आवास में घुसकर उपद्रवियों ने की तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी

सेनाध्यक्ष ने अंतरिम सरकार का दिया भरोसा, सारी जिम्मेदारी ली

- बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी
- सरकार के इस्तीफे की मांग पर हिंसा में दो दिन में 157 लोग मरे

ढाका, प्रेट्र : पड़ोसी देश बांग्लादेश में सोमवार को हंगामा बरप गया। हजारों की संख्या में छात्रों ने सारी रुकावटों को पार करते हुए राजधानी ढाका पर कब्जा कर लिया और भारी तोड़फोड़-आगजनी की। हालात बेकाबू होते देख प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोपहर बाद पद से इस्तीफा दे दिया और बहन रेहाना के साथ भारत के लिए रवाना हो गईं। पहले वह बांग्लादेशी वायुसेना के मालवाही विमान से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और वहां से वह शाम 5.36 बजे गाजियाबाद स्थित वायुसेना के हिंडन एयरबेस पहुंचीं। इस बीच ढाका में प्रधानमंत्री आवास गणभवन पर उपद्रवी छात्रों ने कब्जा कर वहां लूटपाट और आगजनी की है। मंत्रियों के आवासों पर भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम व शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यालय में तोड़फोड़ और आग लगा दी गई है। ढाका में लगी बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा तोड़ दी गई है।

बांग्लादेश में रविवार को प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर ढाका और अन्य शहरों में दिन भर हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी होती रही। देर रात तक इन घटनाओं में 101 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू के बावजूद सोमवार को यह हंगामा और बढ़ गया, लांग मार्च टू ढाका... के आह्वान के साथ आसपास के शहरों से छात्र राजधानी ढाका पहुंच गए। उन्होंने सरकारी भवनों पर हमले शुरू कर दिए। शेख हसीना के दिवंगत पति डा. वाजेद मियां का आवास भी नहीं छोड़ा। मुख्य न्यायाधीश के आवास में भी उपद्रवी घुस गए और वहां तोड़फोड़ की। सोमवार की घटनाओं में देश में 56 लोग मारे गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना भी ढाका की सड़कों पर उतरी लेकिन वह आगे बढ़ते छात्रों को नहीं रोक पाई। इसके बाद सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां ने हसीना से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा और उन्हें देश छोड़कर जाने की सलाह दी। इसके बाद इसी वर्ष लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनीं 76 वर्षीया शेख हसीना को इस्तीफा दे दिया और उसके कुछ मिनट बाद बांग्लादेश छोड़ दिया। जनरल वकार-उज-जमां ने सरकारी टेलीविजन पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की जानकारी दी और खुद सारी जिम्मेदारी लेने का एलान किया। जनरल जमां ने जल्द ही अंतरिम सरकार के गठन का भरोसा दिया है। बांग्लादेश में हिंसा का सिलसिला जुलाई में आरक्षण विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ था, उसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

विशेष आयोजन›› पेज 11 व संपादकीय

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार को काफी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए। यहां उन्होंने जमकर हुड़दंग मचाया ● एएफपी

ढाका में सोमवार को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा पर चढ़े प्रदर्शनकारी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रतिमा को तोड़ दिया ● रायटर

खालिदा जिया की रिहाई का आदेश

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुहम्मद शहाबुद्दीन ने विपक्ष की नेता और पूर्व पीएम खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया है। संभवतः मंगलवार को जेल से रिहाई होगी। खालिदा ने जेल से ही देश में शांति की अपील की है।

लोकतांत्रिक ढंग से बने सरकार : अमेरिका

बांग्लादेश की ताजा स्थिति पर अमेरिका ने वहां पर शांति स्थापित होने की आवश्यकता जताई है। साथ ही देश में जल्द सभी की भागीदारी वाली लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के गठन की जरूरत बताई है।

इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, चार मंदिरों पर हमले

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश में हिंसा के दौरान हिंसक भीड़ ने ढाका स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और चार हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए। बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद के नेता काजोल देबनाथ ने बताया है कि देश के चार मंदिरों पर हमले हुए हैं। इन हमलों में मंदिरों को मामूली नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री हसीना के सत्ता से हटने के बाद हिंदू समुदाय के लोगों में स्थिति को लेकर डर है। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन मार्च 2010 में हुआ था। इस केंद्र में योग, हिंदी, भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारतीय नृत्य कलाओं के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। इस केंद्र के पुस्तकालय में भारत से संबंधित 21 हजार पुस्तकों का भी संग्रह है।

हसीना का सत्ता से बेदखल होना भारत के लिए झटका

नई दिल्ली : शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद बांग्लादेश का भविष्य कैसा होगा, अभी यह अस्पष्ट है। सैन्य शासन लंबा चलता है या जल्द ही चुनाव होंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कई वजह हैं जिसके कारण बांग्लादेश के हालात भारत के लिए चिंता का कारण हैं। ● पेज 11

सेना की सेकेंड कमान के अधिकारियों की नाराजगी का निशाना बनीं हसीना

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

नई दिल्ली : बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने जून, 2024 में अपने पसंदीदा सैन्य अधिकारी जनरल वकार-उज-जमां को बांग्लादेश का चीफ आर्मी स्टाफ तो बना दिया लेकिन इनके नीचे के पद पर आसीन सेना अधिकारियों की नाराजगी को वह भांप नहीं पाईं।

शेख हसीना ● फाइल फोटो

आर्मी चीफ वकार-उज-जमां पर सरकार से नाराज अधिकारियों का था दबाव

जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश सेना में कुल पांच लेफ्टिनेंट जनरल में से चार हसीना सरकार से नाराज चल रहे थे। यही नहीं, बांग्लादेश सेना में तीसरे स्तर के अधिकारियों (54 मेजर जनरल) में भी हसीना सरकार को लेकर नाराजगी उफान पर थी। इन सबने मिलकर अंततः हसीना के विश्वस्त आर्मी चीफ वकार-उज-जमां पर भी दबाव बनाया। इसका नतीजा यह हुआ कि हसीना को सिर्फ कुछ घंटों की मोहलत मिली और उन्हें राष्ट्र के नाम संदेश देने से भी रोक दिया गया। इसके बाद जब आर्मी चीफ की राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई, उसमें अवामी लीग के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया, जबकि पिछले हफ्ते प्रतिबंधित जमाते-इस्लामी के लोगों को बुलाया गया। यह भी बांग्लादेश सेना के बदले रुख को बताता है।

चीन, पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका भी हसीना सरकार से था नाराज ›› पेज 11

संपादकीय

पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का समय : जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को सक्रिय कर पाकिस्तान ने नए सिरे से परोक्ष युद्ध प्रारंभ कर दिया है। सवाल यह है कि हमारा जवाब किस तरह होगा? **कैप्टन आर. विक्रम सिंह** का आलेख।

सुनिश्चित हो परीक्षाओं की शुचिता : भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ स्कूल-कालेज की परीक्षाओं में भी कदाचार रोकने की दिशा में ठोस कदम जरूरी हैं। **सुरेंद्र किशोर** का सुझाव। ● पेज-8

विमर्श

सामाजिक न्याय को मिलेगा नया आयाम : पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसने एक प्रकार से आरक्षण के भीतर आरक्षण पर मुहर लगा दी। डा. वरुण छाछर का विश्लेषण।

रुचिकर बने विद्यालयी शिक्षा : शिक्षा इस तरह से दी जानी चाहिए कि उसके लिए किया गया परिश्रम बच्चों को परिश्रम नहीं, खेल लगे। बस्ता मुक्त दिवस की पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। पीयूष कुमार दुबे का आलेख। ● पेज-9

अमेरिका में मंदी की आहट से सेंसेक्स 2,222 अंक लुढ़का

जेएनएन, नई दिल्ली

अमेरिका में मंदी की आहट और जापान में ब्याज दर बढ़ने से दुनिया के अन्य बाजार के साथ भारतीय बाजार भी सोमवार को धड़ाम हो गए। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 2,222.53 अंक की गिरावट के साथ 78,759.40 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार एनएसई का निफ्टी 662 अंक की गिरावट के साथ 24,055 अंक पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, अगले कुछ दिनों के बाद भारतीय बाजार फिर से पटरी पर आ सकती है, लेकिन मिड कैप और स्माल कैप को संभलने में थोड़ा वक्त लग सकता है।

सेंसेक्स में टाटा मोटर्स के शेयरों में सबसे ज्यादा 7.32 प्रतिशत की गिरावट रही। इसके अलावा तमाम बड़ी कंपनियों के शेयर गिरकर बंद हुए। जापान का निक्केई 12.4 प्रतिशत या 4,451.28 अंक लुढ़ककर 31,458.42 के स्तर पर बंद हुआ। निक्केई में यह 1987 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले शुक्रवार को निक्केई में 5.8 प्रतिशत की गिरावट रही थी। वहीं, सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिका का डाऊ जोंस एक हजार अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ खुला। नैसडेक कंपोजिट इंडेक्स 680 अंक या चार प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट और एसएंडपी 500 सूचकांक 164 अंक या तीन प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट के साथ खुला।

79 हजार के स्तर से नीचे गिरकर 78,759 पर बंद हुआ बीएसई

662 अंक की गिरावट से 24,055 के स्तर पर बंद हुआ एनएसई निफ्टी

12.4% या 4,451 अंक गिरकर बंद हुआ जापान का निक्केई

37 पैसे टूटा रुपया

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका में मंदी की चिंताओं के बीच वैश्विक बिकवाली के चलते डालर के मुकाबले भारतीय रुपया 37 पैसे की गिरावट के साथ 84.09 के सर्वकालिक निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ।

दो दिन में 19.76 लाख करोड़ रुपये घटी निवेशकों की संपत्ति पेज>>10

अग्निवीर के बलिदान होने पर स्वजनों को कारगिल पैकेज देगी राजस्थान सरकार

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार अग्निवीरों के बलिदान होने पर उनके स्वजनों को कारगिल में बलिदान होने वाले जवानों की तरह पैकेज देगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के लिखित सवाल के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि अग्निवीरों के बलिदान होने अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने पर उनके स्वजनों को कारगिल पैकेज की तरह 25 लाख रुपये नकद, नहरी क्षेत्र में 25 बीघा जमीन, एक आश्रित को सरकारी नौकरी, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, माता-पिता के लिए पांच लाख रुपये की एफडी और रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह पैकेज केंद्र की ओर से दिए जाने वाली सहायता के अतिरिक्त होगा।

जागरण विशेष

जन आंदोलन से धरती को पानी लौटाने लगा देवास

देवास : मध्य प्रदेश के देवास शहर में सरकारी मदद के बिना जल क्रांति आ गई है। घरों, स्कूलों, होटलों और मंदिरों की छतों पर लगे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से पानी बचाया जा रहा है। ● पेज-7

डेथ चैंबर बन गए हैं कोचिंग सेंटर : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दिल्ली के कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत मामले का शीर्ष कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
- कहा- यह घटना आंखें खोलने वाली, कोचिंग सेंटर छात्रों की जिंदगी से कर रहे खिलवाड़
- केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस, उप्र व हरियाणा को भी बनाया पक्षकार

दिल्ली में आइएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन गए हैं और छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की दो सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने एनसीआर के सभी कोचिंग सेंटरों के मामले में सुनवाई का मन बनाते हुए उत्तर प्रदेश व हरियाणा को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें भी नोटिस जारी किया है। सभी को 20 सितंबर तक जवाब दाखिल करना होगा।

पीठ ने बीते 27 जुलाई को दिल्ली में हुई भारी बारिश के चलते राव आइएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने के कारण तीन छात्रों की हुई मौत पर चिंता और दुख जताते हुए कहा कि जो उन्होंने कुछ पढ़ा है, वह डराने वाला है। पीठ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिलहाल के लिए हम इन कोचिंग सेंटरों को बंद कर देंगे।

कोर्ट ने कहा कि जब तक भवन नियमों और सुरक्षा मानकों का सावधानीपूर्वक पालन न हो तब तक कोचिंग आनलाइन चलनी चाहिए। ये जगहें (कोचिंग सेंटर) मौत का घर बन गई हैं। कोचिंग सेंटर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाल की घटना हम सभी की आंखें खोलने वाली है। इसलिए कोर्ट इस सुनवाई का दायरा बढ़ाकर मामले में नोटिस जारी करना उचित समझता है।

पीठ ने केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को और दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि अभी तक सुरक्षा के क्या मानक निर्धारित किए गए हैं और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी तंत्र विकसित किया गया है?

पीठ ने मामले की सुनवाई में अटार्नी जनरल से मदद करने का आग्रह किया है। साथ ही एनसीआर में कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा के दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपायों पर छात्रों तथा अन्य हितधारकों से भी सुझाव मांगे हैं।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कोचिंग फेडरेशन आफ इंडिया की याचिका सुनवाई पर लगी थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाई कोर्ट ने अग्निशमन विभाग और नगर निकायों से कहा था कि वे सभी कोचिंग सेंटरों की जांच कर पता लगाएं कि क्या वे आग से सुरक्षा के उपाय और सुरक्षा के अन्य उपायों का पालन कर रहे हैं। कोर्ट ने फेडरेशन की याचिका को बकवास याचिका बताते हुए एक लाख के जुर्माने सहित खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि कम से कम एनसीआर में किसी भी कोचिंग सेंटर को आग से सुरक्षा और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन किए बगैर चलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।

मूलभूत सुविधाओं के लिए तय किए जा सकते हैं नियम पेज>>2

विपक्ष की रणनीति

सपा और वाम दलों ने किया प्रस्तावित विधेयक का विरोध करने का एलान, आइएनडीआइए की नजरें राजग की सहयोगी जदयू और तेदेपा के रुख पर

वक्फ बोर्ड बिल पर प्रवर समिति में सरकार को थामने की होगी कोशिश

संजय मिश्र ● जागरण

नई दिल्ली : वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव करने के लिए लाए जाने वाले संशोधन विधेयक के खिलाफ शुरू हुई राजनीतिक लामबंदी के बीच विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए राजग सरकार के दो सहयोगी दलों जदयू और तेदेपा का इस मुद्दे पर रुख देखने के बाद अपनी अंतिम रणनीति तय करेगा। समाजवादी पार्टी के साथ वामपंथी दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने के अपने इरादे साफ कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस सतर्कता के साथ निर्णय करेगी। दरअसल उसे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करनी है और वह नहीं चाहेगी कि उसके किसी फैसले से कोई ऐसा नैरेटिव तैयार हो जिससे उसका नुकसान हो जाए। सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर चल रहे सियासी दांवपेच इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विपक्ष की ओर से विधेयक को संसद की सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में भेजे जाने की मांग की जाएगी।

संसदीय प्रविधान का दांव।

इसी सत्र में पेश करने की तैयारी

सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन संबंधी विधेयक इसी सत्र में पेश किए जाने की तैयारी है। इस विधेयक में 40 से अधिक संशोधनों पर विचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों को कम करना है।

राजग सरकार की ओर से वर्तमान मानसून सत्र में ही वक्फ संशोधन विधेयक लाए जाने की तैयारी को देखते हुए आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड समेत कई प्रमुख अल्पसंख्यक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार से वक्फ के मामले में छेड़छाड़ नहीं करने का अनुरोध करने के साथ इन संगठनों ने विपक्षी खेमे के दलों से सदन में विधेयक का विरोध करने की अपील की है। विपक्षी खेमे की अगुआई कर रही कांग्रेस से मिल रहे संकेतों के अनुसार विधेयक का मसौदा सामने आने के बाद गुण-दोष के आधार पर पार्टी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेगी। सरकार सदन में विधेयक लाती है तो फिर इसके जटिल पहलुओं का अध्ययन करने के लिए इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की आइएनडीआइए की ओर से मांग की जाएगी, क्योंकि सेलेक्ट कमेटी में आपत्तियों के निवारण की गुंजाइश रहेगी। कांग्रेस की निगाहें इस मामले में जदयू और तेदेपा पर भी लगी है जो राजग सरकार के बहुमत के कर्णधार हैं और इन दोनों दलों के लिए अपने राज्य की सियासत भी महत्वपूर्ण है। विपक्ष को उम्मीद है कि विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की मांग उठेगी तो जदयू और तेदेपा भी इस पर हामी भर सकते हैं।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के केंद्र के कदम का विरोध करेगी। वहीं, माकपा सांसद अमरा राम और आइयूएमएल के सांसद मोहम्मद बशीर ने विधेयक लाने की सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध करने की बात कही। झामुमो सांसद महुआ माजी ने कहा कि सरकार को एकपक्षीय नजरिया नहीं अपनाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के रुख का अभी इंतजार है, मगर जाहिर तौर पर वह सरकार के खिलाफ रहेगा।

वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक पहले राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना पेज>>5

केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं, सीबीआइ के पास मजबूत साक्ष्य

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- हाई कोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका

कहा, जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री

आबकारी नीति घोटाले में ईडी के मनी लांड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार करने के सीबीआइ के फैसले को सही करार दिया। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीबीआइ द्वारा की गई गिरफ्तारी को द्वेषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। जांच एजेंसी ने पर्याप्त सुबूत जुटाने और अप्रैल में मंजूरी मिलने के बाद जांच आगे बढ़ाई और उनकी गिरफ्तारी की गई। तथ्यों को देखते हुए गिरफ्तारी को किसी भी तरह से अवैध नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने मामले में जमानत की मांग के लिए निचली अदालत जाने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने की राह आसान नहीं है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा, जांच एजेंसी ने गवाहों पर केजरीवाल के नियंत्रण व प्रभाव को दिखाया है, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सके।

गिरफ्तारी और रिमांड का दुरुपयोग न हो यह देखना कोर्ट का काम पेज>>2

****

12 जोन में आने वाले 266 पुलिस थानों के मालखानों और अर्धसैनिक बलों के परिसरों की जांच में 308 स्थानों पर मच्छरों का प्रजनन पाया गया। निगम ने इस संबंध में 139 कानूनी नोटिस जारी किए हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 6 अगस्त, 2024

आज का मौसम

सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने एवं हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार हैं। 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
6 अगस्त	34.0	27.0
7 अगस्त	32.0	27.0
नोएडा		
6 अगस्त	35.0	27.0
7 अगस्त	35.0	27.0
गुरुग्राम		
6 अगस्त	34.0	28.0
7 अगस्त	31.0	28.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

विजेंद्र गुप्ता फिर बने विस में नेता प्रतिपक्ष

नई दिल्ली : रामवीर बिधूड़ी के सांसद बनने से विधानसभा में रिक्त हुए नेता प्रतिपक्ष के पद पर भाजपा विधायक दल ने रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। भाजपा विधायक अजय महावर ने गुप्ता के नाम का प्रस्ताव किया जिसके बाद विधायक दल ने सर्व सहमति से विजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष चुना। गुप्ता दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष बने हैं। इससे पहले वह 2015 में तीन विधायक भाजपा के जीतकर आए थे, उसमें विजेंद्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष थे। वह दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। (जासं)

पटेल नगर और रंजीत नगर में छह संपत्तियां सील

नई दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद निगम की सीलिंग की कार्रवाई जारी है। सोमवार को निगम ने छह और संपत्तियों को सील किया है। साथ ही भवन निर्माण के नियमों के उल्लंघन में नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई करोल बाग जोन में दक्षिणी पटेल नगर और रंजीत नगर में की गई। छह संपत्तियों के बेसमेंट और भूतल को सील किया गया है। इनमें अवैध रूप से लाइब्रेरी और जिम संचालित हो रहे थे। (जासं)

सीलमपुर विस क्षेत्र के गांवों का होगा कायाकल्प

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि करीब आठ करोड़ रुपये से सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में किए जा रहे विकास कार्य से उनका कायाकल्प होगा। दिल्ली के गांवों के विकास के लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपये का बजट रखा है। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। इसीलिए पौधा वितरण अभियान शुरू किया है। इस साल सात लाख 74 हजार से अधिक पौधे निश्शुल्क वितरित किए जाएंगे। (वि.)

एलजी को एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार

सुप्रीम निर्णय ▸ इसके लिए दिल्ली सरकार की सहमति लेना जरूरी नहीं

मनोनीत पार्षदों को लेकर लंबे समय से राज्य सरकार और एलजी के बीच रहा विवाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में 10 सदस्यों (एल्डरमैन) को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की शक्ति पर अपनी मुहर लगा दी। सोमवार को अपने अहम फैसले में कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है और उसके लिए सरकार की सलाह और सहायता से बंधे नहीं हैं। उपराज्यपाल (एलजी) को एमसीडी सदस्यों को मनोनीत करने की विधायी शक्ति है, वह ऐसा कार्यकारी शक्ति के तहत नहीं करते।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ ने यह फैसला दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनाया, जिसमें एलजी द्वारा एमसीडी में 10 पार्षदों को मनोनीत किए जाने को चुनौती दी गई थी। एल्डरमैन की नियुक्ति पर लंबे समय से राज्य सरकार और एलजी के बीच विवाद था।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इसी

कोर्ट ने किया एक अहम मसले का निपटारा।

विवाद के चलते एमसीडी में अभी तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में एल्डरमैन कहलाने वाले मनोनीत पार्षद भी मतदान करते हैं। पांच करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट के लिए स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी जरूरी होती है और स्टैंडिंग कमेटी का गठन न होने के कारण बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए पांच करोड़ से अधिक के कई प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल के पास दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट के तहत विधायी शक्ति है, इसलिए एलजी को इसमें दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। इस शक्ति का इस्तेमाल करना राज्यपाल के विधायी कर्तव्यों में आता है न कि राज्य की कार्यकारी शक्ति में।

दिल्ली सरकार की शक्तियों के बारे में शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर संसद संविधान की दूसरी सूची (राज्य सूची) या तीसरी सूची (समवर्ती सूची) में दिए विषय से संबंधित कानून बनाती है तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की कार्यकारी शक्ति उसकी सीमा तक सीमित हो जाएगी। डीएमसी एक्ट 1957 की धारा 3(3)(बी)(1) प्रविधान करता है कि उपराज्यपाल विशेष ज्ञान वाले 10 सदस्यों को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में मनोनीत कर सकते हैं। यह अधिकार 1993 में कानून में किए गए संशोधन के जरिए दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने 10 पार्षदों को मनोनीत करने के एलजी के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि एलजी ने दिल्ली सरकार की सलाह के बगैर एल्डरमैन को मनोनीत किया, जबकि वह ऐसा नहीं कर सकते।

एल्डरमैन और उनके अधिकार

- 10 एलजी निगम प्रशासन का अनुभव रखने वाले 10 लोगों को एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं।
- इनका कार्यकाल उस समय तक होता है, जब तक कि नए सिरे से सदन का गठन पांच वर्ष के लिए चुनाव से नहीं हो जाता।
- एल्डरमैन नगर निगम की वार्ड कमेटी में बतौर विशेषज्ञ अपनी राय रख सकते हैं
- एल्डरमैन वार्ड कमेटी में चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन के साथ ही यहां से चुने जाने वाले स्थायी समिति के सदस्य के लिए वोट कर सकते हैं।

चुनी हुई सरकार को बाईपास कर सारे अधिकार एलजी को दिए जा रहे : आप

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन मनोनीत करने का एकाधिकार एलजी को देने के फैसले से आम आदमी पार्टी ने असहमति जताई है। सोमवार को आए फैसले पर आप के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बाईपास करके सारे अधिकार एलजी को दिए जा रहे हैं, ताकि वो अपने डंडे से दिल्ली को चलाएं। उन्होंने कहा कि पूरा फैसला पढ़ने के बाद हम इस मामले में आगे की रणनीति बनाएंगे।

संजय सिंह ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में भी राज्यपाल एल्डरमैन का मनोनयन करते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार की अनुशंसा पर ही करते हैं। दिल्ली में भी एक चुनी हुई सरकार है, तो फिर दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है? सिंह ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।

संवैधानिक व्यवस्था हुई स्पष्ट : सचदेवा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट द्वारा निगम में एलजी द्वारा नियुक्त एल्डरमैन को सही ठहराए जाने का भाजपा ने स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में एल्डरमैन की व्यवस्था कोई आज व्यवस्था नहीं है। यह वर्षों से चली आ रही है और साथ ही दिल्ली में एलजी को संविधान के माध्यम से जो अधिकार मिले हैं, उसे आप लगातार खत्म करने की कोशिश कर रही है लेकिन वह भूल जाती है कि दिल्ली में और अन्य राज्यों में अंतर है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निगम एक्ट की संवैधानिक व्यवस्थाएं स्पष्ट हुई है। भाजपा ने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की इस मामले पर प्रतिक्रिया को राजनीतिक हताशा करार दिया है। राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद संजय सिंह का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठाना निंदनीय है। वहीं, निगम के नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब महापौर को जल्द से वार्ड कमेटी और स्थायी समिति का गठन करना चाहिए ताकि दिल्ली में रूके हुए विकास कार्य शुरू हो सकें।

अब दिल्ली के विकास को मिलेगी रफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की ओर से एलजी द्वारा मनोनीत 10 पार्षदों (एल्डरमैन) पर मुहर लगने से अब नगर निगम में वार्ड कमेटी से लेकर स्थायी समिति के गठन का रास्ता खुल गया है। स्थायी समिति बनने के बाद दिल्ली के विकास को रफ्तार मिलेगी। साथ ही लंबित पड़े विकास कार्यों को भी शुरू किया जा सकेगा। अब महापौर के आदेश के बाद अगले कुछ सप्ताह में वार्ड कमेटी के चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके बाद द्वारका बी से पार्षद कमलजीत सहरावत के इस्तीफे से रिक्त हुए स्थायी समिति का एक पद रिक्त हो गया है, पहले उसका चुनाव होगा। फिर स्थायी समिति के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को भाजपा अपने पक्ष में मान रही है और उसका दावा है कि उन्हीं का पार्षद स्थायी समिति का चेयरमैन बनेगा।

अभी वार्ड कमेटियों के गठन न होने से स्थानीय स्तर पर निगम के कार्यों की निगरानी नहीं हो पा रही है। साथ ही लोगों की समस्या पर सीधा काम नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, वार्ड कमेटियों के गठन न होने से स्थायी समिति का गठन भी नहीं हो पा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से इन 12 वार्ड कमेटियों और स्थायी समिति का गठन संभव हो पाएगा। 10 सदस्यों के मनोनयन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने से भाजपा को इससे फायदा होगा, क्योंकि एल्डरमैन को वार्ड कमेटी में वोटिंग का अधिकार है।

संयोग नहीं आशा किरण में 14 मौतें : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ समाज कल्याण सचिव को दिया केंद्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश

▸ एक माह में 14 लोगों की मौत के मामले में दायर याचिका पर अदालत ने दिया आदेश

आशा किरण आश्रय गृह में मौतों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सरकार द्वारा संचालित आश्रय गृह में एक महीने में 14 मौतें संयोग नहीं हो सकती हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को व्यक्तिगत रूप से मंगलवार को आशा किरण आश्रय गृह का दौरा करने का निर्देश दिया। यह देखते हुए कि मृत व्यक्ति टीबी से पीड़ित थे, अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड को आश्रय गृह में पानी की गुणवत्ता और स्थिति का तुरंत परीक्षण कराने का निर्देश दिया। साथ ही डीजेबी के सचिव को मामले पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आश्रय गृह में बहुत अधिक लोग हैं तो कुछ लोगों को उचित स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अदालत ने यह निर्देश सोमवार को समाधान अभियान नाम की संस्था की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई

हाई कोर्ट ने दिए अहम निर्देश।

करते हुए दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में जांच की मांग की मांग की गई है। याचिका में वैकल्पिक रूप से मामले की सीबीआइ जांच के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी के सभी आश्रय गृहों के सामाजिक आडिट की मांग की गई है ताकि आश्रय गृहों की सही स्थिति सामने आ सके।

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन निकायों सहित आश्रय गृह के कामकाज में गंभीर खामियां हैं।

वहीं, दिल्ली सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मरने वाले 14 लोगों में से केवल एक बच्चा था, जबकि अन्य वयस्क थे। अदालत को यह भी सूचित किया गया कि सभी मृत व्यक्ति गंभीर श्रेणी की बौद्धिक अक्षमताओं और एक साथ कई बीमारियों से पीड़ित थे। यह भी सूचित किया कि ज्यादातर मौतें अस्पताल में हुईं। शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है और रिपोर्ट का इंतजार है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दो पहलू हैं। एक तो आपराधिक जांच और दूसरा जिम्मेदारी तय करना और ये दोनों उपाय जल्द से जल्द किए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर कोई समस्या है तो सबसे पहले उसका पता लगाएं। अगर आश्रय गृह में पीने के पानी की कमी है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। यदि स्वच्छता की स्थिति की समस्या है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हों, जिससे कि समस्या का समाधान हो सके।

नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को अग्रिम जमानत

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी। शीर्ष अदालत से राहत मिलने के बाद यादव सिंह को भ्रष्टाचार मामले में सीबीआइ द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण मिल गया है। आरोप है कि यादव सिंह ने दिसंबर 2011 में आठ दिनों में 954 करोड़ रुपये के 1,280 रखरखाव अनुबंधों को जारी किया, जिसमें गड़बड़ी हुई।

कोर्ट ने यादव सिंह को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक माह की सात तारीख को मामले के जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों और मुकदमे में सहयोग करें। सीबीआइ की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि आशंका है कि याचिकाकर्ता विदेश भाग सकता है। यादव सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपना पासपोर्ट सीबीआइ के पास जमा कर दिया है। 25 अक्टूबर, 2019 को शीर्ष अदालत ने ईडी द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग मामले में यादव सिंह को जमानत दे दी थी।

एलजी ने गृह मंत्रालय से की आबकारी उपायुक्त के निलंबन की सिफारिश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

हिट एंड रन मामला

नशे में क्रेटा कार सवार आबकारी उपायुक्त रमेश चंद्र मीना द्वारा शनिवार देर रात पूसा रोड पर रैपिडो बाइक सवार को टक्कर मारकर भागने का मामला उन्हें महंगा पड़ गया। सोमवार को एलजी वीके सक्सेना ने 'हिट एंड रन' घटना में शामिल आबकारी उपायुक्त (दानिक्स अधिकारी) रमेश चंद्र मीना को निलंबित करने के लिए गृह मंत्रालय से सिफारिश कर दी। टक्कर के बाद बाइक को तीन किमी तक घसीटते हुए ले जाने के क्रम में कार व बाइक में भीषण आग लग गई थी। कार में बोनट की तरफ आग की लपटें उठती देख मीना ने तुरंत कार रोक दी और बाहर निकलने में कामयाब हो गए। हादसे में मीना व बाइक सवार दोनों बाल-बाल बच गए थे। मामले में करोलबाग थाना पुलिस ने शराब के नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाने व मोटर वाहन अधिनियम की तीन धाराओं में मामला दर्ज कर मीना को गिरफ्तार किया था। बाद में थाने से ही उन्हें जमानत दे दी गई। मामले में आबकारी आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे नई दिल्ली जिले के डीएम ने भी सेवा विभाग को एफआइआर की प्रति भेज दी है।

एलजी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा जारी मेडिको लीगल केस शीट (एमएलसी) में मीना के शराब पीने की पुष्टि हुई है। मामले में सतर्कता निदेशालय ने एलजी को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि दानिक्स अधिकारी का यह कृत्य सरकारी कर्मचारी के लिए गंभीर कदाचार व अशोभनीय है। सक्षम प्राधिकारी उनके निलंबन के बारे में विचार कर सकते हैं, ताकि मीना के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, टक्कर मारने के बाद आबकारी उपायुक्त मौके से क्यों भाग गए थे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाइक सवार के गिर जाने के बाद उन्हें लगा कि कहीं राहगीर उनकी पिटाई न कर दें, इसलिए डर के कारण वह भाग गए थे।

आबकारी घोटाले में सिसोदिया की संलिप्तता के पर्याप्त सुबूत : ईडी

नई दिल्ली, प्रेट्र : ईडी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उसके पास ऐसे पर्याप्त दस्तावेज हैं जो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में उनकी गहरी संलिप्तता दर्शाते हैं। सिसोदिया पिछले करीब 17 महीनों से जेल में हैं और उन्होंने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के मामलों में जमानत देने का अनुरोध किया है। उनका तर्क है कि अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है।

▸ सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसी ने आप नेता की जमानत का किया विरोध

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ को बताया कि यह कोई मनगढ़ंत मामला नहीं है क्योंकि ऐसे कई सुबूत हैं जो सिसोदिया के सीधे तौर पर घोटाले में संलिप्त रहने का संकेत देते हैं। इन मामलों की प्रगति में देरी का उल्लेख करते हुए आप नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआइ और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के मामलों में कुल 493 गवाह और 69,000 पृष्ठों के दस्तावेज हैं। सिंघवी ने पीठ से कहा कि सिसोदिया को 17 महीने बाद भी जेल में क्यों रहना चाहिए? यह उनकी स्वतंत्रता का बड़ा सवाल है। उनकी दलीलों का विरोध करते हुए एएसजी राजू ने कहा कि उनके पास घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता को दर्शाने वाले सुबूत हैं। ऐसा नहीं है कि वह एक निर्दोष व्यक्ति हैं और उन्हें यूं ही गिरफ्तार कर लिया गया। इन मामलों में कार्यवाही में जांच एजेंसियों की ओर से कोई देरी नहीं हुई है और दोहरे मामलों में आरोपितों ने उन दस्तावेज का अवलोकन करने में पांच महीने लगा दिए जो मुकदमे के लिए प्रासंगिक नहीं थे। सोमवार को भी सुनवाई होगी। बता दें कि सिसोदिया को शराब नीति मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

राष्ट्रीय शूटिंग कोच समरेश का घर तोड़ने पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को यहां सिविल लाइंस में राष्ट्रीय पिस्टल शूटिंग कोच समरेश जंग के घर को गिराने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया और कहा कि संपत्ति पर उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। समरेश जंग के परिवार को यह पट्टे पर दिया गया था, इसमें कोई राहत नहीं दी जा सकती।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कोच के भाई समीर जंग द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक मार्च, 2024 के नोटिस को चुनौती दी गई थी। नोटिस में खैबर पास बाजार क्षेत्र में 32 एकड़ में फैले सभी कब्जादारों (लगभग 1,000) को अनधिकृत घोषित किया गया था और एक बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया था। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ओलिंपिक पदक विजेता मनु भाकर को प्रशिक्षित करने वाले समरेश जंग भी उसी संपत्ति में रहते हैं, जिसमें परिवार को लगभग 60-70 साल पहले कानूनी रूप से उप-किरायेदार के रूप में शामिल किया गया था। उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला।

मानसूनी वर्षा की पीडब्ल्यूडी कराएगा समीक्षा

वी के शुक्ला ● जागरण

▸ विभाग की सड़कों पर कहां और कितना जलभराव हुआ, होगा अध्ययन

▸ अगली बार की वर्षा में फिर से उन प्वाइंट का किया जाएगा निरीक्षण

नई दिल्ली : मानसून की हर वर्षा की अब लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) समीक्षा कराएगा। वर्षा कितनी तेज हुई और कितनी देर तक हुई और इस दौरान विभाग की सड़कों पर कहां-कहां और कितना जलभराव हुआ। जलभराव कितनी देर तक रहा और इसके क्या कारण रहे। इस पर अध्ययन होगा। अगली बार की वर्षा में फिर से उन प्वाइंट का निरीक्षण किया जाएगा और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जलभराव अगर किसी दूसरी एजेंसी के कारण हुआ है तो उसे भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही उस विभाग के साथ बैठक कर समस्या का समाधान भी निकाला जाएगा।

इस समीक्षा रिपोर्ट को दिल्ली के बनने वाले ड्रेनेज मास्टर प्लान पर काम करने वाली टीम को भी सौंपा जाएगा, जिससे यह साफ रहे कि आज तक दिल्ली में अधिकतर कितनी वर्षा हो हुई है, उसी आधार पर प्लान तैयार किया जा सके। बता दें कि मानसून को लेकर दिल्ली में नालों की सफाई के नाम पर खानापूरी तो होती ही है, दिल्ली की भौगोलिक

नई दिल्ली में हुई वर्षा के कारण रिंग रोड आइटीओ पर हुए जलभराव से गुजरते वाहन। जागरण आर्काइव

स्थिति भी ऐसी है कि ज्यादा वर्षा को झेल पाना शहर के लिए संभव नहीं है। ऐसे में हर बार दिल्ली जलभराव से जूझती है, दुकानों और घरों तक में भी वर्षा का पानी भर जाता है। इस साल 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में आइएएस की तैयारी करने वाले तीन विद्यार्थियों की बेसमेंट में डूब जाने से हुई घटना ने सभी को हिला कर रख दिया है। यह इलाका जरूर नगर निगम के अधीन है, मगर इस घटना ने सभी को चिंता में डाल दिया है।

वर्षा की बात करें तो वर्ष 1901 के बाद जून माह की तीसरी सर्वाधिक वर्षा हुई है। इससे पहले 88 साल पहले वर्ष 1936 और 91 साल पहले वर्ष 1933 में इससे अधिक वर्षा हुई थी। दिल्ली में इस साल 28 जून को 24 घंटे में सर्वाधिक वर्षा हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार, इस साल जून में 30 में से नौ दिन वर्षा हुई है। इस बार जून में वर्षा सामान्य से 228 प्रतिशत ज्यादा हुई है। माह की औसत वर्षा है 74.1 मिमी, जबकि 243.4 मिमी हुई है। इसके अलावा जुलाई में भी दो बार अत्यधिक वर्षा हुई है, हालांकि इस माह कोई रिकार्ड नहीं टूट पाया, मगर अत्यधिक वर्षा रिकार्ड की गई है। इन्हीं सब मुद्दों को भी बनाए जाने वाले ड्रेनेज मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा, ताकि बनाया जाने वाला प्लान प्रभावी रहे।

मूलभूत सुविधाओं के लिए तय किए जा सकते हैं नियम : सुप्रीम कोर्ट

प्रथम पृष्ठ से आगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं के अलावा सम्मान से जीवन जीने की व अन्य सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे हवा आने का उचित प्रबंध, निकासी, रोशनी, बिजली, पीने का पानी, वाशरूम आदि और अन्य जरूरी सुविधाएं। इनके बारे में विधायी नियम और दिशानिर्देश तय किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कोचिंग फेडरेशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही गत 27 जुलाई को तीन कोचिंग छात्रों की डूबने से हुई मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी। 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश की 25 वर्षीय श्रेया यादव, तेलंगाना की 25 वर्षीय तान्या सोनी और केरल के 24 वर्षीय नेविन डेल्विन की राव आइएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से मौत हो गई थी। तीन छात्रों की मौत के बाद से ही विभिन्न कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्र इन सेंटरों में सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

चिंता की बात

वीडियो गेम अधिक खेलने से बच्चों की हड्डियां कमजोर

घुटने टेढ़े होने की समस्या के साथ ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं कई बच्चे, आउटडोर खेल में कम सक्रियता व विटामिन डी की कमी बन रही इसका कारण

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

खेलकूद सिर्फ पेशेवर खिलाड़ी और एथलीट बनने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास और मजबूती के लिए भी जरूरी है। खेलकूद के जिस उम्र में हड्डियों का विकास होता है उस उम्र में कई बच्चे भी हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी के साथ ही ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं। आरएमएल अस्पताल में राष्ट्रीय अस्थि दिवस के मद्देनजर आयोजित कार्यक्रम में डाक्टरों ने यह जानकारी दी। डाक्टर बताते हैं कि मोबाइल व वीडियो गेम में अधिक सक्रियता और आउटडोर खेल से दूरी बच्चों में हड्डियों के कमजोर और घुटने टेढ़े होने की बीमारी का कारण बन रही है।

अस्पताल के आर्थोपेडिक के विभागाध्यक्ष डा. राहुल खरे ने बताया कि छोटी उम्र में हड्डियों व मांसपेशियों का विकास होता रहता है। यह प्रक्रिया 25 वर्ष की उम्र तक जारी रहती है। इसके बाद हड्डियों के मजबूत होने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। महिलाओं में मेनोपाज के बाद हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। इस वजह से महिलाएं आस्टियोपोरोसिस से अधिक पीड़ित होती हैं। पुरुषों को ज्यादातर यह बीमारी 65 वर्ष के बाद होती है। इन सबके बीच ओपीडी में हर दिन पांच से छह ऐसे बच्चे देखे जाते हैं जिनके घुटने टेढ़े होते हैं। इसका कारण यह है कि बच्चों का खेलकूद कम हो गया है। बच्चे मोबाइल पर गेम या वीडियो देखने में अधिक समय देते हैं। बाहर खेलने के लिए नहीं निकल पाते। इस वजह से विटामिन डी की भी कमी होती है। इसका असर हड्डियों के विकास पर पड़ता है और धीरे-धीरे घुटने टेढ़े होने लगते हैं। जल्दी इलाज नहीं करने पर बाद में सर्जरी की नौबत आ जाती है। ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए खानपान में नियमित रूप से दूध, पर्याप्त प्रोटीन व कैल्शियम युक्त भोजन जरूरी है। इसके अलावा बाहर खेलकूद जरूरी है।

आदत बन रही आफत। प्रतीकात्मक

ये लक्षण हों तो डाक्टर से संपर्क करना जरूरी

- जिन बच्चों के सिर की खोपड़ी मुलायम रह जाए।
- दांत देर से निकलें या टेढ़े हों।
- पेट फूला रहता हो।
- जिन बच्चों की कलाई चौड़ी हो।
- जिन बच्चों के घुटने आपस में टकराते हों तो यह घुटना टेढ़ा होने का लक्षण हो सकता है।

गिरफ्तारी और रिमांड का दुरुपयोग नहीं हो यह देखना कोर्ट का काम : हाई कोर्ट

प्रथम पृष्ठ से आगे

हाई कोर्ट ने कहा, प्रत्येक अदालत को प्रथमदृष्टया यह सुनिश्चित करना होता है कि गिरफ्तारी और रिमांड की असाधारण शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाए। इस मामले में अगस्त, 2022 में सीबीआइ द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने और ज्ञापन मेमो में कोई नया साक्ष्य या आधार नहीं होने के केजरीवाल के वकील की दलील पर पीठ ने कहा, सीबीआइ ने बताया है कि केजरीवाल के सीएम पद का सम्मान करते हुए एजेंसी ने सावधानी बरती। पूछताछ और पर्याप्त सुबूत जुटाने के बाद केजरीवाल के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए मंजूरी मांगी, जो 23 अप्रैल, 2024 को मिली।

केजरीवाल के प्रभाव के कारण सामने नहीं आ रहे थे गवाह : 48 पन्नों के निर्णय में पीठ ने कहा कि केजरीवाल सामान्य नागरिक न होकर मुख्यमंत्री होने के साथ ही मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। गवाहों पर केजरीवाल नियंत्रण और प्रभाव से प्रथमदृष्टया पता चलता है कि आबकारी घोटाले के अपराध का लिंक पंजाब से भी है। केजरीवाल के प्रभाव के कारण ही मामले से जुड़े गवाह सामने नहीं आ रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद गवाह सामने आए और बयान दर्ज कराए। इनमें दो सरकारी गवाह भी बने।

भ्रामक था केजरीवाल का तर्क : पीठ ने केजरीवाल के वकील की इस दलील को 'भ्रामक' करार दिया, जिसमें कहा गया था कि मनी लांड्रिंग मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में होने के कारण ट्रायल कोर्ट से जेल में बंद आरोपित से पूछताछ के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। अदालत ने कहा कि सीबीआइ को आवेदन देना पड़ा क्योंकि आरोपित को पीएमएलए मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। अदालत की अपेक्षित अनुमति के बिना सीबीआइ अधिकारियों को उससे पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी गई होगी।

सीबीआइ ने बताया था कि सुबूतों से सामना कराने, आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आरोपितों/संदिग्धों के बीच रची गई बड़ी साजिश का पता लगाने और धन के लेन-देन का पता लगाने के लिए केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत थी। सीबीआइ ने निचली अदालत के समक्ष अपने आवेदन में कहा था कि जेल में पूछताछ के दौरान केजरीवाल टालमटोल करते रहे। इसके कारण प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने में बाधा उत्पन्न हुई।

****

4000 करोड़ का ऋण ले चुकी है हिमाचल की कांग्रेस सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक। जानकारों का कहना है कि ऐसे ही हालात रहे तो 31 मार्च, 2025 तक राज्य पर 94,992 करोड़ रुपये के ऋण का भार होगा।

संसद प्रश्नोत्तर

एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी से 177 करोड़ रु.से अधिक की क्षति

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने सोमवार को संसद को बताया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में क्रेडिट, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी के कारण 177 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा, साइबर धोखाधड़ी के कारण नुकसान की राशि वित्त वर्ष 2022-23 में 69.68 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 177.05 करोड़ रुपये हो गई है। चौधरी ने कहा, यदि गलती बैंक की ओर से हुई है, तथा ऐसे मामलों में जहां गलती न तो बैंक की है, न ही ग्राहक की, बल्कि सिस्टम में कहीं और है और ग्राहक ने अनधिकृत लेनदेन के बारे में सूचना प्राप्त करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर बैंक को सूचित कर देता है, तो ग्राहक को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। चौधरी ने कहा, अनधिकृत इलेक्ट्रानिक बैंकिंग लेनदेन मामले में ग्राहक की जिम्मेदारी साबित करने का दायित्व बैंक पर होगा। नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी सहित किसी भी साइबर घटना की रिपोर्ट करने की सुविधा देने के लिए, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय

संसद में बोलते पंकज चौधरी (बाएं)। एएनआई

साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर '1930' शुरू किया है। ग्राहक आधिकारिक ग्राहक सेवा वेबसाइट या बैंकों की शाखाओं पर भी वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकते हैं।

सरकारी साधारण बीमा कंपनियों के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं : एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के विलय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तीन सरकारी साधारण बीमा कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस व यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में 2019-20 से 2021-22 के दौरान 17,450 करोड़ रुपये डाले गए हैं।

मणिपुर हिंसा के कारण पांच छात्रों ने स्कूल छोड़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में प्रश्न के उत्तर में बताया, मणिपुर सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में वर्ष 2023 तक हिंसा के कारण पांच छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है। राज्य में हिंसा के कारण किसी भी शिक्षक ने नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया है। पिछले वर्ष मई से इंफाल घाटी स्थित मैतेयी और समीपवर्ती पहाड़ियों पर स्थित कुकी-जो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

पालम में हीट स्ट्रोक से हुई थी मोरों की मौत

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा में प्रश्न के दौरान बताया कि जून में पालम एयर बेस पर मृत पाए गए 27 मोर हीट स्ट्रोक के कारण मरे थे। उनका पोस्टमार्टम किया गया। कोई बीमारी नहीं पाई गई।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार देश के राष्ट्रीय पक्षी के संरक्षण को लेकर बहुत चिंतित है। सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने दक्षिण भारत में मोरों के लिए दो अभयारण्य तय किये हैं। उन्होंने बताया कि मोर तीन प्रजाति के होते हैं। भारत में पाए जाने वाले मोर नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। एक

लोस में बोलते भूपेंद्र यादव (दाएं)। एएनआई

अन्य प्रजाति चीन, कंबोडिया व कुछ अन्य एशियाई देशों में पाई जाती है। तीसरी प्रजाति कांगो में पाई जाती है। भारत में पाए जाने वाले मोर सबसे सुरक्षित हैं। चीन व अन्य एशियाई देशों में पाए जाने वाले मोर लुप्तप्राय श्रेणी में हैं, जबकि कांगो में पाए जाने वाले मोर गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं।

पीएमएवाई के तहत 89 लाख से अधिक घर महिलाओं को आवंटित

नई दिल्ली, आइएएनएस : आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत 89 लाख से अधिक घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। तोखन साहू ने प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 89 लाख से अधिक घर महिलाओं के नाम पर हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। मंत्री ने पीएमएवाई योजना के तहत प्रत्येक राज्य में आवंटित घरों की संख्या का आंकड़ा भी पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट 2024-25 के अनुसार, पीएमएवाई-शहरी 2.0 का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 2.20 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करना है।

देश में आर्सेनिक, फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में आई कमी

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि देश में आर्सेनिक, फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों की संख्या में कमी आई है। भारत में आर्सेनिक प्रभावित ग्रामीण बस्तियों की संख्या 316 और फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों की संख्या 265 है। अप्रैल 2019 में 14,020 आर्सेनिक प्रभावित और 7,996 फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र थे।

एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने कहा, 31 जुलाई, 2024 तक देश में 316 आर्सेनिक और 265 फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियां बची हुई हैं। यह अप्रैल 2019 में रिपोर्ट की गई 14,020 आर्सेनिक प्रभावित और 7,996 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की तुलना में काफी कम है।

मंत्री ने कहा, सरकार ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की है। अब तक, विभिन्न स्तरों (राज्य, क्षेत्र, जिला, उप-मंडल और ब्लाक स्तर) पर 2,163 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इन प्रयोगशालाओं में नाममात्र शुल्क पर पानी के नमूने का परीक्षण कराया जा सकता है।

बातचीत से हल होगा किसानों का मसला : शिवराज

राजनीतिक दलों से अपील, वे किसानों को वोट बैंक न समझें, केंद्र राज्य सरकारों के सहयोग के बिना काम नहीं कर सकती

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर वह किसानों और उनके संगठनों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने इसमें राज्य सरकारों से भी सहयोग मांगा। कहा कि किसानों का मसला बातचीत ही हल होगा। कृषि मंत्रालय के कामकाज और किसान कल्याण पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्यसभा में उन्होंने कहा कि कृषि में समस्याएं हैं, लेकिन समाधान भी है।

चौहान ने राजनीतिक दलों से भी अनुरोध किया कि वे किसानों को वोट बैंक न समझें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग के बिना काम नहीं कर सकती। वह संघीय भावना का सम्मान करते हैं और उन्होंने किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए राज्य सरकारों के कृषि मंत्रियों को आमंत्रित किया है। कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार, भारत न केवल पर्याप्त पौष्टिक भोजन, सब्जियों और फलों का उत्पादन करेगा, बल्कि दुनिया का फूड बास्केट भी बनेगा।

सोमवार को प्रश्नकाल के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने चौहान को अपना जवाब पूरा करने के लिए बुलाया। इसके तुरंत बाद विपक्षी

शिवराज सिंह चौहान फाइल

सदस्यों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। चौहान ने विपक्षी दलों के हंगामे के बीच अपना जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों को आत्मनिर्भर, मजबूत और सशक्त बनने में मदद की है। कांग्रेस ने बेशक हमेशा किसानों को सीधे मदद करने की बात की है। लेकिन, उसने ऐसा कभी नहीं किया। वह पीएम नरेन्द्र मोदी ही थे, जिन्होंने पीएम किसान योजना शुरू की।

किसानों पर गोली चलाने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चौहान ने कहा कि विपक्ष के हाथ किसानों के खून से रंगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 24 किसान मारे गए थे। चौहान ने यह बात तब कही, जब दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अन्य कांग्रेस सदस्यों के साथ सदन में हंगामा कर रहे थे। चौहान ने कांग्रेस शासन के दौरान हुई गोलीबारी की घटनाओं का जिक्र किया। विपक्ष ने जवाब देने के लिए समय मांगा, जिसे धनखड़ ने खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्ष सदन से वाकआउट कर गया।

किसान कभी भी कांग्रेस की प्राथमिकता नहीं थे : शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए पूर्व प्रधानमंत्रियों के सभी भाषण सुने हैं। किसान कभी भी कांग्रेस की प्राथमिकता नहीं थे। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिछले भाषणों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके 15 भाषणों में किसान शब्द का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि, कुछ भाषणों में इंदिरा गांधी ने जिक्र किया है, लेकिन उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं था।

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक नेता अपनी यात्रा के दौरान किसानों से मिलने के लिए सोनीपत गए। वहां किसानों से पूछते पाए गए कि उनके साथ कैसे पोज दिया जाए।

बागवानी क्लस्टर स्थापित के लिए 18,000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कृषि आय बढ़ाने के लिए अगले पांच वर्षों में 100 बागवानी क्लस्टर स्थापित करने पर 18,000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने खाद्य तेल के आयात को कम करने के लिए 6,800 करोड़ रुपये के तिलहन मिशन की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सिंचाई का विस्तार 1.30 लाख हेक्टेयर तक किया गया है।

कांग्रेस का आरोप, सदन में कृषि मंत्री ने किया झूठा दावा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: किसानों को एमएसपी देने के मुद्दे पर रास में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दावे को कांग्रेस ने झूठा करार देते हुए उन पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इसे लेकर कृषि मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की घोषणा भी की है। कृषि मंत्रालय के कामकाज पर सदन में हुई चर्चा का जवाब दे रहे चौहान के जवाब से असंतुष्ट होकर पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वाकआउट किया। बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, मोदी सरकार की 'किसान विरोधी' नीतियों के प्रतिकार के लिए हमने कृषि मंत्री का बहिष्कार किया। कृषि मंत्री ने गलतबयानी की है। सुरजेवाला ने दावा किया कि चौहान ने सदन में स्वीकारा कि सरकार एमएसपी पर तभी फसल खरीदती है, जब जरूरत होती है। इसका अर्थ है कि सरकार ने माना है कि वह किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदती, क्योंकि वह इसे जरूरी नहीं समझती। दिग्विजय ने कहा, चौहान को झूठ बोलने की आदत है। मप्र में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 37 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। सदन में चौहान का यह दावा झूठा है कि कांग्रेस को मिले अवसर में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। हम इसका सुबूत देंगे और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे।

भाजपा को मिल सकती है लोकसभा की सात- आठ समितियों की अध्यक्षता

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा को लोकसभा की विभाग संबंधी संसदीय समितियों में से सात से आठ समितियों की अध्यक्षता मिल सकती है। कांग्रेस को तीन और समाजवादी पार्टी को एक समिति की अध्यक्षता मिल सकती है।

सूत्रों ने सोमवार को बताया कि 16 समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सहित किसी भी अन्य पार्टी के पास किसी समिति की अध्यक्षता पर दावा करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। तृणमूल कांग्रेस 29 सांसदों के साथ सीटों के मामले में लोकसभा में चौथे स्थान पर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन समितियों और उनके सदस्यों के बीच निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे।

विभाग-संबंधी समितियों में से 16 समितियों की अध्यक्षता लोकसभा सांसदों द्वारा की जाती है तथा आठ की अध्यक्षता राज्यसभा सदस्यों द्वारा की जाती है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा अपने कुछ सहयोगियों, विशेषकर शिवसेना को कम से कम एक अध्यक्ष पद दिलाने के लिए समर्थन दे सकती है।

हरियाणा में सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद के फैसले पर कैबिनेट की मुहर

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

- मुख्यमंत्री सैनी ने आप व कांग्रेस शासित सरकारों को एमएसपी पर खरीद की दी चुनौती
- पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर सीमा आठ लाख करने व अग्निवीरों को आरक्षण पर भी मुहर

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा के अगले दिन सोमवार को राज्य कैबिनेट ने उस पर मुहर लगा दी। प्रदेश में पहले 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही थी। रविवार को मुख्यमंत्री ने 10 और फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी दो-चार फसलें एमएसपी पर खरीदने की पहल करनी चाहिए। गेहूं और धान की फसल ऐसी है, जो सीधे केंद्र सरकार खरीदती है। यदि पंजाब सरकार दावा करे कि इन दोनों फसलों को वह एमएसपी पर खरीदती है तो यह किसानों संग धोखा है। सैनी ने पंजाब के आंदोलनकारी किसानों से भी अनुरोध किया कि वे मान सरकार पर एमएसपी पर फसलों की खरीद का दबाव बनाएं। साथ ही कहा, कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें भी एमएसपी पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करें। कैबिनेट ने ब्रिटिश काल से किसानों से लिया जा रहा आबियाना शुल्क गत एक अप्रैल से नहीं लिया जाएगा, जिन्होंने जमा कर दिए हैं, उन्हें वापस मिलेगा।

बीसी-बी को शहरी व ग्रामीण निकायों में आरक्षण पर मुहर : कैबिनेट ने पिछड़े वर्ग की क्रीमीलेयर सीमा छह से बढ़ाकर आठ लाख करने को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की उस रिपोर्ट को भी मंजूरी दी है, जिसमें कहा गया है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग बीसीबी को पालिकाओं व पंचायतों में राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की जरूरत है। इसके तहत पांच प्रतिशत कोर्ट का प्रविधान है।

हरियाणा के 1830 अग्निवीर हो चुके भर्ती, 2215 और होंगे: मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा के अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, फोरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन व स्पेशल पुलिस आफिसर की भर्ती में 10 प्रतिशत होरिजंटल आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी दी गई। ग्रुप सी के पदों में भर्ती के लिए ली जाने वाली लिखित संयुक्त पात्रता परीक्षा से अग्निवीरों को छूट दे दी गई है। कौशल प्रमाणपत्र वालों को स्किल टेस्ट से भी छूट मिलेगी। भर्ती के लिए आयु सीमा में तीन साल की छूट दी गई है। अग्निवीरों को नौकरी देने वाले उद्योगों को राज्य सरकार 60 हजार रुपये वार्षिक सब्सिडी देगी, बशर्ते की उन्हें 30 हजार रुपये मासिक वेतन मिले। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिये अग्निवीरों को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। उद्योग लगाने के लिए पांच लाख तक ऋण बिना ब्याज मिलेगा। 15 जुलाई 2022 को लागू की गई योजना के तहत साल 2022 के दौरान सेना, वायु सेना व नौसेना में 36 हजार 649 भर्ती प्रस्तावित थी। हरियाणा से 2023-24 में 2215 अग्निवीर भर्ती होने हैं।

दिल्ली में वर्ष 2019 से अब तक 33,477 निर्माण ध्वस्त किए

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में 2019 से अब तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 33,477 निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। इस कार्रवाई से 20,643 लोग प्रभावित हुए हैं।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, 2023 में 16,138 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। 2019 में शहर में विभिन्न एजेंसियों ने कुल 4,804 निर्माण ध्वस्त किए। 2020 में 2,967, 2021 में 2,927, 2022 में 4,017, 2023 में 16,138 और 2024 में अब तक 2,624 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, इन ध्वस्तीकरणों से लगभग 20,643 लोग प्रभावित हुए हैं।

2019 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा कुल 256 ध्वस्तीकरण कार्यक्रम चलाए गए। 2019 में डीडीए ने 20 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। 2020 में 13, 2021 में 23, 2022 में 47, 2023 में 88 और 2024 में अब तक 65 निर्माण ध्वस्त किए हैं।

मुफ्त वाली योजनाओं से पीछे हटने लगी हिमाचल सरकार

रियायती बस पास और अन्य यात्रा कार्ड की राशि में भी की वृद्धि

प्रकाश भारद्वाज ● जागरण

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिन मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के वादों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई अब वही वादे सरकार को चुभने लगे हैं। हजारों करोड़ रुपये का ऋण और कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारी हमेशा सरकार की चिंता का कारण रहे हैं। इसी से सबक लेकर अब गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे राज्य ने फ्रीबीज यानी मुफ्त बांटने की आदत से बाहर निकलने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला कदम उठाते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट निश्शुल्क बिजली का दायरा सीमित करने का निर्णय लिया। अब आयकर देने वालों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। इसकी अधिसूचना जारी होना शेष है। कांग्रेस ने ही विस चुनाव में सभी को 300 यूनिट निश्शुल्क बिजली देने की गारंटी दी थी किंतु उसके लिए जयराम सरकार के समय से जारी 125 यूनिट की छूट को निभाना भी गले तक आ गया। इसके अतिरिक्त हिमाचल

125 125 यूनिट निश्शुल्क बिजली का दायरा सीमित करने का लिया निर्णय

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। फाइल

पथ परिवहन निगम के रियायती बस पास और यात्रा कार्ड की राशि में वृद्धि की है। इसमें 50 रुपये तक की वृद्धि के साथ अवधि घटा कर एक वर्ष की गई है।

महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने की योजना : मतदाताओं को लुभाने के लिए विस चुनाव में कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थीं। इसमें महिलाओं को मासिक 1500 रुपये देने की भी गारंटी थी। यह योजना जनजातीय लाहुल स्पीति जिला से शुरू हो चुकी है, लेकिन सभी जिलों में लागू करना संभव नहीं होगा।

निजी स्कूलों के लिए चल रही सरकारी बसों का शुल्क बढ़ाया: हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला के निजी स्कूलों के बच्चों के लिए 60 बसें चलाता है। वर्ष 2016 में इनका शुल्क तय किया गया था। अब निगम ने शुल्क में वृद्धि की है। पांच किमी के दायरे में बस का प्रति छात्र मासिक शुल्क 900 रुपये होगा। 20 किमी दूरी के लिए 1800 रुपये देने होंगे।

स्कूलों में निश्शुल्क वर्दी अब गरीब परिवार के बच्चों को ही: सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए निश्शुल्क वर्दी देने की व्यवस्था थी। वर्तमान सरकार ने अब इसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों तक सीमित किया है।

हिमाचल पर 87,589 करोड़ रुपये का ऋण : हिमाचल का ऋण 87,589 हजार करोड़ रुपये है। नौ हजार करोड़ रु. से अधिक की देनदारी नए वेतन आयोग के एरियर व डीए की है। यदि इस देनदारी को अलग रखा जाए तो 31 मार्च, 2025 तक राज्य पर 94,992 करोड़ रुपये के ऋण का भार होगा। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार अब तक 4400 करोड़ का ऋण ले चुकी है।

लोकलुभावन कदम उठाकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं : हाई कोर्ट

दयानंद शर्मा ● जागरण

- टिप्पणी की-सरकार ऐसी प्रक्रिया अपनाने के लिए पूरी तरह सक्षम, जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राज्य सरकार ऐसी प्रक्रिया अपनाने के लिए सक्षम है जिससे न केवल राज्य को अधिकतम राजस्व प्राप्त हो बल्कि कारोबारियों को व्यापार में आसानी रहे। इससे भारी निवेश का विश्वास भी मिलेगा। कोर्ट का मानना है कि किसी भी राज्य से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह सिर्फ लोकलुभावन कदम उठाकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए।

जस्टिस अरुण पल्ली और विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने यह आदेश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को गुरुग्राम में 287 करोड़ रुपये की वाणिज्यिक साइट की ई-नीलामी के लिए 'स्विस चैलेंज' पद्धति अपनाने पर दिए हैं। इस पद्धति के तहत एक निजी डेवलपर सरकार को एक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना का प्रस्ताव देता है। सरकार मूल प्रस्ताव पर जवाबी प्रस्ताव मांगती है और सभी विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करती है। अमित किशन मदान ने याचिका दायर कर सरकार की इस नीति को चुनौती दी थी। दलील थी कि स्विस चुनौती पद्धति को अपनाकर एचएसवीपी ने स्पर्धा के लिए समान मैदान प्रदान नहीं किया है। खंडपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। मदान ने गुरुग्राम के अर्बन एस्टेट सेक्टर-43 में स्थित 1.32 एकड़ की वाणिज्यिक कांप्लेक्स साइट को एचएसवीपी द्वारा 19 जुलाई को नीलाम करने की मांग की थी। इस साइट का आरक्षित मूल्य 287.97 करोड़ रुपये तय किया गया था। बयाना राशि 71.98 करोड़ रुपये बताई गई थी, जो आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत है। याचिकाकर्ता की शिकायत आरक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत पर बयाना राशि मांगने पर थी।

सुप्रीम निर्देश

कोर्ट ने कहा, क्या जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग से कोई परामर्श किया गया था, कोर्ट ने राज्य सरकार से सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा, इस मामले में 16 अगस्त को फिर सुनवाई की जाएगी

ओबीसी में शामिल जातियों के पिछड़ेपन के आंकड़े दे बंगाल सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में 77 और जातियों (ज्यादातर मुस्लिमों) को शामिल करने वाली बंगाल की ममता सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़ों को लेकर सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उसने जिन जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया है, उनके शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े होने और सरकारी नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के आंकड़े पेश करे। कोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर यह भी बताने को कहा है कि क्या उसने जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श किया था। इस मामले में 16 अगस्त को फिर सुनवाई की जाएगी।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 22 मई के आदेश के खिलाफ दाखिल बंगाल सरकार की याचिका पर उन लोगों को भी नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ओबीसी सूची में नई जातियों को शामिल करने के विभिन्न आदेश रद कर दिए थे। हाई कोर्ट ने अप्रैल व सितंबर 2010 के बीच 77 वर्गों को ओबीसी सूची में शामिल करने और 2012 के कानून के आधार पर 37 और वर्गों को ओबीसी में शामिल करने का निर्णय रद कर दिया था। साथ ही 11 मई 2012 का कई जातियों के उपवर्गीकरण का कार्यकारी आदेश भी रद कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि उसका आदेश फैसले की तारीख से लागू होगा। इससे जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, वे डिस्टर्ब नहीं हुए। सरकार ने सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की थी, पर कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक आदेश जारी नहीं किया है। हालांकि, अंतरिम रोक की मांग पर भी नोटिस जारी किया गया है।

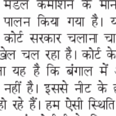
प्रतीकात्मक

सोमवार को बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंद्रा जय सिंह ने हाई कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों का विरोध करते हुए कहा, हाई कोर्ट ने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जातियां मुसलमान हैं। जय सिंह ने कहा, उनके पास रिपोर्ट है जिससे साबित होता है कि सभी पहलुओं पर विचार हुआ है और मंडल कमीशन के मानकों का पालन किया गया है। यहां हाई कोर्ट सरकार चलाना चाहता है। सियासी खेल चल रहा है। कोर्ट के आदेश का नतीजा यह है कि बंगाल में ओबीसी का कोटा नहीं है। इससे नीट के छात्र भी प्रभावित हो रहे हैं। हम ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते, जहां ओबीसी के लिए आरक्षण न हो। राज्य में 39 प्रतिशत ओबीसी हैं। जय सिंह ने पीठ से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। दूसरी ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने राज्य की मांग का विरोध करते हुए कहा कि ओबीसी में जातियों को जोड़ा जाना पूरी तरह फर्जीवाड़ा है। यहां बिना किसी अध्ययन के आरक्षण का लाभ दिया गया है। हालांकि, पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि सूची को रद कर देना एक स्वच्छंद कार्रवाई है क्योंकि राज्य में कोई आरक्षण नहीं होगा। तभी एक अन्य पक्ष की ओर से पेश वकील बांसुरी स्वराज ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ज्यादातर मुस्लिम जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया था। यह चलन एक खतरनाक नजीर पेश करता है जिसमें राजनीतिक संतुष्टीकरण की नीति जारी रहती है। दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने बंगाल सरकार से पूछा कि क्या जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने से पहले उनके पास उनके पिछड़ेपन के कोई आंकड़े थे। या फिर उन्हें ओबीसी की सूची में शामिल करने से पहले ऐसा कोई अध्ययन कराया गया था जिससे संकेत मिलता हो कि उनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

कह कर रहेंगे — माधव जोशी

****

2014 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वर्ष 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, जो बाद में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया के बाद तीन साल के अध्यक्ष चुने गए थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण मंगलवार 6 अगस्त, 2024

'अनुच्छेद 370 पर निर्णय थोपने की जगह सहमति से चाहता था'

पीएम मोदी ने कहा, जम्मू-कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेने की बात मेरे मन में एकदम स्पष्ट थी, पांच वर्ष पहले हटाने का लिया था निर्णय

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के उनकी सरकार के फैसले के बारे में कहा कि मेरे मन में यह बात बहुत स्पष्ट थी कि इस फैसले के क्रियान्वयन के लिए जम्मू-कश्मीर की जनता को विश्वास में लेना नितांत आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने '370 : अनडूइंग द अनजस्ट, ए न्यू फ्यूचर फार जम्मू कश्मीर' नामक नई किताब की प्रस्तावना में यह टिप्पणी की है। उन्होंने प्रस्तावना में लिखा, हम चाहते थे कि जब भी यह निर्णय लिया जाए तो यह लोगों पर थोपने के बजाय उनकी सहमति से होना चाहिए।

यह किताब गैर-लाभकारी संगठन 'ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन' ने लिखी है और इसे पेंगुइन इंटरप्राइज ने प्रकाशित किया है। किताब में विस्तार से उन जानकारियों का उल्लेख किया गया है कि मोदी ने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए थे, उन्हें कैसे हासिल किया। प्रकाशकों ने बताया कि इस पुस्तक का विमोचन अगस्त में ही किया जाना है। उन्होंने कहा कि यह किताब निस्संदेह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक उपलब्धि के साथ-साथ यह भी बताती है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने असंभव प्रतीत होने वाला यह काम किया। पेंगुइन ने सोमवार को अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के पांच साल पूरे होने पर एक बयान में कहा कि यह पुस्तक स्वतंत्रता के समय की गई कई भूलों पर प्रकाश डालती है, जिसकी परिणति अनुच्छेद 370 के अन्यायपूर्ण क्रियान्वयन के रूप में हुई। यह 1949 में लागू किए जाने के बाद से ही अनुच्छेद 370 के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करती है।

प्रकाशकों ने दावा किया है कि यह मोदी सरकार पर अपनी तरह की पहली किताब है, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित शीर्ष नीति निर्माताओं के साथ बातचीत के माध्यम से असल में निर्णय लेने की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण किया गया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण निर्णय का अत्यंत पठनीय विवरण है। यह पुस्तक इस पर प्रकाश डालती है कि कैसे पहले के युग के राजनीतिक समीकरणों और व्यक्तिगत रुझानों का राष्ट्रीय भावना ने अंततः प्रतिकार किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। फाइल

'अनुच्छेद 370 निरस्त से जमीनी स्तर पर मजबूत हुआ लोकतंत्र'

गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और 35(ए) को निरस्त किए जाने को सशक्तीकरण के नए युग की शुरुआत बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, पीएम मोदी के इस परिवर्तनकारी नेतृत्व निर्णय ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए सशक्तीकरण के एक नए युग की शुरुआत की है और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है।

जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के नए युग की शुरुआत

नई दिल्ली, एएनआइ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 (ए) को निरस्त किए जाने को देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि इस कदम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत हुई। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35(ए) को निरस्त किए जाने की पांचवीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने कहा कि इसके साथ ही महिलाओं, युवाओं, पिछड़े, आदिवासी और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सुरक्षा, सम्मान और अवसर का सृजन हुआ। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, आज हम भारत की संसद द्वारा अनुच्छेद 370 और 35(ए) को निरस्त किए जाने की पांचवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था।

बदलाव व विकास के पांच साल पूरे होने पर मनाया जश्न

राज्य ब्यूरो, जागरण ● श्रीनगर

- जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति के पांच साल पूरे
- भाजपा ने पाकिस्तान की सीमा से सटे आरएसपुरा में आयोजित की एकात्मता महोत्सव रैली

जम्मू के आरएसपुरा के बाना सिंह स्टेडियम में आयोजित एकात्मता महोत्सव रैली में लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते केंद्रीय मंत्री जी. कृष्ण रेड्डी व अन्य भाजपा नेता। जागरण

अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति के पांच साल पूरे होने पर सोमवार को प्रदेश भाजपा ने पूरे जम्मू-कश्मीर में जश्न मनाया और बदलाव व विकास के इन पांच वर्षों में हासिल उपलब्धियों को जनजन तक पहुंचाया। कश्मीर में तिरंगा रैली के अलावा भाजपा का जम्मू संभाग में मुख्य कार्यक्रम पाकिस्तान के साथ सटी सीमा पर स्थित आरएसपुरा के बाना सिंह स्टेडियम में एकात्मता महोत्सव रैली के रूप में हुआ, जहां केंद्रीय कोयला मंत्री व जम्मू-कश्मीर के चुनाव प्रभारी कृष्ण रेड्डी ने लोगों को शांति, सुरक्षा एवं विश्वास के वातावरण की बहाली के लिए बधाई दी। वहीं, पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, नेकां के प्रमुख प्रवक्ता तनवीर सादिक समेत विभिन्न नेताओं ने प्रशासन पर उन्हें उनके घरों में नजरबंद करने का आरोप लगाया। इस बीच, जम्मू में कांग्रेस, पीडीपी, नेकां व डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने प्रदर्शन कर पांच अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाया। जबकि जम्मू व कश्मीर पूरी तरह खुला रहा और जनजीवन पूरी तरह सामान्य रहा। इस बीच, जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कड़ी रही। सुरक्षाबलों के काफिलों की राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य कुछ मार्गों पर आवाजाही के अलावा श्री अमरनाथ की यात्रा को जम्मू से एक दिन के लिए एहतियातन स्थगित रखा गया।

वर्ष 2019 को पांच अगस्त के दिन ही संसद ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया था। इसी अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान और निशान समाप्त हुआ और प्रदेश में सभी केंद्रीय कानून लागू हुए। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित हुआ। केंद्र सरकार के इस फैसले से कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों के तंत्र पर चोट पहुंची। उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इससे हताश आतंकी व अलगाववादी तत्वों का प्रयास रहता है कि वह पांच अगस्त के अवसर पर कोई बड़ी वारदात करें। कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों जिनकी राजनीति परोक्ष रूप से अलगाववाद के तुष्टिकरण पर चलती थी, वह भी केंद्र के इस फैसले से नाराज हैं। जम्मू के आरएसपुरा में एकात्मता महोत्सव रैली में केंद्रीय कोयला मंत्री कृष्ण रेड्डी ने कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस तथा पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन राजनीतिक दलों ने हमेशा लाभ की राजनीति की है। इनको वोट देना मतलब आंतकवाद, भ्रष्टाचार तथा परिवारवाद को बढ़ावा देना है। रेड्डी ने कहा कि सितंबर तक यहां चुनाव होने की पूरी संभावना है, ऐसे में यहां की जनता भाजपा को सहयोग दे। रेड्डी ने कहा कि पाकिस्तान, नेहरू परिवार और अब्दुल्ला परिवार के कारण जम्मू-कश्मीर में कभी शांति स्थापित नहीं हुई।

अब सितंबर में शुरू हो सकती है भाजपा संगठन चुनाव की प्रक्रिया

नीलू रंजन, नई दिल्ली: भाजपा के संगठन की चुनाव प्रक्रिया अब सितंबर से शुरू हो सकती है। सितंबर और अक्टूबर में सामान्य व सक्रिय सदस्य बनाने के अभियान के साथ ही उनके सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद संगठनात्मक चुनाव शुरू होंगे और जनवरी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। 15 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशभर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद ही संगठन चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, पहले एक अगस्त से सदस्यता अभियान शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक को देखते हुए इसे टाल दिया गया। माना जा रहा है कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में पीएम मोदी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का संदेश देंगे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, संगठनात्मक चुनाव पूरा होने तक जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाले रह सकते हैं। दरअसल, पार्टी इस बार कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती। राष्ट्रीय अध्यक्ष को संगठन के चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से लाने के पक्ष में है। माना जा रहा है कि आरएसएस के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक में भी इस रणनीति पर मुहर लगी है। एक बार कार्यकारी अध्यक्ष बना देने के बाद संगठनात्मक चुनाव में उसी के स्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की संभावना होती है।

बिखर रही अपनी पार्टी, अब नूर मोहम्मद शेख ने छोड़ा बुखारी का साथ

राज्य ब्यूरो, जागरण ● श्रीनगर

- फिर से पीडीपी में जाने की संभावना, 2014 में बटमालू विस क्षेत्र से रहे हैं विधायक
- बीते माह ही पूर्व एमएलसी खुर्शीद आलम व पूर्व मंत्री उस्मान मजीद ने भी छोड़ी थी पार्टी

नूर मोहम्मद शेख।

अल्ताफ बुखारी।

जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पटल पर करीब चार वर्ष पहले उभरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को संभालना चेयरमैन सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। उनके सभी पुराने साथी एक-एक कर उनसे अलग होते जा रहे हैं। वह भी तब, जब प्रदेश में किसी भी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ताजा घटनाक्रम में अपनी पार्टी की श्रीनगर जिला इकाई के प्रधान और पूर्व विधायक नूर मोहम्मद शेख ने उनका साथ छोड़ दिया। वह खुद को सभी संगठनात्मक गतिविधियों और जिम्मेदारियों से अलग करने का एलान किया है। उनके फिर से पीडीपी में लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। नूर मोहम्मद ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में बटमालू विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी के टिकट पर चुनाव जीता था।

वर्ष 2020 में पूर्व वित्तमंत्री सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी से अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन किया था। इसमें शामिल होने वाले अधिकांश नेताओं का संबंध पीडीपी से ही रहा है। अपनी पार्टी को जम्मू कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी के विकल्प के रूप में सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने प्रचारित किया और उन्होंने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण पर खुलकर भाजपा का समर्थन किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी पार्टी के समर्थन में कश्मीर में कोई अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था। इसके बावजूद पार्टी एक भी सीट जीतने में असमर्थ रही। लोकसभा चुनाव के दौरान ही इस बात की अटकलें शुरू हो गई थी कि पार्टी के कई नेता बुखारी का साथ छोड़ सकते हैं। बीते एक माह के दौरान अपनी पार्टी से अलग होने वाले नूर मोहम्मद शेख तीसरे वरिष्ठ नेता हैं। उनसे पहले पूर्व एमएलसी खुर्शीद आलम और पूर्व मंत्री उस्मान मजीद ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था। खुर्शीद आलम वापस पीडीपी में लौट गए हैं। उस्मान मजीद कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी का दामन थामा था। वह भी अगले कुछ दिन में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।

नूर मोहम्मद शेख ने अपनी पार्टी छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि अपनी पार्टी में रहकर बहुत कुछ सीखा और समझा, लेकिन यह भी महसूस किया कि कई मुद्दों पर मैं लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूं। इसलिए अपनी पार्टी से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने पीडीपी या किसी अन्य दल में शामिल होने की संभावना पर कहा कि मेरे पास बहुत से विकल्प हैं, लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। उनके करीबियों की मानें तो वह वापस पीडीपी में शामिल होने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कश्मीर मामलों के जानकार बिलाल बशीर ने कहा कि अपनी पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि वह अपनी पार्टी के टिकट पर जीत नहीं पाएंगे। इसलिए अब अपने लिए नया ठिकाना तलाश रहे हैं। नूर मोहम्मद शेख ने बटमालू से चुनाव जीता था। वह जिला प्रधान थे। उनका अलग होना अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है।

बंगाल को विभाजित करने के प्रयास के खिलाफ एक जुट हुए ममता और सुवेंदु, प्रस्ताव पारित

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

ममता बनर्जी। फाइल

- ममता ने की प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सुवेंदु अधिकारी की प्रशंसा
- सुवेंदु बोले, दरअसल हम उत्तरी जिलों का विकास चाहते हैं

सुवेंदु अधिकारी। फाइल

बंगाल विधानसभा ने राज्य को विभाजित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ सोमवार को मानसून सत्र के अंतिम दिन एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस प्रस्ताव पर एकमत दिखीं, जो अभूतपूर्व है। भाजपा पर बंगाल के विभाजन की मांग को हवा देने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि, तृणमूल द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भाजपा राज्य के विभाजन के विचार के खिलाफ है। उन्होंने उत्तर बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल हम उत्तरी जिलों का विकास चाहते हैं।

प्रस्ताव पर चर्चा में ममता बनर्जी ने कहा कि हम सहकारी संघवाद में यकीन करते हैं। हम राज्य को विभाजित करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ हैं। प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए ममता ने सुवेंदु की प्रशंसा भी की। बता दें कि बंगाल के दो जिलों और बिहार-झारखंड के कुछ जिलों को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने तथा उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का हिस्सा बनाने संबंधी कुछ भाजपा नेताओं की हालिया मांगों के बीच तृणमूल ने मानसून सत्र के अंतिम दिन नियम 185 के तहत सदन में यह प्रस्ताव लाया था।

ममता ने सुवेंदु से कहा, आप चाय पर बुलाइए, मैं आऊंगी

सुवेंदु ने इस दौरान अलग कूचबिहार राज्य की मांग के कट्टर समर्थक भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनंत महाराज से ममता की मुलाकात को लेकर सवाल उठाया। इस पर ममता ने पलटवार करते हुए कहा कि अनंत महाराज से मिलने में क्या दिक्कत है? उन्होंने मुझे चाय पर बुलाया था। आप भी मुझे चाय पर अपने घर बुला सकते हैं और मैं आऊंगी। इधर, बाद में विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए सुवेंदु ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पहले लाया गया प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित था।

वन अधिकारी से दुर्व्यवहार : अखिल गिरि ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

मंत्री ने कहा- महिला अधिकारी से नहीं मांगेंगे माफी, जो किया उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं

बंगाल के जेल मंत्री अखिल गिरि ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने रविवार को गिरि से मंत्री पद से इस्तीफा देने और वन विभाग की एक महिला अधिकारी को धमकाने तथा अपशब्द कहने के लिए उनसे माफी मांगने को कहा था। हालांकि रामनगर से टीएमसी विधायक गिरि ने कहा कि वह किसी अधिकारी से नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी मांगेंगे।

गत शनिवार को पूर्व मेदिनीपुर के ताजपुर समुद्र तट से अतिक्रमण हटाने से अखिल गिरि इस कदर आगबबूला हो गए थे कि उन्होंने महिला वन अधिकारी मनीषा साव को जानवर तक कह डाला था और कहा था कि होश में नहीं पहने पर वह उन्हें डंडे से पीटेंगे। इस घटना के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री से मंत्री की गिरफ्तारी के साथ उन्हें मंत्रिमंडल से निकालने की मांग की थी। गिरि ने संवाददाताओं से कहा कि उस दिन लोगों की पीड़ा और वन विभाग के लोगों द्वारा उन पर अत्याचार देखकर मैं अपना आपा खो बैठा। मैं एक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है, वह लोगों के हित के लिए किया है। उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। रामनगर के विधायक ने आरोप लगाया कि छोटे व्यापारियों ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में ताजपुर समुद्र तट के पास वन विभाग की जमीन पर दुकानें शुरू करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को रिश्वत दी थी। वह उन घटनाओं के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से लिखेंगे।

उद्धव ठाकरे आज से तीन दिन के दिल्ली दौरे पर

राज्य ब्यूरो, मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मंगलवार से तीन दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के नेताओं से भी मिलेंगे। शिवसेना (यूबीटी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने इसे संवाद टूर बताते हुए कहा है कि अपनी इस यात्रा में उद्धव ठाकरे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस आदि दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला से भी मुलाकात होनी है।

राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीटों पर उतारे उम्मीदवार: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने दो सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सोमवार को राज ठाकरे ने मुंबई की शिवड़ी सीट से अपने वरिष्ठ नेता बाला नांदगांवकर को एवं पंढरपुर सीट से दिलीप धोत्रे को अपना घोषित कर दिया।

झारखंड में बदलने लगे 'समीकरण', नीतीश का बड़ा दांव

प्रदीप सिंह ● जागरण

रणनीति

- सरयू राय को जदयू में शामिल कर नीतीश ने की झारखंड में जदयू को स्थापित करने की पहल
- विधानसभा चुनाव में कम से कम तीन सीटों पर होगा दावा, एनडीए का राज्य में बढ़ेगा दायरा

नीतीश कुमार।

सरयूचंद राय। फाइल

राज्य ब्यूरो: झारखंड में पूर्व मंत्री सरयू राय के जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में शामिल होने के बाद अब राजनीतिक समीकरण थोड़े बदल सकते हैं। इसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े दांव के तौर पर भी देखा जा रहा है। सरयू राय को साथ लाकर उन्होंने राज्य में जदयू को स्थापित करने की गंभीर पहल की है। इससे हाल के दिनों में झारखंड में हाशिये पर चले गए जदयू को जहां कुछ सीटें हासिल हो सकती हैं, वहीं उसे एनडीए फोल्डर में सीटें मांगने में भी आसानी होगी। केंद्र के साथ-साथ पड़ोसी बिहार में भी भाजपा की निर्भरता जदयू पर है, ऐसे में आसानी से जदयू को कुछ सीटें दी जा सकती है।

विधायक सरयू राय ने 2019 में जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। इस बार भी वह इसी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। जदयू में शामिल होने के बाद इस बार उन्हें जमशेदपुर पूर्वी सीट पर भाजपा का समर्थन हासिल करने में भी आसानी होगी। जमशेदपुर के अलावा हजारीबाग के मांडू और पलामू के छतरपुर सीटों पर भी जदयू की दावेदारी हो सकती है। मांडू से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो अपने पुत्र को राजनीति में उतारना चाहते हैं, जबकि छतरपुर से सुधा चौधरी चुनाव जीतती रहीं हैं। सरयू राय अपने आभामंडल का प्रयोग कर कुछ प्रभावी नेताओं को भी जदयू में लाने की क्षमता रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में जदयू का आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में खाता खुल सकता है। झारखंड में जदयू का विस्तार नीतीश कुमार लंबे समय से करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ प्रयोग भी किए। खीरू महतो को राज्यसभा में लाना इसी दिशा में उठाया गया कदम था। हालांकि इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अब सरयू राय के आने से जदयू को काफी उम्मीदें हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि इससे पार्टी को राज्य में मजबूती मिलेगी।

राज्य में बढ़ेगा एनडीए का दायरा: इस राजनीतिक घटनाक्रम से राज्य में भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का दायरा बढ़ सकता है। अभी तक राज्य में इस गठबंधन में आजसू पार्टी सम्मिलत रहा है। एनडीए के अन्य घटक दल की राज्य में प्रभावी मौजूदगी नहीं होने के कारण किसी भी दल को सीटों के बंटवारे में हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इस बार जदयू की गंभीरता से एनडीए का कुनबा राज्य में भी बढ़ेगा। एनसीपी (अजीत पवार) के हुसैनाबाद के विधायक कमलेश कुमार सिंह की भी दावेदारी होगी। उनका प्रभाव कई सीटों पर होने के कारण एनसीपी कुछ अन्य सीटों पर भी दावा जताएगा।

फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है। जानकारी के मुताबिक एमडीए में आजसू पार्टी को अभी तक झारखंड में आठ सीटें देने पर सहमति बनी है। आजसू पार्टी ने इससे अधिक सीटों पर दावा किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे में यथोचित हिस्सेदारी नहीं मिलने पर आजसू पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी। इसका भाजपा और आजसू दोनों को नुकसान हुआ था। देखना यह है कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिछाई गई इस बिसात से राजग को कितना फायदा मिलता है।

माफीनामा

श्री अकाल तख्त सचिवालय ने सुखबीर बादल का माफीनामा किया सार्वजनिक, सुखबीर ने पत्र के साथ ही लगाया था पिता द्वारा 2015 में सौंपा गया माफीनामा,

'पार्टी नेताओं की शिकायतें सिर माथे, हर सजा के लिए तैयार'

जागरण संवाददाता, अमृतसर

सुखबीर सिंह बादल। फाइल

निष्कासित नेताओं ने अकाली सुधार लहर के तहत करवाया सेमिनार

शिअद से निष्कासित नेताओं की ओर से शिरोमणि अकाली दल सुधार लहर के तहत सिख राजनीति और श्री अकाल तख्त साहिब की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सिख विद्वान डा. बलकार सिंह व श्री गुरु ग्रंथ साहिब वि के पूर्व कुलपति डा. गुरमोहन सिंह वालिया ने कहा कि भविष्य में बड़े बदलाव की जरूरत है।

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) सदैव श्री गुरु ग्रंथ साहिब एवं श्री अकाल तख्त साहिब को समर्पित रहा है और रहेगा। तर्क व दलील वहां होती है जहां किसी को समझाने अथवा कोई पर्दा रखने की जरूरत हो। दास गुरुघर का छोटा सा सेवक है। अकाली सरकार के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो बेअदबी की घटनाएं हुईं और मेरे खिलाफ जो भी पार्टी नेताओं ने लिखित शिकायतें दी हैं, मैं परिवार का प्रमुख होने के नाते समस्त गलतियों को अपनी झोली में डालता हूं। फिर चाहे यह गलतियां पार्टी द्वारा हुई थीं या फिर सरकार द्वारा। दास इस महान तख्त, गुरु साहिब एवं गुरु पंथ से बिना शर्त माफी मांगता है। श्री अकाल तख्त साहिब से गुरमत परंपराओं के अनुसार जारी हर आदेश को दास व मेरे साथी खुशी-खुशी स्वीकार करेंगे। ये बातें शिअद के प्रधान सुखबीर बादल की ओर से 24 जुलाई को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार रघबीर सिंह को सौंपे गए माफीनामे में लिखी हैं। इस माफीनामे को श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय की ओर से सोमवार को सार्वजनिक किया गया। इस माफीनामे पर पांचों तख्तों के जत्थेदार बैठक कर फैसला सुनाएंगे। सुखबीर बादल ने अपने माफीनामे के साथ ही अपने पिता स्व. प्रकाश सिंह बादल की ओर से 17 अक्टूबर 2015 को दिए गए माफीनामे की कापी भी लगाई हुई थी। सुखबीर बादल ने अपने माफीनामे में लिखा है कि वर्ष 2007 से 2015 तक अकाली सरकार के दौरान जो दुखदायी घटनाएं घटित हुई थीं, उन हृदय को आघात पहुंचाने वाली घटनाओं के लिए पूर्व मुख्यमंत्री स्व. प्रकाश सिंह बादल भी 17 अक्टूबर, 2015 को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष निजी तौर पर पेश होकर सौंपे गए पत्र में अपनी भावना व्यक्त कर चुके हैं। स्व. बादल इन घटनाओं से बेहद आहत हुए थे। बता दें कि सोमवार को ही अकाल तख्त से सचिवालय की ओर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की ओर से गुरमीत राम रहीम को माफी देने के बाद दिए गए विज्ञापन संबंधी स्पष्टीकरण को भी सार्वजनिक किया है।

बागी गुट ने एक जुलाई को श्री अकाल तख्त के समक्ष पेश हो जत्थेदार को सौंपा था माफीनामा: एक जुलाई को शिअद के बागी गुट पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की पूर्व प्रधान बीबी जगीर कौर सहित वरिष्ठ नेताओं ने अकाली सरकार के दौरान डिप्टी सीएम व प्रधान सुखबीर बादल की अगुआई में हुई गलतियों के लिए श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होकर माफीनामा जत्थेदार रघबीर सिंह को सौंपा था। इन गलतियों में डेरा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सिंह साहिबानों से माफी दिलाना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हुई बेअदबी की घटनाओं की सही जांच न कर पाने के नतीजन पीड़ितों को न्याय न दिला पाना प्रमुख थीं। 15 जुलाई को पांच तख्तों के सिंह साहिबानों की हुई बैठक में शिअद प्रधान को 15 दिन के भीतर निजी तौर से पेश होकर सुखबीर को स्पष्टीकरण देने का फरमान जारी किया था। इसके तहत सुखबीर 24 जुलाई को निजी तौर पर जत्थेदार रघबीर सिंह के समक्ष पेश हुए थे।

****

'सिद्दरमैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे'

एमयूडीए में भूमि घोटाला

गृहमंत्री बोले, राज्यपाल कैबिनेट की सलाह को इतनी आसानी से खारिज कर देंगे, इसकी उम्मीद नहीं

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) संबंधी मामले में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को दिया गया अपना कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कैबिनेट की सलाह को खारिज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि राज्यपाल कैबिनेट की सलाह को खारिज करते हैं और सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं तो कांग्रेस सरकार कानूनी लड़ाई लड़ेगी। हमने राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने और कार्यकर्ता टीजे अब्राहम द्वारा सिद्दारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका को खारिज करने की सलाह दी है। उम्मीद है कि राज्यपाल ऐसा ही करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह कैबिनेट की सलाह को इतनी आसानी से खारिज कर देंगे। अधिवक्ता टीजे अब्राहम द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर राज्यपाल ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ लगे आरोपों पर सात दिन के भीतर अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया था। गौरतलब है कि एमयूडीए में भूमि घोटाले का मामला सामने आया है। इसमें मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम भी सामने आ रहा है।

10 अगस्त से चलेगी विशेष रेलगाड़ी ऊधमपुर से छपरा के बीच। भारतीय रेलवे ने घोषणा करते हुए बताया कि छपरा से यह साप्ताहिक ट्रेन हर शनिवार को 14:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रविवार की रात 22:10 बजे बलिदानी कप्तान तुषार महाजन स्टेशन पहुंचेगी।

न्यूज गैलरी

सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने वाला बिश्नोई से प्रेरित

मुंबई : बालीवुड सुपरस्टार सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग करने वाले शूटरों में से एक ने दावा किया है कि वह जेल में बंद गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के सिद्धांतों से प्रेरित है। सोमवार को उसने अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत मांगी। उसने कहा है कि कर्ज ने उसे अपराध करने के लिए विवश किया। आरोपित विक्की कुमार गुप्ता ने कहा कि लारेंस बिश्नोई को मामले में गलत तरीके से नामित किया गया है। फायरिंग में उनकी कोई भूमिका नहीं है। मुंबई पुलिस ने गलत आरोप लगा रही है। फायरिंग का उद्देश्य केवल खान को 26 साल पहले दो काले हिरणों को मारने के उनके कृत्य के लिए डराना था। (प्रेट्र)

पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

आजमगढ़ : अदालत के स्टे आर्डर के बावजूद दूसरे के खेत पर कब्जा करने, गाली व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने बिहार के पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है। (जासं)

त्रिपुरा में समर्पण कर चुके 300 उग्रवादियों ने शुरू की भूख हड़ताल

अगरतला: त्रिपुरा में विभिन्न उग्रवादी संगठनों के समर्पण कर चुके करीब 300 उग्रवादियों ने पुनर्वास समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से 48 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर में मानु-मानपुई क्षेत्र में उग्रवादी भूख हड़ताल कर रहे हैं। समर्पण कर चुके उग्रवादियों ने 31 जुलाई को सीएम माणिक साहा को सूचित किया था। (आइएएनएस)

असम में कांग्रेस विधायक का बेटा तेल चोरी में गिरफ्तार

नगांव : असम के नगांव जिले में कांग्रेस विधायक के बेटे को तेल चोरी रैकेट में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपित रेजाउल हुदा फराजी ने रविवार रात पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। कलैबोर सब-डिवीजनल पुलिस अधिकारी रूपज्योति दत्ता ने कहा कि हाल ही में रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था और जांच में कांग्रेस विधायक के बेटे रेजाउल का नाम सामने आया। (प्रेट्र)

बेंगलुरु में पेड़ में लटकते पाए गए सीसीबी इंस्पेक्टर

बेंगलुरु : बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल अपराध शाखा (सीसीबी) में पदस्थ एक इंस्पेक्टर थिम्मेगौड़ा सोमवार को मृत पाए गए। शहर के बाहर बिदादी के सुनसान क्षेत्र में इंस्पेक्टर पेड़ में लगे फंदे से लटकते पाए गए। पुलिस को आत्महत्या का मामला होने का संदेह है, लेकिन थिम्मेगौड़ा के पास कोई नोट बरामद नहीं हुआ है। इस घटना से तीन दिन पहले यादगिर में एक सब-इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। (प्रेट्र)

एनआइआरएफ की संस्थानों की रैंकिंग की घोषणा 12 को

नई दिल्ली: राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग (एनआइआरएफ) के नौवें संस्करण के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की घोषणा 12 अगस्त को दिन के तीन बजे की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। वार्षिक रैंकिंग की घोषणा हर वर्ष अप्रैल में की जाती है, लेकिन इस वर्ष इसमें देरी हुई है। पिछले वर्ष आइआइटी-मद्रास लगातार पांचवें भी वर्ष देश में सर्वोत्कृष्ट उच्च शिक्षण संस्थान के स्थान पर बना रहा। (प्रेट्र)

रिएक्टर विस्फोट से धातू का टुकड़ा घर पर गिरा, तीन घायल

ठाणे : बदलापुर के खारवई गांव में स्थित दवा कंपनी के रिएक्टर के रिसीवर टैंक में सोमवार को विस्फोट से धातू का टुकड़ा उड़कर समीप के मकान पर जा गिरा और तीन लोग घायल हो गए। घायल व्यक्ति के दोनों पैर काटने पड़े। (प्रेट्र)

सच्चर समिति ने भी जताई थी बदलाव की जरूरत

वक्फ एक्ट ▸ विवाद का कारण संपत्तियों का अपरिवर्तनीय होना

बेट द्वारका के दो द्वीपों पर वक्फ का दावा है, जिसे कोर्ट ने भी उलझन भरा माना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वक्फ बोर्ड। प्रतीकात्मक

मुस्लिमों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति जानने के लिए गठित सच्चर कमेटी की सिफारिशों में भी वक्फ बोर्ड के प्रविधानों में संशोधन की बात कही गई है। समिति ने रिपोर्ट संप्रग सरकार के दौरान 2006 में सौंपी थी, जिसमें कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने की जरूरत है। इसी तरह 2008 में संयुक्त संसदीय समिति ने भी माना था कि वक्फ बोर्ड में कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं, जिन्हें बदलने की जरूरत है। जरूरत क्यों है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो तमिलनाडु का हिंदू बहुल गांव तिरुचेंथुराई ही है।

वहां के एक किसान राजगोपाल को बेटी की शादी में कर्ज हो गया। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपनी कृषि भूमि को बेचने का प्रयास किया तो पता चला कि वह उनकी नहीं, वक्फ बोर्ड की है। इसलिए नहीं बेच सकते। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड का दावा था कि पूरा गांव उसकी संपत्ति है। दरअसल लगभग तीन सौ वर्ष पहले उस इलाके के तत्कालीन नवाब अनवरदीन खान (1672-1749) ने पूरे गांव को ही 'वक्फ' में दान कर दिया था। उनका उद्देश्य संपत्तियों की अवैध बिक्री को रोकना था, लेकिन इसका मतलब यह निकाल लिया गया कि राजगोपाल वक्फ बोर्ड की सहमति के बिना जमीन नहीं बेच सकते थे। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पंजीकरण विभाग से राजगोपाल की भूमि को 'शून्य मूल्य' करने का अनुरोध किया। इससे राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा। वक्फ बोर्ड की अव्यवस्था के ऐसे कई उदाहरण हैं।

वक्फ के विवादित होने का असली कारण इसकी संपत्तियों का अपरिवर्तनीय होना है। किसी भी संपत्ति को अगर एक बार वक्फ घोषित कर दिया गया तो वह हमेशा वैसी ही रहेगी। देश में ऐसे कई उदाहरण हैं। बेंगलुरु ईदगाह मैदान को 1850 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जाता है। सूरत नगर निगम की इमारत पर भी ऐसा ही दावा है, क्योंकि मुगल काल में हज के दौरान सराय के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। बेट द्वारका के दो द्वीपों पर वक्फ का दावा है, जिसे कोर्ट ने भी उलझन भरा माना है। देश में अभी वक्फ से जुड़े लगभग 40 हजार मामले वक्फ ट्रिब्यूनलों में लंबित हैं, जिनके फैसलों पर कोई निगरानी नहीं है। जाहिर है, जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड की अवधारणा लाई गई थी, वह अव्यवस्था की शिकार हो गई है। उसके अधिकारों एवं फैसलों में कई तरह के संवैधानिक पेच हैं। सबसे बड़ी अव्यवस्था तो यह है कि सदियों से किसी संपत्ति को अपने कब्जे में रखने के बावजूद ग्रामीणों के पास उसे बेचने का अधिकार नहीं होता। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को बेचने से नहीं रोक सकेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर वक्फ की वैधता पर प्रश्न उठाते हुए दलील दी कि तुर्की, मिस्र और जार्डन सहित कई इस्लामी देशों में ऐसी संस्थाएं नहीं हैं।

वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा न बनें, इसके लिए अधिनियम में संशोधन जरूरी

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून

▸ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी का किया स्वागत

शादाब शम्स। फाइल

कहा, विरोध करने वाले बताएं कि वक्फ बोर्ड ने कितने बेसहारा व्यक्तियों को दिया सहारा

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाने का केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा न बनें, इसके लिए अधिनियम में संशोधन आवश्यक है। इसके साथ ही, प्रश्न किया कि जो लोग वक्फ अधिनियम में संशोधन का विरोध कर रहे हैं, वे बताएं कि वक्फ बोर्ड ने कितने गरीबों की मदद की, कितने छात्रावास खोले, कितने बेसहारों को सहारा दिया, कितने शैक्षणिक संस्थान व अस्पताल खोले। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब कुछ नहीं में मिलेगा। फिर ऐसे बोर्ड का क्या, जिससे जरूरतमंद जनता को कोई लाभ न हो। शम्स ने कहा कि कभी-कभी ज्यादा शक्तियां देने से नुकसान होता है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों के मामले में भी ऐसा ही है। तमाम जगह वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद, संपत्ति खुर्द-बुर्द करने, वक्फ की जमीन व मकान कब्जाने जैसे कई प्रकरण पूर्व में विभिन्न राज्यों में सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। आवश्यक है कि वक्फ बोर्ड के अधिकार नियंत्रित हों और सरकार को भी पता हो कि वक्फ की संपत्तियां कितनी हैं और किस उपयोग में आ रही हैं।

सभी वक्फ बोर्ड के कार्यकाल की हो सीबीआइ जांच : शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड में जगह-जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें दोषी हैं। कांग्रेस सरकारों ने इस पर नियंत्रण की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे हालात बिगड़ते चले गए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में, जहां भी वक्फ बोर्ड गठित हैं, उनकी ठीक से जांच हो जाए तो यह सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा।

वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक पहले राज्यसभा में हो सकती है पेश

नई दिल्ली, एएनआइ : वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए लाए जाने वाले विधेयक को सबसे पहले राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक के जरिये वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि सरकार इसी सप्ताह वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए कदम उठा सकती है। संसद का बजट सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने संशोधन लाने से पहले विभिन्न मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से बातचीत की और सुझाव लिए। वक्फ बोर्ड अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है। वक्फ अधिनियम को पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिए। 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया, ताकि 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के लिए अधिक अधिकार दिए जा सकें।

धीरेंद्र ब्रह्मचारी की संपत्ति हरियाणा सरकार को स्थानांतरित करने का फैसला रद

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

▸ खंडपीठ ने माना, एकल जज का फैसला गलत, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन

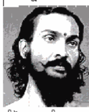
धीरेंद्र ब्रह्मचारी। फाइल

याचिका दायर करने वाली कंपनी पर भी लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने हाई कोर्ट की एकल बेंच के उस आदेश को रद कर दिया है, जिसमें एकल बेंच ने दिवंगत योगगुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी की पूरी संपत्ति राज्य सरकार को कब्जे में लेने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने वाली एक कंपनी पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया।

खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने ऐसा आदेश पारित करते समय सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। खंडपीठ ने कहा कि एकल अवमानना बेंच का फैसला गलत तरीके से दिया गया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने अपने विस्तृत आदेश में यह भी माना है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को अवमानना याचिका दायर करने की बजाय विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत सिविल मुकदमा दायर करना चाहिए था। पीठ ने इस मुद्दे पर अवमानना याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खंडपीठ ने यह आदेश रेडाक्स टेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किए हैं। रेडाक्स टेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की एक कंपनी है, जिसने आश्रम की विवादित जमीन खरीदी थी। खंडपीठ ने कहा है कि एकल पीठ द्वारा सात मई को पारित आदेश संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत इस न्यायालय को दिए गए अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है।

जस्टिस राजबीर सहरावत की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने सात मई को अपने आदेश में कहा था कि सोसायटी की स्थापना स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने की थी। चूंकि वे संन्यासी थे, इसलिए उन्होंने दुनिया के सामने घोषणा की थी कि उन्होंने संसार त्याग दिया है। ऐसे व्यक्ति का कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, जिसने संसार त्याग दिया हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति या ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थापित संपत्ति को उक्त संन्यासी की मृत्यु के बाद बिना किसी अधिकार के राज्य की संपत्ति माना जाना चाहिए। जस्टिस सहरावत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा था कि सामान्य तौर पर स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी और उनके द्वारा स्थापित सोसायटी की पूरी संपत्ति राज्य के पक्ष में चली जानी चाहिए। इन आदेशों से व्यथित होकर कंपनियों ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया था कि जब संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित विवाद लंबित है, तो अदालत को उक्त संपत्तियों को राज्य के पक्ष में संपत्ति जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।

बिहार में ईडब्ल्यूएस को सीधी भर्ती में आरक्षण देने पर जवाब तलब

विधि संवाददाता, जागरण, पटना : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को अनारक्षित पदों से आरक्षण न देकर सीधी भर्ती में दस प्रतिशत आरक्षण देने पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार सहित बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन एवं न्यायाधीश नानी तागिया की खंडपीठ ने अजय कुमार लाल एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता डीके सिन्हा एवं राकेश कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ईडब्ल्यूएस को अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध पदों पर आरक्षण न देकर सीधी भर्ती में दस प्रतिशत आरक्षण दे रही है। उन्होंने सरकार के नियम-4 को चुनौती देते हुए सीधी भर्ती में आरक्षण देने को गलत बताया। इस नियम को निरस्त करने की मांग की। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ईडब्ल्यूएस को सीधी भर्ती में दस प्रतिशत आरक्षण दे रही है।

राजस्थान विस में कांग्रेस विधायकों और मार्शल के बीच धक्का-मुक्की

▸ विधायक के निलंबन और सदन से बाहर निकालने को लेकर हुआ जोरदार हंगामा

▸ महिला विधायक की चूड़ियां टूटीं, बुजुर्ग विधायक गिरे, कांग्रेस विधायकों ने सदन में दिया धरना

राजस्थान विधानसभा में सोमवार रात धरना देते कांग्रेस के विधायक। जागरण

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के निलंबन और सदन से बाहर निकालने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भाकर को सदन से बाहर जाने के निर्देश दिए, लेकिन वे बाहर नहीं गए तो मार्शल को उन्हें निकालने का निर्देश दिया गया। मार्शल भाकर को सदन से बाहर ले जाने के लिए पहुंचे तो कांग्रेस विधायकों ने उन्हें घेर लिया और मार्शल के साथ उनकी जमकर धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान महिला विधायक की चुड़ियां टूट गईं, जबकि बुजुर्ग विधायक भी जमीन पर गिर गए। हंगामा बढ़ा तो देवनानी ने सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद भी कांग्रेस के विधायक सदन में ही बैठे रहे। कांग्रेस विधायकों का धरना देर शाम तक जारी था। धरने के दौरान विधायकों ने रामधुन भी गाया।

दरअसल, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने विधि मंत्री जोगाराम पटेल के पुत्र को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाए जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया था। वे चर्चा कराने को लेकर अड़ गए। वहीं, देवनानी ने उन्हें कहा कि नियमों के तहत आएं, वह मंगलवार को चर्चा की व्यवस्था देंगे। दोनों के बीच नोकझोंक बढ़ गई।

राष्ट्रपति मुर्मु और अन्य पूर्व राष्ट्रपतियों को मिले 250 उपहारों की होगी नीलामी

▸ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शैल शिल्प पेंटिंग और भगवान बुद्ध की मूर्ति उन चुनिंदा 250 उपहारों में शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शैल शिल्प पेंटिंग और भगवान बुद्ध की मूर्ति उन चुनिंदा 250 उपहारों में शामिल है, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और पूर्व राष्ट्रपतियों ने उपहार के तौर पर प्राप्त किया था। ये अब सोमवार से नीलामी के लिए उपलब्ध हैं। इन उपहारों को खरीदने के इच्छुक व्यक्ति अपनी बोली राष्ट्रपति भवन की एक वेबसाइट पर जाकर लगा सकते हैं, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति मुर्मु ने हाल ही में की थी। नेताजी की यह पेंटिंग देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का स्मरण कराती है। यह पेंटिंग बोली के लिए उपलब्ध सबसे महंगी वस्तु है, जिसका आधार मूल्य 4,02,500 रुपये है। पेंटिंग के विवरण के अनुसार, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया चित्र है, जिसे पूरी तरह से सीप के टुकड़ों से बनाया गया है। उन्हें उनकी प्रतिष्ठित सैन्य वर्दी में दिखाया गया है। पेंटिंग का वजन 14.15 किलोग्राम है। फ्रेम के शीर्ष पर लगा स्मृति चिन्ह 30 दिसंबर, 1943 को पोर्ट ब्लेयर में नेताजी द्वारा पहली बार भारतीय तिरंगा फहराने की ऐतिहासिक घटना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। ई-नीलामी के लिए उपलब्ध एक अन्य वस्तु भगवान बुद्ध की मूर्ति है। यह उपहार मुर्मु को बोधगया में स्थित एक प्राचीन बौद्ध मंदिर महाबोधि मंदिर से मिला था। जीवंत पीले रंग की पृष्ठभूमि के साथ सुनहरे रंग की चादर से ढकी यह बुद्ध प्रतिमा शांत ध्यान मुद्रा में चित्रित की गई है, जो गहन ध्यान और आंतरिक शांति का प्रतीक है।

यह स्मृति चिन्ह 82,500 रुपये के आधार मूल्य पर बोली के लिए उपलब्ध है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मिली एक खूबसूरत ट्राफी भी 2,700 रुपये के आधार मूल्य पर नीलामी के लिए उपलब्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा, जो पूर्व राष्ट्रपति एपी जे अब्दुल कलाम को भेंट की गई थी, बोली के लिए रखी गई है। इसकी शुरुआती कीमत 3,100 रुपये है। नीलामी के लिए रखी गई उपहार में मिली यह वस्तुएं राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में जनता के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेंगी।

उत्तराखंड का सिनला पास और सरूताल बुग्याल ट्रेक आफ द ईयर घोषित

जागरण संवाददाता, देहरादून

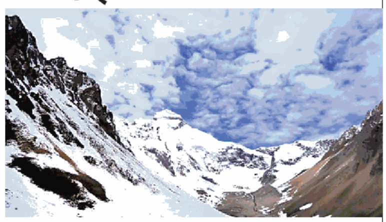
सिनला पास का विहंगम दृश्य। सौ. पर्यटन विभाग

पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा से लगी दो महत्वपूर्ण घाटियों को जोड़ने वाले सिनला पास और उत्तरकाशी के सरूताल बुग्याल को पर्यटन विभाग ने ट्रेक आफ द ईयर घोषित किया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज व पर्यटन विभाग सितंबर में आधिकारिक तौर पर विधिवत ट्रेक आफ द ईयर-2024 का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन विभाग दो सितंबर से 30 नवंबर तक इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां संचालित कराएगा।

18 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित सिनला पास धारचूला तहसील के अंतर्गत आने वाली व्यास और दारमा घाटी को आपस में जोड़ता है। बर्फ से लकदक रहने वाले इस क्षेत्र में पार्वती कुंड, गौरी कुंड, आदि कैलास, ऊं पर्वत और पंचाचूली बेस कैंप जैसे खूबसूरत स्थल हैं।

35 किमी की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी व्यास घाटी से दारमा घाटी तक पहुंचने के लिए ट्रेकरों को। इस रूट से ट्रेकर देश के प्रथम गांव विदांग के साथ ही भारत-तिब्बत व्यापार की पुरानी मंडी खिमलिंग को भी देख सकेंगे।

3,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है गोविंद वन्यजीव विहार। यहां से सरूताल से स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ, काली चोटी सहित अन्य बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं के दीदार होते हैं। इससे पहले जिले में चाईशील बुग्याल, हरकीदून, दयारा बुग्याल व देवक्यारा को ट्रेक आफ द ईयर घोषित जा चुका है।

राहुल, प्रियंका से मिले रेलवे स्टेशन के कुली, ज्ञापन सौंपा

नई दिल्ली, प्रेट्र : रेलवे स्टेशन के कुलियों के एक दल ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की और अपनी शिकायतों का विवरण देते हुए एक ज्ञापन सौंपा। पिछले वर्ष सितंबर में राहुल ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों के साथ बातचीत की थी और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली थी। इस दौरान राहुल ने न केवल कुलियों की खास लाल रंग की शर्ट पहनी थी, बल्कि सिर पर सामान भी उठाया था। कुलियों ने सोनिया गांधी के 10 जनपथ आवास के बाहर राहुल एवं प्रियंका से मुलाकात की और समस्याओं को उठाने का आग्रह किया।

राहुल ने मोची से मुलाकात का वीडियो पोस्ट किया : नेता प्रतिपक्ष राहुल ने सुल्तानपुर से लखनऊ लौटने के क्रम में मोची राम चेत से हुई मुलाकात का वीडियो सोमवार को पोस्ट किया और लिखा कि भारत की सबसे बड़ी संपदा कारीगरों के परिवारों के पारंपरिक कौशल में निहित है। यदि इन्हें समर्थन मिले तो वे भाग्य बदल सकते हैं।

तैयारी

मूंज के आकर्षक टोकरी में रखा जाएगा गंगा जल, अक्षयवट का पत्ता, गाय का गोबर, देश-दुनिया से आने श्रद्धालुओं को बिक्री किया जाएगा यह कलश, तेजी से तैयारी शुरू

महाकुंभ के लिए तैयार किए जा रहे डेढ़ लाख अक्षय गंगा कलश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

महाकुंभ के लिए तैयार किया गया अक्षय गंगा कलश। जागरण

महाकुंभ को लेकर मूंज से डेढ़ लाख अक्षय गंगा कलश का निर्माण कराया जा रहा है। मूंज के खूबसूरत टोकरी में मिट्टी के कलश में गंगा जल होगा। इस टोकरी में ही पवित्र अक्षयवट का पत्ता रखा जएगा। इसको लैमिनेट कराया जाएगा कि जल्दी सूखे नहीं। गाय का गोबर भी होगा। ताम्रपत्र की तरह महाकुंभ के लोगो का प्रिंट किया कपड़ा भी टोकरी का हिस्सा होगा। इसे बनाने का कार्य शुरू हो गया है। इस नवाचार से मूंज क्राफ्ट उद्योग का रूप ले सकेगा तो स्थानीय शिल्प कला को बढ़ावा भी मिलेगा।

एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल मूंज उत्पाद के लिए मशहूर प्रयागराज जिले के महेवा गांव की 55 समूह की लगभग 550 महिलाओं को इस कार्य में लगाया गया है। कुल एक लाख 51 हजार अक्षय गंगा कलश तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे तैयार करने में महेवा के आसपास के आठ गांवों और सोनभद्र, मीरजापुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा जिले तथा मध्य प्रदेश के सीधी व शहडोल तथा बिहार के मधुबनी के हस्त शिल्पियों को भी लगाया जाएगा। यदि इन जिलों के शिल्पकार जुट जाएंगे तो अगले पांच माह में पांच लाख कलश तैयार हो सकेंगे। एक कलश की कीमत अभी 501 रुपये रखने का प्रस्ताव है। महाकुंभ के दौरान हर होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, टेंट कालोनी से लेकर टेंट सिटी तक यह कलश बिक्री के लिए रखा जाएगा। मठ-मंदिरों से लेकर कुंभ मेला के सभी सेक्टर कार्यालयों, 15 विभागों के कार्यालयों में रखा जाएगा। मेला के विभिन्न बाजारों प्रदर्शनियों में इसके स्टाल लगाए जाएंगे। पर्यटन विभाग नोडल बनाया गया है।

मंगलकारी माना गया है मूंज

मूंज का धार्मिक व पौराणिक महत्व भी है। यह पुण्यकाल, लाभकारी, संस्कार को अग्रगण्य करने वाला है। ज्योतिषाचार्य पं. आचार्य देवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि मूंज अति पवित्र माना जाता है। उसकी बनी वस्तुएं भी पवित्रता को प्राप्त होती हैं। सभी 10 प्रकार के कुश में मूंज भी एक है।

महाकुंभ में मूंज क्राफ्ट का यह नवाचार निश्चित तौर पर हस्त शिल्प के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा। इससे शिल्पियों की आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ होगी ही, साथ में स्थानीय शिल्प की पूरी दुनिया में आभा बिखरेगी। इसके लिए वृहद स्तर पर तैयारी की जा रही है। पर्यटन और उद्योग विभाग के साथ कुल 16 विभागों की टीम लगाई जा रही है।
–गौरव कुमार, सीडीओ प्रयागराज

सेवानिवृत्ति के बाद बेटों और भतीजों को विरासत सौंपेंगे गौतम अदाणी

▸ 70 वर्ष में सेवानिवृत्ति की योजना बना रहे हैं अदाणी समूह के चेयरमैन

▸ चारों उत्तराधिकारियों को पारिवारिक ट्रस्ट में बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी

बेंगलुरु, रायटर: अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी 70 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति और 2030 की शुरुआत में अपने बेटों और भतीजों को कारोबारी विरासत सौंपने की योजना बना रहे हैं। 62 वर्षीय गौतम अदाणी के साक्षात्कार पर आधारित ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

अदाणी जब सेवानिवृत्त होंगे तो उनके चारों उत्तराधिकारियों बेटे करण व जीत और भतीजे प्रणव और सागर को पारिवारिक ट्रस्ट में बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा गया है कि एक गोपनीय समझौते के तहत समूह की फर्मों में हिस्सेदारी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाएगी। हालांकि, अदाणी समूह ने इस रिपोर्ट के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अदाणी समूह की वेबसाइट के अनुसार, गौतम अडानी के बड़े बेटे करण अदाणी पोर्ट्स के प्रबंध निदेशक हैं जबकि उनके छोटे बेटे जीत अदाणी एयरपोर्ट्स के निदेशक हैं। प्रणव अदाणी एंटरप्राइजेज के निदेशक हैं और सागर अदाणी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रणव और करण चेयरमैन बनने के लिए सबसे स्पष्ट उम्मीदवार हैं। गौतम अदाणी ने कहा कि कारोबार की स्थिरता के लिए उत्तराधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने यह विकल्प दूसरी पीढ़ी पर छोड़ दिया है क्योंकि परिवर्तन जैविक, क्रमिक और बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। अदाणी के बच्चे साक्षात्कारों में कह चुके हैं कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद संकट या जरूरत के समय संयुक्त निर्णय लेंगे।

****

14 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के एससी-एसटी छात्र-छात्राओं को योगी सरकार के उस निर्णय का लाभ मिलेगा, जिसमें उनसे दाखिले की फीस नहीं लेने का फैसला किया गया है।

टारगेट किलिंग और धमाकों का षड्यंत्र विफल, आतंकियों के पांच मददगार दबोचे

अभियान ▶ अनुच्छेद-370 के निरस्तीकरण के पांच वर्ष पूरे होने पर करना चाहते थे वारदात

अनंतनाग और पुलवामा में सुरक्षाबलों को मिली कामयाबी, हथियार भी बरामद

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर

अनंतनाग में सोमवार को सुरक्षाबलों ने आतंकियों के तीन मददगारों को गिरफ्तार कर उनसे हथियार व अन्य सामान बरामद किया। सौ : पुलिस

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा में सुरक्षाबलों ने सोमवार को दो अलग-अलग अभियानों में आतंकियों के पांच मददगारों को गिरफ्तार कर लिया। यह अनुच्छेद-370 के निरस्तीकरण के पांच वर्ष पूरे होने पर टारगेट किलिंग और आइईडी धमाके करने का षड्यंत्र रच रहे थे। पकड़े गए आतंकी मददगारों से दो पिस्तौल, एक ग्रेनेड और एक आइइडी व अन्य सामान भी बरामद किया गया है।

पांच अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 और 35ए को हटाते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया था। सोमवार को इसके पांच वर्ष पूरे हुए हैं। अनुच्छेद-370 के निरस्तीकरण से आतंकी और अलगाववादी तत्व हताश हो चुके हैं और वह हर वर्ष पांच अगस्त को किसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने का मौका तलाशते हैं।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि खुफिया एजेंसियों ने पहले ही सचेत कर दिया था कि पांच अगस्त पर कश्मीर में आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस आधार पर विभिन्न जगहों पर विशेष नाके लगाए गए थे और कई जगह तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे थे। ऐसे ही एक अभियान के तहत जिला पुलवामा के अवंतीपोरा के पास पंजगाम में सुरक्षाबलों ने आतंकियों के दो मददगारों को पकड़ा। उनकी तलाशी लेने पर एक पिस्तौल, दो मैगजीन और अन्य सामान मिला है। दोनों को उसी समय निकटवर्ती पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनकी पहचान जुबैर अहमद डार और एजाज नजीर मागरे निवासी पुलवामा के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें अवंतीपोरा के पास किसी आतंकी को टारगेट किलिंग के लिए पिस्तौल व अन्य सामान सौंपना था। उन्हें उनके हैंडलर ने सिर्फ यही कहा था कि वह पंजगाम में पहुंचे, उनके पास हथियार लेने के लिए खुद आतंकी आएंगे।

अनंतनाग से पकड़े गए तीन आतंकी मददगार : आतंकियों के तीन अन्य मददगार अनंतनाग में पकड़े गए हैं। इन्हें पुलिस, सेना और सीआरपीएफ एक संयुक्त कार्यदल ने पकड़ा। तीनों हसनपोरा तवेला के रहने वाले हैं। इनके पास से एक पिस्तौल, एक मैगजीन, आठ कारतूस, एक ग्रेनेड और एक आइइडी मिली है। उन्हें तुलखान-बिजबिहाड़ मार्ग पर एक जगह विशेष पर आइईडी लगाने का जिम्मा सौंपा गया था। पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर ने उन्हें हाईवे पर किसी जगह सुरक्षाबलों पर ग्रेनेड हमले का भी जिम्मा सौंपा था।

एलओसी पर दिखी संदिग्ध हरकत, सेना के जवानों ने किया फायर

राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशहरा सेक्टर के बीच एलओसी पर रविवार रात करीब एक बजे सेना के जवानों ने कुछ संदिग्ध हरकत देखी। इसके बाद उन्होंने कुछ गोलियां भी चलाईं, ताकि अगर कोई घुसपैठिया भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ हो तो उसे मौत के घाट उतारा जा सके। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सूत्रों के अनुसार, कुछ आतंकी भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे, जिसे सेना के जवानों ने विफल कर दिया और आतंकी वापस भाग गए। हालांकि सेना ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया या बयान जारी नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान अक्सर एलओसी पर घुसपैठ का षड्यंत्र रचता रहता है।

अंडमान में पैरा एथलीट ने अधिकारी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप

पोर्ट ब्लेयर, प्रेट्र : अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पैरा-एथलीट ने खेल विभाग के एक अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत के बाद अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना इस वर्ष मार्च में हुई थी, लेकिन महिला एथलीट ने उस समय मामला दर्ज नहीं कराया। उसे डर था कि इससे शाटपुट और डिस्कस थ्रोअर के रूप में उसका करियर प्रभावित होगा।

पीड़ित महिला पैरा एथलीट ने 2021 में राष्ट्रीय पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण पदक जीते थे। दक्षिण अंडमान की पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट के अनुसार, हाल ही में उसने पुलिस में मामला दर्ज कराने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि हम इस मामले से जुड़े सभी लोगों की जांच कर रहे हैं।

पीड़ित महिला पैरा एथलीट की शिकायत के अनुसार, उसने 2022-23 के लिए पारिश्रमिक और पैरा-एथलीटों के लिए अन्य सुविधाओं के लिए खेल विभाग को पत्र लिखा था।

पैरा एथलीट के पत्र के अनुसार, मैंने सहायक सचिव स्तर के अधिकारी के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी को फोन किया। नोडल अधिकारी ने मुझे पोर्ट ब्लेयर में अपने चैंबर में मिलने के लिए कहा। जैसे ही मैं वहां गई, उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की।

'अनुशासन के नाम पर विद्यार्थियों के साथ शारीरिक हिंसा क्रूरता'

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर

▶ छात्रा की आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने की महत्वपूर्ण

▶ टिप्पणी, संविधान में बच्चों को वयस्कों जैसा अधिकार

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छात्रा की आत्महत्या के मामले में शिक्षिका की ओर से लगाई गई याचिका खारिज कर दी और कहा कि स्कूल में अनुशासन के नाम पर विद्यार्थियों के साथ शारीरिक हिंसा क्रूरता है और यह सर्वथा अनुचित है। संविधान में जितना अधिकार वयस्क को दिया गया है, बच्चों को भी उसी अनुरूप अधिकार संपन्न बनाया गया है।

दरअसल, सात फरवरी 2024 को अंबिकापुर के कार्मेल कान्वेंट की कक्षा आठवीं की छात्रा ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या विषयक नोट में छात्रा ने स्कूल की शिक्षिका पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर शिक्षिका के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र भी पेश किया है। आरोपित शिक्षिका ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर उनके खिलाफ प्रस्तुत आरोपपत्र को निरस्त करने की मांग की थी।

चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रमेश सिन्हा व जस्टिस रवींद्र अग्रवाल की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसले में लिखा कि बच्चों को संवैधानिक अधिकार से पूरी तरह सुरक्षित किया गया है। उनके अधिकारों का हनन सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे बच्चे हैं। शारीरिक व मानसिक दंड से बच्चों के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। फाइल

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि बाल मन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का असर परिवार के सदस्यों को भी भुगतना पड़ता है। हिंसा का कोई भी कार्य जो बच्चे को आघात पहुंचाता है, आतंकित करता है या उसकी क्षमताओं पर विपरीत असर डालता है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। सरकार का दायित्व है कि वह बच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा, अपमानजनक व्यवहार, यौन शोषण से सुरक्षित करने के लिए विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करे।

तीन वर्षीया के दुष्कर्मी को फांसी की सजा, निर्णय में मानस की चौपाई का उल्लेख

जागरण संवाददाता, हरदोई

▶ हरदोई में वर्ष 2020 को हुई थी वारदात, मुठभेड़ में हुई थी गिरफ्तारी

तीन वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले उसके सगे ताऊ (पिता के बड़े भाई) को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 28 जुलाई, 2020 को दुष्कर्मी ने मासूम को कुछ खिलाने के बहाने ले जाकर यह घृणित कार्य किया था। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) मोहम्मद नसीम ने आदेश में रामचरित मानस की चौपाई का भी उल्लेख किया, 'अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी।। इन्हहि कुदृष्टि बिलोकई जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई'। यानी छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि बच्ची के साथ ऐसा कुकृत्य करने वाला आदमी नहीं नर-पिशाच है और इसे तब तक फंदे पर लटकाए रखा जाए, जब तक उसके प्राण न निकल जाएं। अपने सगे भाई की तीन वर्षीय बेटी के साथ ऐसा करने वाले अविवाहित दोषी की पैरवी के लिए कोई भी अदालत में नहीं आया।

दुष्कर्म के बाद मरणासन्न मिली बच्ची को पुलिस ने एंबुलेंस को स्कार्ट कर लखनऊ तक पहुंचाकर उसकी जान बचा ली थी। उपचार से बच्ची की जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी नर्क बन गई। अब भी वह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। वीभत्स घटना के बाद बच्ची का मल-मूत्र द्वार एक हो जाने से वह पाइप के जरिये ही नित्यक्रिया करती है। आर्थिक रूप से कमजोर पिता उसे लेकर दिल्ली में मजदूरी कर रहा है। फोन पर रोते हुए उसने कहा कि मेरी बिटिया आज भी बिस्तर पर पड़ी रहती है और घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। दुष्कर्मी को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता की मां की तरफ से दर्ज कराई गई एफआइआर की विवेचना कर छह अक्टूबर, 2020 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। पीड़िता ने अदालत को खुद उसके साथ हुई हैवानियत की कहानी सुनाई थी। पीड़िता के बयान, गवाही के साथ ही अभियोजन पक्ष की पैरवी से कोर्ट ने दुष्कर्मी को दोषी माना।

कोर्ट की टिप्पणी

'ऐ भेड़िया, नरपिशाच....। तूने तो ऐसा कृत्य किया है, जिसे सोचकर भी मैं रातभर सो नहीं पाया। बस यही सोचता रहा कि हमारे समाज को क्या हो गया है। डायन भी कम से कम सात घर छोड़कर अपना शिकार करती है। तूने तो ऐसी मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया, जोकि तुझे बड़े पापा कहती थी। यह हवस नहीं दरिंदगी है। तूने ऐसी बच्ची को अपना शिकार बनाया, जिसका वजन मात्र 11 किलो था और तीन फीट लंबाई थी। उस लड़की का जर्रा-जर्रा जालिम तेरा शिकार हुआ। मेरी निगाह में इससे बड़ा कोई और अपराध नहीं होगा।'

उप्र मदरसा शिक्षा कानून संबंधी याचिकाओं पर 13 को सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को रद कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने इसे 'असंवैधानिक' और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला बताया था। शीर्ष अदालत ने पांच अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि फैसले के खिलाफ सात याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे विचार के लायक हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इन याचिकाओं को अंतिम निपटारे के लिए 13 अगस्त को सूचीबद्ध करेगी। पीठ ने इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेज के सामान्य संकलन को सुनिश्चित करने के लिए वकील रुचिरा गोयल को नोडल वकील भी नियुक्त किया। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की गई है।

सजा माफी याचिकाओं पर विचार में देरी पर उप्र सरकार को फटकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर माफी याचिकाओं पर विचार करने के आदेश का पालन नहीं करने के लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने राज्य के कारागार विभाग के प्रधान सचिव को 19 अगस्त को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

▶ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के जेल विभाग के प्रधान सचिव को 19 अगस्त को पेश होने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने राज्य की नीति के अनुसार सजा में छूट की मांग करने वाले एक दोषी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, हम व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं। शीर्ष अदालत ने जेल विभाग के प्रमुख सचिव को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

आज जब मामला सुनवाई के लिए आया तो राज्य सरकार के वकील ने फिर से समय मांगा। पीठ ने कहा, चार महीने बीत चुके हैं। आप फिर से याचिका पर निर्णय लेने के लिए दो और महीने मांग रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य का सवाल है, हमने देखा है कि इस अदालत द्वारा विशिष्ट समय में माफी याचिका पर विचार करने के लिए पारित आदेशों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सजा माफी याचिकाओं पर विचार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को छह सप्ताह का समय दिया था। 10 जुलाई को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जेल अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के मामले में अनुकूल अनुशंसा करने के बावजूद राज्य सरकार ने कोई आदेश पारित नहीं किया है।

मानव अंगों से मिलते-जुलते चुनाव चिह्न को हटाने की मांग वाली याचिका रद

नई दिल्ली, आइएएनएस: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को मानव अंगों से मिलते-जुलते चुनाव चिह्नों को हटाने, फ्रीज करने और रद करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका पर विचार करने से इन्कार करते हुए पीठ ने कहा कि वह चुनाव निकाय को निर्देश नहीं दे सकती।

याचिका में कहा गया था कि वादी ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मानव शरीर के अंगों से मिलते-जुलते या समान प्रतीकों के खिलाफ कई शिकायतें कीं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। जबकि आदर्श आचार संहिता में स्पष्ट रूप से मतदान के 48 घंटे से पहले चुनाव प्रचार बंद करने का उल्लेख है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर चुनाव चिह्न के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसे में मानव शरीर के अंगों को छिपाया नहीं जा सकता है और यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

मणिपुर हिंसा संबंधी जस्टिस मित्तल समिति का कार्यकाल बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए गठित जस्टिस गीता मित्तल समिति का कार्यकाल सोमवार को छह महीने के लिए बढ़ा दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को सूचित किया गया कि समिति का कार्यकाल 15 जुलाई को समाप्त हो गया है। इसके बाद पीठ ने जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया। पिछले साल सात अगस्त को पीठ ने पीड़ितों के राहत और पुनर्वास तथा उन्हें मुआवजा देने की निगरानी के लिए हाई कोर्ट की तीन पूर्व महिला न्यायाधीशों की समिति गठित करने का आदेश दिया था।

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाले इस समिति में बांबे हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस (सेवानिवृत्त) शालिनी पी. जोशी और दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज आशा मेनन शामिल हैं।

सीएचसी के डीप फ्रीजर में वैक्सीन के बजाय ठंडी हो रही है बीयर

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर

▶ बुलंदशहर के धरपा सीएचसी का मामला, सीएमओ ने दिए जांच के निर्देश

▶ वैक्सीन व दवा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दिए हैं डीप फ्रीजर

वैसे ते स्वास्थ्य विभाग में फ्रीजर दवा और वैक्सीन सुरक्षित रखने के लिए होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के धरपा स्थित सरकारी अस्पताल के डीप फ्रीजर में वैक्सीन के बजाय बीयर की केन, सोडा और पानी की बोतलें ठंडी की जा रही हैं। मामला सोमवार को चर्चा का विषय बना रहा।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिशुओं को जन्म लेने के 24 घंटे के भीतर बीसीजी का टीका, पोलियो की जीरो खुराक और हेपेटाइटिस-बी का टीका लगाया जाता है। इसके अलावा भी कई प्रकार की वैक्सीन और दवा रखने के लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर डीप फ्रीजर उपलब्ध कराए गए हैं।

नियमानुसार इनमें दवा और वैक्सीन ही रखी होनी चाहिए, लेकिन धरपा में डीप फ्रीजर में बीयर की केन ठंडी हो रही हैं। जब ऐसी तस्वीरें बाहर आईं तो सीएचसी के जिम्मेदार कार्रवाई के बजाय लीपापोती में जुट गए। बुलंदशहर के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमओ) डा. विनय कुमार सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। वह सहायक मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी (एसीएमओ) को भेजकर जांच कराएंगे। जिसने भी बीयर रखी होगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बुलंदशहर में धरपा सीएचसी में डीप फ्रीजर में रखीं बीयर की केन। सौजन्य : इंटरनेट मीडिया

वैवाहिक दुष्कर्म मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक दुष्कर्म से जुड़ी याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। कोर्ट उस बहुचर्चित कानूनी प्रश्न पर सुनवाई करेगा कि अगर पति अपनी पत्नी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है, जो नाबालिग नहीं है, तो क्या पति को दुष्कर्म के अपराध के लिए अभियोजन से छूट मिलनी चाहिए? पीठ ने सोमवार को एक पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील करुणा नंदी की दलीलों पर गौर किया कि वैवाहिक दुष्कर्म के मुद्दे पर याचिकाओं पर सुनवाई की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। बता दें कि निरस्त भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत अगर पत्नी नाबालिग नहीं है तो पति द्वारा उसके साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। यहां तक कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 63 (दुष्कर्म) के अपवाद-2 में स्पष्ट किया गया है कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम नहीं है तो पति द्वारा उसके साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं है।

तिहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद के चचेरे भाई समेत 10 को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, मेरठ

▶ 2008 में मीट कारोबारी इजलाल के घर में की गई थी मेरठ कालेज के तीन छात्रों की हत्या

▶ इजलाल को पसंद नहीं था शीबा से तीनों का मिलना-जुलना, फैसले के बाद रोने लगी शीबा

तिहरे हत्याकांड में 16 वर्ष बाद अदालत ने मीट कारोबारी इजलाल कुरैशी और शीबा सिरोही समेत 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन-द्वितीय पवन कुमार शुक्ला की कोर्ट ने सोमवार को सभी पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने एक अगस्त को इस मामले में सभी आरोपितों को दोषी करार दिया था। इस दौरान कचहरी में पुलिस और पीएसी तैनात रही। जेल से सभी दोषियों को कोर्ट में पेश किया गया था। इजलाल बसपा के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का चचेरा भाई है।

22 मई, 2008 की रात 27 वर्षीय सुनील ढाका, 22 वर्षीय पुनीत गिरि और 23 वर्षीय सुधीर उज्ज्वल की मीट कारोबारी के घर में हत्या कर दी गई थी। अगले दिन सुबह इन तीनों के शव 40 किलोमीटर दूर बागपत जिले में हिंडन नदी के पास एस्टीम कार से मिले थे। तीनों मेरठ कालेज के छात्र थे। वारदात इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों, रिश्तेदार और साथियों के साथ मिलकर की थी। इजलाल की दोस्त शीबा सिरोही को हत्या के लिए उकसाने का आरोपित बनाया गया था। पुलिस ने 14 आरोपितों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया। एक अगस्त को कोर्ट ने इजलाल कुरैशी, अफजाल, महराज, कल्लू उर्फ कलुआ, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा, वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन पर हत्या समेत तमाम धाराओं और शीबा सिरोही पर हत्या के लिए उकसाने के आरोपों को सही मानते हुए दोषी करार दिया था। दो आरोपित इसरार और माजिद की मौत हो चुकी है। एक आरोपित शमी जेल में बंद है। उसका मुकदमा विचाराधीन है। एक नाबालिग आरोपित की अपील हाई कोर्ट में लंबित है।

उप्र में एससी-एसटी छात्रों को दाखिले में नहीं देनी फीस

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में गरीब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति (एससी-एसटी) के छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत देने जा रही है। इन्हें इस बार दाखिले के समय ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन के समय ही अर्हता पूरी करने वाले छात्र-छात्राओं का फ्री शिप कार्ड जेनरेट (तैयार) हो जाएगा। योगी सरकार के इस फैसले के बाद दाखिले के समय शैक्षिक संस्थान में इसे जमा करने पर ट्यूशन फीस से मुक्ति मिल जाएगी।

यह व्यवस्था वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रदेश में लागू होने जा रही है। इसका लाभ करीब 14 लाख से अधिक एससी-एसटी छात्र-छात्राओं को मिलेगा। यह सुविधा शुरुआत में सरकारी व एडेड कालेजों में दाखिला लेने वाले छात्र-छात्राओं को मिलेगी। योगी सरकार के इस फैसले को लेकर राज्य के एससी-एसटी छात्र-छात्राओं ने काफी प्रशंसा की है।

बांग्लादेशी घुसपैठ

तीन दशक पहले रेलवे स्टेशन पर 121 बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने का मामला, साहिबगंज के बरहड़वा जीआरपी में दर्ज हुए थे बांग्लादेशी घुसपैठ के आठ मामले

बांग्लादेशी घुसपैठियों को छोड़ने पर डीएसपी और थाना प्रभारी गए थे जेल

डा. प्रणेश ● जागरण

साहिबगंज : झारखंड में शासन-प्रशासन भले ही बंगाल से सटे जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ से इन्कार कर रहा हो, लेकिन घुसपैठ के मामले यहां अक्सर सामने आते रहे हैं, जो सरकारी आंकड़ों में भी दर्ज हैं। झारखंड के संताल परगना प्रमंडल के जिलों में चार दशक पूर्व ही घुसपैठ शुरू हो गई थी। वर्ष 1986 से 1993 तक सात वर्ष में बरहड़वा जीआरपी थाने में घुसपैठ के आठ मामले दर्ज हुए थे और 121 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। सभी मामलों में चार्जशीट भी दाखिल हुई थी। बरहड़वा व पाकुड़ नगर थाने में भी कई मामले दर्ज हुए थे। तब पाकुड़ भी साहिबगंज जिले का ही भाग था। खास बात यह है कि उस दौरान पाकुड़ के तत्कालीन डीएसपी ओलिबर मिंज व पाकुड़ नगर थाना प्रभारी डीएन विश्वास को बांग्लादेशी घुसपैठियों को छोड़ने पर जेल जाना पड़ा था।

बरहड़वा जंक्शन। फाइल

साहिबगंज में विदेशी घुसपैठ विरोधी संघर्ष समिति से जुड़े कमल कृष्ण भगत ने बताया कि वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से बड़ी संख्या में लोग भागकर बंगाल व आसपास के राज्यों में जाकर रहने लगे। बांग्लादेश के बिगड़ते हालात को देखते हुए सभी घुसपैठिये यहां स्थायी रूप से बस गए। धीरे-धीरे बंगाल से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी साहिबगंज भी पहुंच गए। उनके आने का सिलसिला लगातार जारी रहा।

स्थानीय लोग घुसपैठियों को पकड़ कर देते थे जीआरपी के हवाले : भाजपा के कद्दावर नेता रहे कैलाशपति मिश्रा ने अपने समय में संसद में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाया था। तब सांसद सैयद शहाबुद्दीन ने उन्हें घुसपैठियों को खोज कर लाने की चुनौती दी थी। उस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। आजिमगंज-गया के बीच रात में चलने वाली ट्रेन से बांग्लादेशी घुसपैठियों के नियमित रूप से साहिबगंज, पाकुड़ आदि इलाकों में पहुंचने की सूचना थी। इसके बाद ट्रेनों में ही इन्हें पकड़ने की रणनीति बनी। पाकुड़ व बरहड़वा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के रुकने पर स्थानीय लोग घुसपैठियों को खोजते और जीआरपी के हवाले कर देते थे। इस क्रम में सैकड़ों घुसपैठियों को पकड़ा गया। उन्हें साहिबगंज व राजमहल के साथ-साथ भागलपुर जेल में भी रखा गया। सजा पूरी करने के बाद उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया था।

पाकुड़ में दर्ज हुए घुसपैठ के कई मामले

कमल कृष्ण भगत ने बताया कि इसी क्रम में घुसपैठियों पर पाकुड़ नगर थाना में 1991 में केस दर्ज हुआ। डीएसपी व थाना प्रभारी ने पकड़े गए 18 बांग्लादेशी घुसपैठियों को छोड़ दिया। इसके बाद आंदोलन से जुड़े लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 25 नवंबर, 1993 को डीएसपी व थाना प्रभारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस पदाधिकारियों ने मामले को काफी दिनों तक लटकाए रखा, तब कोर्ट के हस्तक्षेप पर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। भाजपा नेता व तब जिला उपाध्यक्ष रहे गणेश तिवारी कहते हैं कि घुसपैठ के खिलाफ 1992-93 में जोरदार आंदोलन चला था। इस क्रम में साहिबगंज में धरना प्रदर्शन किया गया था। उस समय साहिबगंज-पाकुड़ में 1.75 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश का अनुमान था।

पटना में दिनदहाड़े पंजाब नेशनल बैंक से 20.48 लाख की लूट

जागरण संवाददाता, पटना

▶ सुरक्षा में तैनात निहत्थे सैप जवानों, ग्राहकों एवं बैंककर्मियों को बनाया बंधक

▶ सीसीटीवी का डीवीआर उखाड़कर ले गए, बाइक से पहुंचे थे चार बदमाश

पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखा में सोमवार को दिनदहाड़े लगभग साढ़े 20 लाख रुपये लूट लिए गए। हथियारबंद अपराधियों ने सुरक्षा में तैनात निहत्थे सैप (स्पेशल आर्म्ड पुलिस) जवान समेत बैंककर्मियों और 13 ग्राहकों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद लूटी गई नकदी और बैंक में लगे सीसी कैमरों का डीवीआर लेकर बाइक से भाग निकले। तीन-चार की संख्या में रहे अपराधियों ने बैंक लूट की है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी।

सुल्तानपुर-कौरया स्थित पीएनबी की शाखा के प्रबंधक संतोष कुमार के अनुसार, स्ट्रांग रूम के एक लाकर में रखे 75 हजार की करेंसी व फटे-पुराने नोट बच गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो बदमाश वारदात से पहले बैंक परिसर में घुस कर रेकी कर रहे थे। वे फार्म लेकर दस मिनट तक इधर-उधर घूमते रहे। सुबह 10:25 बजे उनका साथी पिस्तौल के बल पर सुरक्षाकर्मी को लेकर अंदर आया। तब उन दोनों ने भी हथियार निकाल लिए। एक शाखा प्रबंधक के कमरे में चला गया। उसने पिस्तौल दिखाकर बाकी कर्मियों को भी वहीं आने को विवश किया। सभी के मोबाइल लेकर मेज पर रखे। खौफ पैदा करने के लिए प्रबंधक और कैशियर को घूसे भी मारे। फिर सभी को स्ट्रांग रूम में ले गए और रकम निकलवाकर उसी में बंद कर दिया।

****

केदारघाटी में निकाले गए 1,401 और तीर्थयात्री

कुदरत का कहर ▸ उत्तराखंड में छह दिन में सकुशल निकाले जा चुके 11,652 लोग, अब तक चार शव बरामद

हिमाचल के तीन जिलों में बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत, 39 अब भी लापता

जागरण टीम, नई दिल्ली

उत्तराखंड और हिमाचल में वर्षा, बादल फटने और बाढ़ के चलते दुश्वारियां बनी हुई हैं। उत्तराखंड की केदारघाटी में सोमवार को एक और शव बरामद हुआ है। घाटी में अब तक पत्थरों और मलबे में दबे चार शव मिल चुके हैं। इसके साथ ही सोमवार को 1,401 तीर्थयात्रियों को निकाला गया है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित सुन्नी बांध में दो शव और मिले हैं। इनमें एक महिला और दूसरा पुरुष का है। अब भी लापता लोगों की तलाश जारी है।

केदारघाटी में 31 जुलाई को पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद भूस्खलन होने से फंसे तीर्थ यात्रियों को निकालने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान छह दिन से जुटे हैं। धाम तक पहुंचने के लिए क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग और पुल बनाने का काम शुरू हो गया है। मोबाइल सेवा भी शुरू हो गई है। आशंका है कि अब भी कुछ लोग जंगल में फंसे हैं या मलबे और पत्थरों के नीच दबे हुए हैं। खोजबीन में ड्रोन के साथ श्वान दस्ते की मदद ली जा रही है।

केदारनाथ धाम में फंसे लोगों का एमआइ 17 से किया गया रेस्क्यू। सूचना विभाग

दारचा-शिंकुला मार्ग पर फिर बादल फटा, बाढ़ आई

लाहुल घाटी के धांदल नाले में आई बाढ़ से सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पुल को नुकसान पहुंचा है। मायड़ घाटी में करपट से आगे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, दारचा-शिंकुला मार्ग पर फिर से बादल फटने से बाढ़ आ गई है। चार दिन से जंस्कार का मनाली से संपर्क कटा हुआ है। जिंगजिंगबार में बाढ़ आने से मनाली-लेह मार्ग चार घंटे बंद रहा। शिचलिंग नाले में बाढ़ आने से समदो-काजा मार्ग बंद हो गया है। लादारचा मैदान में सड़क क्षतिग्रस्त होने से लगभग 300 वाहन फंस गए थे। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों व लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है।

मौसम हुआ साफ तो बचाव अभियान में जुटा चिनूक : केदारघाटी में सोमवार को जो शव बरामद हुआ है। उसकी पहचान गौतम निवासी 223 ए, वार्ड नंबर 18 जगाधरी, यमुनानगर (हरियाणा) के रूप में हुई। वहीं, यहां फंसे तीर्थ यात्रियों को निकालने का अभियान अभी पूरा नहीं हो पाया है। चिनूक हेलीकाप्टर का मौसम साफ होने से पहली बार इस अभियान में उपयोग हो पाया।

वायुसेना के एमआइ-17 और छोटे हेलीकाप्टर ने भी भरपूर सहयोग किया। अब तक 11,652 तीर्थ यात्रियों को सकुशल निकाला जा चुका है। श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि अब धाम में 70 से 100 तीर्थयात्री और करीब 300 स्थानीय लोग हैं।

राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ के हालात : राजस्थान के सवाईमाधोपुर, दौसा, बीकानेर, सीकर सहित कई जिलों में रविवार रात से हो रही वर्षा से हालात बिगड़ने लगे हैं। सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को राहत के आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वर्षा से अलग-अलग हादसों में आधा दर्जन लोगों की मौत की सूचना है। जोधपुर में तेज वर्षा के बीच सोमवार सुबह करीब चार बजे एक फैक्ट्री की दीवार गिर गई। इसमें 13 मजदूर दब गए, जिनमें से तीन की मौके पर और एक की अस्पताल में मौत हो गई।

जोधपुर के ही गोतावर बांध में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पाली में दो पुराने मकान गिर गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। जोधपुर मंडल के केरल-पाली मारवाड़ एवं बिलाड़ा-पिपाड़ मार्ग पर पानी भरने के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है।

हिमाचल प्रदेश में पांचवें दिन मिले दो और शव

हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, शिमला और मंडी जिले में सात स्थानों पर बादल फटने के बाद बाढ़ आने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 39 लापता हैं। सोमवार को दो और शव बरामद हुए हैं। फिलहाल इनकी पहचान नहीं हो पाई है। अन्य लापता लोगों के स्वजन उनकी सलामती की उम्मीद में उनकी राह देख रहे हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, सेना, आइटीबीपी व सीआइएसएफ की टीमें जुटी हुई हैं।

37 के डीएनए सैंपल लिए

शिमला के समेज में त्रासदी में लापता लोगों के स्वजन के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। डीएनए मिलान के बाद ही शवों की पहचान हो पाएगी। पुलिस ने दो दिन में 37 लोगों के डीएनए सैंपल लिए हैं। समेज में लापता हुए 33 लोगों में से अब तक पांच के शव बरामद हो चुके हैं।

इकोसेंसिटिव जोन के लिए योजना बनाए केरल सरकार : भूपेंद्र यादव

▸ केंद्रीय मंत्री ने विजयन सरकार पर लगाया अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप

नई दिल्ली, एएनआइ : केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के बाद चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को केरल की पी. विजयन के नेतृत्व वाली सरकार पर अवैध खनन को शह देने का आरोप लगाया। कहा- केरल सरकार के संरक्षण में अवैध मानव निवास और अवैध खनन चल रहा है। साथ ही कहा कि केरल सरकार को इकोसेंसिटिव जोन के लिए योजना बनानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह एक अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। लेकिन स्थानीय राजनेताओं द्वारा यहां अवैध मानव निवास और खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां तक कि पर्यटन के नाम पर भी वे उचित क्षेत्र नहीं बना रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र पर अतिक्रमण की अनुमति दी। हमने पहले ही पूर्व वन महानिदेशक संजय कुमार की अध्यक्षता में इस संबंध में एक समिति का गठन किया है। उसने केरल सरकार के साथ पत्राचार भी किया। हमें लगता है कि यह राज्य सरकार की गलती है। स्थानीय सरकार के संरक्षण में अवैध मानव निवास और अवैध खनन गतिविधि चल रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केरल सरकार को इकोसेंसिटिव जोन के लिए एक योजना बनानी चाहिए। उसे पूर्व वन महानिदेशक की अध्यक्षता वाली समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। यादव ने कहा कि इकोसेंसिटिव जोन में

कहा- इकोसेंसिटिव जोन में अवैध आवास और खनन नहीं किया जाना चाहिए

अवैध आवास और खनन नहीं किया जाना चाहिए। अवैध आवास और खनन की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा है। हमने पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (इकोसेंसिटिव जोन) के लिए एक समिति बनाई है। लंबे समय से राज्य सरकार इस समिति से बच रही है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।

वायनाड आपदा में मृतक संख्या 388 हुई, 180 अभी भी लापता : आइएएनएस के अनुसार, केरल के वायनाड में राहत और बचाव अभियान सातवें दिन यानी सोमवार को भी जारी रहा। पिछले मंगलवार को वायनाड में भारी बारिश के बाद हुए विनाशकारी भूस्खलन से मरने वालों संख्या अब बढ़कर 388 हो गई है तथा 180 लोग अभी भी लापता हैं। भारी बारिश के बाद वायनाड में हुए भूस्खलन में चार गांव चूरलमाला, मुंडक्कई, अट्टमाला और नूलपुझा पूरी तरह तबाह हो गए थे।

स्वजन से दी अनुमति, दुष्कर्म पीड़िता का होगा गर्भपात, डीएनए परीक्षण भी

अयोध्या दुष्कर्म प्रकरण

▸ बाल कल्याण समिति की ओर से नियुक्त महिला सहायक ने दी रिपोर्ट

▸ बेहतर उपचार को किशोरी लखनऊ के अस्पताल में कराई गई भर्ती

जागरण संवाददाता, अयोध्या

अयोध्या में दुष्कर्म की शिकार किशोरी के घर वालों ने गर्भपात की सहमति दे दी है। पुलिस ने आरोपितों को दंड दिलाने के लिए डीएनए जांच करने का भी निर्णय लिया है। परिवार की सहमति के बाद सोमवार को सुबह 11 बजे अयोध्या से सीएमओ संजय जैन किशोरी को लेकर लखनऊ रवाना हुए। दोपहर बाद तीन बजे उसे गर्भपात व बेहतर उपचार के लिए कड़ी सुरक्षा में लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुष्कर्म के आरोपित समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर पंचायत अध्यक्ष मोईद खान और उसके सहयोगी राजू को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। गत दिनों मामला प्रकाश में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेकर पीड़ित परिवार से भेंटकर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था और आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई थी। इसी के साथ आरोपित की अतिक्रमण कर बनाई गई बेकरी पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। अन्य संपत्तियों की भी जांच चल रही है।

किशोरी के परिवार की बेहतर चिकित्सा की मांग पर उसे लखनऊ में इलाज का भरोसा दिया गया था। इसी के बाद गर्भपात पर निर्णय लेने के लिए बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की ओर से नियुक्त की गई सहायक ने स्वजन की सहमति ली और रिपोर्ट समिति के अध्यक्ष सर्वेश अवस्थी को सौंप दी। अध्यक्ष ने बताया कि चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम 1971 के अंतर्गत हुए संशोधन में यह प्रविधान है कि यदि पीड़िता का गर्भ 24 सप्ताह से कम का है तो गर्भ समापन के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। संबंधित प्रकरण में किशोरी का गर्भ 12 से 13 सप्ताह का है। किशोरी को न्याय दिलाने के लिए बाल कल्याण समिति उसे निश्शुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में किशोरी की आयु 22 वर्ष पूर्ण होने तक 2500 रुपये प्रति माह, जबकि स्पांसरशिप योजना में 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रत्येक माह चार हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

उधर, एसएसपी राजकरन नय्यर ने कहा कि अकाट्य साक्ष्य एकत्र करने के लिए पुलिस फारेंसिक जांच कराएगी, जिसके अंतर्गत डीएनए टेस्ट भी होगा, ताकि आरोपितों को कठोरतम दंड दिलाया जा सके। डीएनए टेस्ट के लिए न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक होता है। आरोपितों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है, ताकि गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जा सके।

वायनाड के पीड़ितों के लिए कांची मठ ने बनाया विशेष कोष

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केरल के वायनाड में भूस्खलन से हुई भारी तबाही के बाद राहत और पुनर्वास कार्य में केंद्र और कई राज्य सरकारों के साथ सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने भी पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ा दिए हैं। इस क्रम में कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने मठ की ओर से वायनाड़ की सहायता के लिए विशेष कोष गठित करने की घोषणा की है। मठ ने कहा है कि श्रद्धालुओं और दानदाताओं की ओर से इस कोष में मिलने वाली संपूर्ण राशि वायनाड़ में तबाही के शिकार लोगों के राहत-पुनर्वास पर खर्च की जाएगी और अनुदान जुटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कांची शंकराचार्य ने वायनाड़ पीड़ितों की मदद के लिए लोगों से उदारता से आगे आने की अपील की है। गोवा की भाजपा सरकार के साथ वहां के स्पीकर ने भी वायनाड़ के प्रभावितों की मदद का सोमवार को एलान किया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने वायनाड़ में 100 घर बनाने की तो तेलंगाना सरकार ने भी कई तरह से मदद की घोषणा की है।

विस उपचुनाव से पहले भाजपा करना चाहती षड्यंत्र : अखिलेश

राज्य ब्यूरो, जागरण लखनऊ

अयोध्या में नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा षड्यंत्र करना चाहती है। समाजवादी विचारक जनेश्वर मिश्र की 92वीं जयंती पर सोमवार को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बात कहते हुए उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही भाजपा का लक्ष्य रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए।

उन्होंने डीएनए टेस्ट कराने की अपनी मांग फिर से दोहराई। हाथ में एक कागज दिखाते हुए बोले कि यह वर्ष 2023 का भाजपा सरकार का ही आदेश है कि जिस मामले में सात साल से अधिक की सजा का प्राविधान है, उसमें डीएनए टेस्ट कराया जाए। ऐसे में मैं क्या गलत मांग कर रहा हूं? यह भी बोले कि पुलिस सच्चाई जानती है, लेकिन वह भाजपा के

अयोध्या के दुष्कर्म प्रकरण में सपा मुखिया ने लगाया आरोप, डीएनए टेस्ट की मांग दोहराई

इशारे पर काम कर रही है। अधिकारी इतने दबाव में हैं कि वे किसी को सिर न मार दें, जैसा कि क्योटो (वाराणसी) में हुआ। कन्नौज में वंचित समाज की बेटी के साथ घटना हुई है। पुलिस ने उसके आत्महत्या करने की झूठी कहानी बता दी। कन्नौज के भाजपा नेता के इशारे पर उस बेटी की लाश का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इस दौरान अखिलेश ने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का नाम लिए बिना कहा कि एक मंत्री चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया है। सरकार में रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे। जिन्हें आरक्षण की चिंता है, वे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई-बहन चाहे दिल्ली में हों या लखनऊ में, तुरंत भाजपा को छोड़ दें।

रोज वैली चिटफंड घोटाला

ईडी जमाकर्ताओं को 12 करोड़ रुपये वापस करे : कोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता : रोज वैली चिटफंड घोटाले में कोलकाता की विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने ईडी को आदेश दिया है कि वह समूह की कुर्क की गई 14 एफडी में से लगभग 12 करोड़ रुपये करीब 22 लाख छोटे जमाकर्ताओं को वापस करे। यह राशि कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप कुमार सेठ की अध्यक्षता वाली संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) को सौंपी जाएगी। समिति या अदालत के निर्देशानुसार आनुपातिक आधार पर वैध दावेदारों को वितरित किया जाएगा।

बता दें कि रोज वैली समूह ने भारी रिटर्न का वादा कर लोगों से पैसे जमा लिए, जिनमें अधिकतर लोगों को पैसे लौटाए नहीं गए। समूह पर विभिन्न राज्यों में निवेशकों के करीब 17,000 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप है। ईडी ने रोज वैली समूह के अध्यक्ष गौतम कुंडू और अन्य के खिलाफ वर्ष 2014 में मामला दर्ज करने के बाद धन शोधन निरोधी कानून के तहत 14 एफडी को जब्त कर लिया था।

कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश पर रोक बढ़ी

▸ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकार के निर्देशों पर 22 जुलाई को लगाई थी अंतरिम रोक

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी उन निर्देशों पर अंतरिम रोक सोमवार को बढ़ा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को दुकान मालिक और कर्मचारी का नाम, पता आदि प्रदर्शित करने के प्रशासनिक और पुलिस आदेशों पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा था कि दुकान मालिकों और कर्मचारियों को नाम और पहचान उजागर करने को बाध्य नहीं किया जा सकता।

जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ समय की कमी के कारण मामले की सुनवाई नहीं कर सकी, लेकिन अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया। एक पक्ष की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि वर्तमान में कांवड़ यात्रा जारी है। श्रावण 19 अगस्त को समाप्त होगा। जब उन्होंने अदालत से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया तो पीठ ने कहा कि सुनवाई की तारीख तय की जाएगी, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि

समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं कर सकी अदालत, अंतरिम आदेश को बढ़ाया

मामले की अगली सुनवाई कब होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना, "संभावित भ्रम" से बचना और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के अलावा मध्यप्रदेश के उज्जैन में भाजपा शासित नगर निकाय ने भी दुकान मालिकों को इसी तरह का निर्देश जारी किया था। उज्जैन में भगवान शिव का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है।

हिमाचल में होगा कैंसर रोगियों का निश्शुल्क उपचार

▸ मुख्यमंत्री सुक्खू ने की निश्शुल्क दवाएं प्रदान करने की घोषणा

▸ कहा, हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला

हिमाचल में अब कैंसर रोगियों को निश्शुल्क उपचार मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस रोग का निश्शुल्क उपचार और दवाएं प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कैंसर के उपचार के लिए 42 दवाएं निश्शुल्क देगी। इसमें ट्रैस्टुजुमाब टीका भी शामिल है, जिसका मूल्य करीब 40 हजार रुपये होता है। ब्रेस्ट कैंसर होने पर वर्ष में ऐसे 18 टीके लगते हैं। इस टीके को उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक रोगी पर राज्य सरकार लगभग 7.20 लाख रुपये व्यय करेगी। ये दवाइयां सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश जनसंख्या के अनुपात में कैंसर के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर है। इसी के मद्देनजर कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया है। वह सोमवार को शिमला में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड आन कैंसर एंड पैलिएटिव केयर प्रोग्राम की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सरकारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्टेट एडवाइजरी बोर्ड आन कैंसर एंड पलिएटिव केयर प्रोग्राम की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए। जागरण

अस्पतालों में कैंसर के उपचार के लिए 42 दवाएं निश्शुल्क मिलेंगी। इन्हें राज्य की अनिवार्य दवा सूची में शामिल किया गया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से हमीरपुर में स्थापित किए जाने वाले कैंसर केयर सेंटर आफ एक्सीलेंस में विश्वस्तरीय तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यहां न्यूक्लियर मेडिसन का विशेष विभाग स्थापित किया जाएगा, जिसमें बड़ी क्षमता की न्यूक्लियर लैब और साइक्लोट्रोन भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

रात को सुनवाई कर इंडोनेशिया से आए जहाज को बंदरगाह पर रोका

▸ एक पेपर कंपनी ने जहाज से क्षतिग्रस्त माल की आपूर्ति का लगाया है आरोप

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता

कलकत्ता हाई कोर्ट ने रविवार रात को जरूरी आधार पर सुनवाई कर इंडोनेशिया से आए एक जहाज को हल्दिया बंदरगाह पर आठ अगस्त तक रोककर रखने का आदेश दिया। जहाज के सोमवार सुबह सात बजे रवाना होने की बात थी। बता दें कि एक पेपर कंपनी ने जहाज प्रबंधन पर क्षतिग्रस्त माल की आपूर्ति करने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। कंपनी ने कहा कि हल्दिया बंदरगाह पर क्षतिग्रस्त माल की आपूर्ति कर जहाज भारत छोड़कर पनामा जा रहा है। इसे नहीं रोके जाने पर उसे कई करोड़ रुपये का नुकसान होगा। कंपनी ने कहा कि इंडोनेशिया से जहाज 25 जुलाई को हल्दिया पहुंचा था। जहाज में 8,000 मीट्रिक टन पेपर था, जिसकी कीमत 54 लाख 22 हजार 356 डालर है। उनमें से 1,312 टन पेपर क्षतिग्रस्त पाए गए हैं, जिसका भारतीय मुद्रा में मूल्य सात करोड़ 48 लाख 77 हजार 480 रुपये है। कानून के मुताबिक जहाज में सामान के नष्ट होने पर जहाज प्रबंधन की जिम्मेदारी

बनती है।

मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए रात नौ बजे न्यायाधीश अरिंदम मुखर्जी ने अदालत बिठाई। उन्होंने जहाज को हल्दिया बंदरगाह पर आठ अगस्त तक रोकने के आदेश के साथ यह भी कहा कि जहाज के अधिकारी अगर इसके पहले जहाज ले जाना चाहते हैं तो अदालत में सात करोड़ रुपये जमा कर ऐसा कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर पेपर कंपनी आठ अगस्त तक साबित कर देती है कि पेपर के क्षतिग्रस्त होने का जिम्मेवार जहाज प्रबंधन है तो आगे की कार्रवाई के लिए जहाज को रोका जा सकता है, नहीं तो जहाज को छोड़ दिया जाएगा। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

जागरण विशेष

'जल आंदोलन' से जुड़ा जनसमूह तो धरती मां को पानी लौटाने लगा देवास

मप्र के शहर ने बिना सरकारी मदद रचा इतिहास, घरों, उद्योगों, निजी व सरकारी स्कूलों, होटल, मंदिर-आश्रमों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से सहेजा वर्षा जल

चंद्रप्रकाश शर्मा • नईदुनिया

देवास: मध्य प्रदेश के देवास शहर में पांच लोगों द्वारा शुरू किए गए अभियान ने सरकारी मदद के बिना इतिहास रच दिया है। सड़क पर व्यर्थ बहने वाले वर्षाजल को इस वर्ष जमीन में उतारने के लिए शुरू हुए अमृत संचय जन आंदोलन से जब शहर के लोग जुड़े तो इसने 'जल आंदोलन' का रूप ले लिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि रसातल की ओर जाने वाला भूजल स्तर ऊपर उठना शुरू हो गया।

हर जगह वर्षाजल सहेजने का प्रयास: घरों, उद्योगों, अस्पताल, निजी व सरकारी स्कूल, होटल, वेयरहाउस, मंदिर-आश्रम की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर बूंद-बूंद वर्षाजल को सहेजा जा रहा है। छतों के अलावा अन्य स्थानों पर गिरने वाले वर्षाजल को रिचार्ज पिट, डगवेल, परकोलेशन टैंक, संकेन पांड, कंटूर ट्रेंचेस आदि के माध्यम से जमीन में उतारा जाने लगा। आमतौर पर एक हजार वर्गफीट क्षेत्रफल वाली छत से करीब एक लाख लीटर जल वर्षाकाल में व्यर्थ बह जाता है। अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि देवास में जितनी छतों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हैं, उससे अब तक करीब दो सौ करोड़ लीटर जल संचयन हो चुका है। देवास के इस नवाचार पर अब मप्र काउंसिल आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। टीम आकर देखेगी कि इतना बड़ा जन आंदोलन बिना सरकारी मदद के कैसे संभव हुआ और इसका देवास के भूजल स्तर पर क्या प्रभाव हुआ। इस रिपोर्ट को मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से साझा किया जाएगा, ताकि वे भी प्रयास कर सकें।

यूं आरंभ हुआ अमृत संचय: भूजलविद् डा. सुनील चतुर्वेदी इस बात से चिंतित थे कि देवास में जलसंकट गहराता जा रहा है। उन्होंने इस चिंता को चिंतन में बदला और 'अमृत संचय' नामक अभियान शुरू किया। वह अपनी टोली के साथ घर-घर गए और लोगों को जल का महत्व समझाया। देखते ही देखते यह पहल जन अभियान बन गई। इसी वर्ष 16 मई से शुरू हुए इस अभियान में देवास शहर के विभिन्न सेक्टरों की सूची बनाई गई और अनेक बड़े संस्थानों को अभियान से जोड़ा गया। सबके साथ बैठक कर छत का पानी जमीन में उतारने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने को प्रेरित किया गया। दो माह से भी कम समय में यह पहल बड़ा अभियान बन गई और घरों व प्रतिष्ठानों में हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए।

कभी ट्रेन से आता था पानी

एक दौर था, जब देवास में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची थी। भूजल स्तर गिरने से वर्ष 1980 से 2000 के बीच यहां ट्रेन से पानी मंगवाना पड़ा था। उसके बाद भी वर्षों तक संकट बना रहा।

वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से छत का पानी उतारे जाने से कुआं इस सीजन में ही लबालब हो गया • सौ. टीम अमृत संचय »

सूख चुके कुआं व बोरिंग में आया पानी

देवास में आरंभ हुए अभियान की सफलता पहले ही वर्ष दिखाई देने लगी है। जिन घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया, वहां इसी वर्षा ऋतु में कुआं व बोरिंग में पानी आ गया है, जबकि प्रतिवर्ष सीजन के अंत तक इनमें पानी आता था। इससे अभियान टीम के साथ शहरवासियों का भी उत्साह बढ़ा है। उत्साहित लोग दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपने घरों पर लगे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के फोटो और वर्षा का पानी जमीन में उतरने की प्रक्रिया के वीडियो एक-दूसरे से साझा कर रहे हैं।

अमृत संचय अभियान सरकार का नहीं, जनता का है। हमने पानी का महत्व बताया, जन-जन को जागरूक किया और इसे बचाने के तरीके बताए। लोग आज और आने वाली पीढ़ी के लिए जल सहेजने में जुट गए हैं। हमने देश-दुनिया को संदेश दिया है कि कैसे कोई शहर जल आत्मनिर्भर बन सकता है। अभी यह शुरुआत है, इसके और सुखद परिणाम दिखेंगे।

डा. सुनील चतुर्वेदी, भूजलविद् व अमृत संचय अभियान के प्रणेता, देवास

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

ग्वालियर चिड़ियाघर में बाघिन मीरा ने दिया तीन शावकों को जन्म

तीनों शावकों के साथ बाघिन मीरा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित गांधी प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) की पहचान अब बाघों से हो रही है। यहां लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। 28 जून तक चिड़ियाघर में तीन शावक मिलाकर नौ बाघ थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। रविवार देर रात बाघिन मीरा ने तीन शावकों को जन्म दिया। इनमें से दो सफेद हैं। चिड़ियाघर में अब पांच सफेद और सात रायल बंगाल टाइगर हैं। सीएम डा. मोहन यादव ने वन विभाग के कर्मचारियों को बधाई दी है।

****

दैनिक जागरण
हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं

बेहाल बांग्लादेश

करीब सात महीने पहले फिर से सत्ता में आईं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिस तरह आनन-फानन देश छोड़कर भारत आने के लिए विवश होना पड़ा, उससे यही पता चलता है कि हालात किस कदर उनके खिलाफ हो गए थे। इसे इससे भी समझा जा सकता है कि उनका इस्तीफा मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने उनके सरकारी आवास में घुसकर तो तोड़फोड़ की ही, उनके पिता एवं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के साथ उनके नाम पर बने एक संग्रहालय को भी जला दिया। जैसी आशंका थी, शेख हसीना के पलायन करते ही सेना ने सत्ता संभाल ली और मिली-जुली अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की। शायद सेना इसकी तैयारी पहले से कर रही थी। शेख हसीना लगातार चौथी बार ऐसे चुनावों के जरिये सत्ता में आई थीं, जिनका प्रमुख विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था। चूंकि शेख हसीना ने अपने लंबे शासनकाल में बांग्लादेश को स्थिरता प्रदान की और उसे आगे बढ़ाया, इसलिए उनकी सत्ता को कोई खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ समय पहले आरक्षण के खिलाफ छात्रों की ओर से शुरू हुआ आंदोलन उनके लिए मुसीबत बन गया। इस आंदोलन को शीघ्र ही शेख हसीना के सभी विरोधियों और साथ ही ऐसे कट्टरपंथी संगठनों ने भी समर्थन दे दिया, जो पाकिस्तान की कठपुतली माने जाते हैं। इसके चलते आरक्षण विरोधी आंदोलन सत्ता परिवर्तन के हिंसक अभियान में बदल गया। लगता है शेख हसीना विरोधियों की चाल भांप नहीं सकीं।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में भारी कटौती कर दी, लेकिन विरोधी संतुष्ट नहीं हुए। वे शेख हसीना का इस्तीफा मांगने पर अड़ गए। आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और उसमें तीन सौ लोगों के मारे जाने के कारण शेख हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निंदा करने में मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उसकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं थीं। बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संतुलन साधने की शेख हसीना की नीति से चीन भी उनसे रुष्ट था और इसी कारण उन्हें हाल की अपनी चीन यात्रा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा था। इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्वों के जरिये शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि वह नई दिल्ली के प्रति मित्रवत थीं। यदि सेना के प्रभुत्व वाली अंतरिम सरकार चीन के प्रभाव में काम करती है तो यह भारत के लिए और अधिक चिंता की बात होगी। बांग्लादेश में एक अर्से से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं।

अवैध खनन पर सख्ती

प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन माफिया की सक्रियता कम नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का अवैज्ञानिक तरीके से अंधाधुंध दोहन कर न केवल प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि प्रदेश सरकार को भी राजस्व की हानि झेलनी पड़ रही है। अवैध खनन रोकने के लिए 14 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश में खनन से जितनी कमाई सरकार नहीं कर पाती, उससे कई गुणा अधिक माफिया कर लेता है। अवैध खनन को गंभीरता से लेते हुए उद्योग मंत्री ने पिछले दिनों कई जिलों का दौरा कर बैठकें कीं और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। अब प्रदेश में कई स्थानों पर उनकी पहल का प्रभाव खनन माफिया पर कार्रवाई के रूप में दिखने लगा है। ऊना व पुलिस जिला बद्दी में अवैध खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई में तेजी आई है। रविवार को ऊना में 11 वाहनों के चालान काट जुर्माना वसूला गया। बद्दी में भी मुख्य संसदीय सचिव की पत्नी के नाम पर चल रहे वाहन को जब्त किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। खनन माफिया की कमर तोड़ने के लिए सभी जिलों में व्यापक स्तर पर अभियान चलाना समय की मांग है। सुखद है कि लोग भी अब सामने आने लगे हैं और अवैध गतिविधियों की जानकारी शासन-प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं।

अवैध खनन रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के सकारात्मक परिणाम आने की आशा है

पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का समय

कैप्टन आर. विक्रम सिंह

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को सक्रिय कर पाकिस्तान ने नए सिरे से परोक्ष युद्ध प्रारंभ कर दिया है। सवाल यह है कि हमारा जवाब किस तरह होगा?

जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35 ए से मुक्ति दिलाए हुए पूरे पांच वर्ष हो गए है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के बाद जम्मू-कश्मीर के परिवेश में आए गुणात्मक परिवर्तन ने वहां अलगाववाद को दरकिनार कर विकास एवं रोजगार से जुड़ी संभावनाएं जगाई हैं। परिवारवादी राजनीति को हाशिए पर धकेल कर नया विकासोन्मुख नेतृत्व खड़ा होने लगा है। लोकसभा चुनाव में हुई बंपर वोटिंग के बाद पाकिस्तान को आशंका सता रही है कि यदि विधानसभा चुनावों में भी ऐसा हुआ तो उससे यही माना जाएगा कि कश्मीरी जनमानस ने भारत के साथ अपने भविष्य को जोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है। स्वाभाविक है कि राज्य में यह सकारात्मक बदलाव पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। यही कारण है कि उसने यहां आतंकवाद को नए सिरे से धार देना शुरू कर दिया है। ऐसी खबरें है कि पाकिस्तान राज्य में बड़ी घुसपैठ की साजिश में लगा है। कहा जा रहा है कि मुजफ्फराबाद में छह सौ एसएसजी कमांडोज की यूनिट लाई गई है। इस सिलसिले में उनके कमांडिंग आफिसर सईद सलीम जंजुआ का नाम भी सामने आया है।

कुछ ही दिन पहले आतंकियों ने जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमले के बाद कठुआ और डोडा में सैन्य बलों पर हमला किया। भारतीय सीमा के इतने भीतर आकर आक्रमण से स्पष्ट है कि आतंकी उच्चस्तरीय प्रशिक्षित हैं। भारत सरकार ने संज्ञान लेते हुए बीएसएफ के उच्चाधिकारियों को हटा दिया है। चूंकि जम्मू-कश्मीर अब कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं रहा, इसलिए पाकिस्तान का उद्देश्य इसे किसी भी तरह अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर नए सिरे से उभारने का है। पाकिस्तान को चीन की शह भी मिली हुई है। अमेरिकी मेहरबानी के चलते आइएमएफ से मिली वित्तीय मदद ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को थोड़ी-बहुत राहत भी दी है। अमेरिका के पाकिस्तान प्रेम का प्रकट लक्ष्य तो उसे चीन से दूर करना है, लेकिन उसके लिए भारत को नियंत्रित करने के लिए भी पाकिस्तान को जिंदा रखना और कश्मीर को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाए रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के बाद अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के तर्क पर रूस-यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए कहा था कि युद्धकाल में ऐसी कोई स्वायत्तता नहीं होती और हमारे संबंध गहरे तो हैं, पर इतने गहरे भी नहीं कि आप जो चाहें, वह कर डालें। यह बयान कम चेतावनी अधिक थी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसका तीखा जवाब भी दिया था। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में फिलहाल गर्मजोशी का अभाव दिखता है। ऐसे कुछ संकेत भी हैं कि उसने भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की भी कोशिश की। इस सबसे पाकिस्तान का आत्मविश्वास नए सिरे से बढ़ा है।

पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ानी होगी सतर्कता। फाइल

पाकिस्तान की ताजा हरकतों से उसके साथ संघर्षविराम की कोई उपयोगिता नहीं रह गई। पाकिस्तानी शासक अपनी जनता को बरगलाते आए हैं कि कश्मीर तो उनकी शहरग अर्थात 'गले की नस' है और उसे वे लेकर रहेंगे। मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार अख्तर निसार ने पाकिस्तानी सेना पर व्यंग्य करते हुए कहा था कि यह कैसी शहरग है, जिसके बगैर भी हम सत्तर सालों से जिंदा हैं। पाकिस्तानी सेना को अब स्थानीय स्तर चुनौतियां मिलने लगी हैं। उसका फरेब खत्म हो जाने के बाद वह पाकिस्तान के लोकतांत्रिक दलों को भला कैसे नियंत्रित कर पाएगी? कश्मीर मुद्दे के विवादित न रहने से पाकिस्तान को गृहयुद्ध के उस आशंकित परिदृश्य से कौन रोक पाएगा, जिसकी पठान एवं बलूच क्षेत्रों में अभी से झलकियां दिखने लगी हैं। अब पाकिस्तानी शासकों के सामने यही उपाय बचा है कि वे आंतरिक स्थितियों से आम जनता का ध्यान हटा कर भारत एवं हिंदू शत्रुता के एजेंडे को भुनाएं। उन्होंने कारगिल में देखा है कि भारत पूरे नियम-कायदों से युद्ध लड़ता है। विवादित और दूसरों के अवैध कब्जों वाले क्षेत्रों में चाहे वह कश्मीर ही क्यों न हो, प्रवेश नहीं करता। अतः ऐसे सीमित युद्ध के परिणामों से उनके सामने कोई अस्तित्व का संकट खड़ा नहीं होगा। इसके साथ ही चीन और अमेरिका को कूटनीति की एक बड़ी संभावना दिखेगी। इस तरह संयुक्त राष्ट्र और मुस्लिम देशों के सहयोग से कश्मीर को वापस अंतरराष्ट्रीय विवाद के केंद्र लाना संभव हो सकेगा। पाकिस्तान को अंदाजा है कि घुसपैठ की किसी उच्चस्तरीय योजना पर भारत की संभावित सैन्य प्रतिक्रिया क्या हो सकती है?

अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यही है कि विश्व में प्रायः युद्ध ही समस्याओं का अंतिम समाधान करते दिखते हैं। शांति वार्ताएं स्थायी समाधान नहीं दे पातीं। पाकिस्तान के मामले में ही सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक इसकी मिसाल रहीं। याद रहे कि हर युद्ध परोक्ष युद्ध के रूप में ही प्रारंभ होता है। यदि आत्मप्रशंसा से प्रेरित हमारे रणनीतिविहीन नेतृत्वों ने पूर्व के युद्धों में आत्मसमर्पणकारी सोच का घालमेल न करके सैन्यशक्ति एवं कूटनीति का तार्किक उपयोग किया होता तो कश्मीर समस्या का समाधान बहुत पहले हो गया होता। देश किस सीमा तक जाकर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं, हमारे सामने आज इजरायल-हमास और रूस-यूक्रेन युद्ध इसके उदाहरण हैं। युद्धों के अपनी स्वाभाविक परिणति तक पहुंचने के बाद ही शांति वार्ताओं के लिए स्थान बनता है। यह भी एक बड़ा सत्य है कि युद्धों के बाद ही अस्थिरताओं का समापन होता है एवं शांति और विकास के लंबे दौर आते हैं।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को सक्रिय कर पाकिस्तान ने नए सिरे से परोक्ष युद्ध प्रारंभ कर दिया है। सवाल यह है कि हमारा जवाब क्या होगा? इतिहास गवाह है कि हमारे नेताओं ने देश को बांटकर आजादी का सौदा किया था। कश्मीर को बांटकर वहां भी शांति की सौदेबाजी चाही। अपनी इन आत्मघाती नीतिगत बाध्यताओं के कारण हमने कभी भी कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए पाकिस्तान को निर्णायक रूप से परास्त करने का लक्ष्य नहीं बनाया। हमने बहुत समय गंवा दिया। आज की परिस्थितियां यही अपेक्षा करती हैं कि हम अपने दृष्टिकोण में आधारभूत नीतिगत परिवर्तन के साथ लक्ष्य नियत करें और राष्ट्रहित के मार्ग पर पूरी शक्ति से बढ़ने का निर्णय लें।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

सुनिश्चित हो परीक्षाओं की शुचिता

सुरेंद्र किशोर

भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ स्कूल-कालेज की परीक्षाओं में भी कदाचार रोकने की दिशा में ठोस कदम जरूरी हैं

प्रश्नपत्र लीक होने के सिलसिले को रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ आठ राज्य सरकारों ने भी इससे संबंधित कानून बनाए हैं। हाल में बिहार सरकार ने भी बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक पारित किया है। यह सराहनीय और समयानुकूल है। सामान्य और भर्ती परीक्षाओं में कदाचार की समस्या देशव्यापी है। यह जरूरी था कि केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी इसे रोकने की दिशा में कदम उठातीं। भर्ती परीक्षाओं के अलावा सामान्य परीक्षाओं में भी कदाचार रोकने की दिशा में ठोस काम होना चाहिए, तभी नए कानून कारगर हो पाएंगे। यह संयोग नहीं है कि नीट में प्रश्नपत्र लीक के केंद्र हजारीबाग और पटना रहे।

बिहार के प्रश्नपत्र लीक रोधी कानून में भी दस साल तक की सजा और एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रविधान किया गया है। इससे कानून का उल्लंघन करने वालों में अधिक भय पैदा होगा। इससे पहले बिहार में 1981 में नकल विरोधी कानून बना था। उसके तहत छह महीने की जेल और दो हजार रुपये के जुर्माने का प्रविधान था। वह कानून तनिक भी करगर साबित नहीं हुआ। बिहार ने जो नया कानून बनाया है, उसके तहत दायर मुकदमों की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। पुराने कानून में ऐसा प्रविधान नहीं था। बिहार सरकार पेपरलीक कांड की जांच बिहार पुलिस के अलावा किसी अन्य एजेंसी से करा सकेगी। बिहार का यह कानून जिन संस्थाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा, उनमें बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद, बिहार तकनीकी सेवा आयोग शामिल हैं। यह सब ठीक है, लेकिन प्रश्न है कि क्या स्कूल-कालेज और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं को कदाचारमुक्त किए बिना भर्ती परीक्षाओं में जारी कदाचार को पूर्णतः रोका जा सकता है? यह सवाल बिहार के सामने ही नहीं, सभी राज्यों के समक्ष है। आखिर आज देश के कितने राज्यों के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा-परीक्षा हो पा रही है? शिक्षा-परीक्षा को सुधारे बिना भर्ती परीक्षाओं के लिए कितने सुशिक्षित उम्मीदवार मिल पाएंगे? इसलिए अगले कदम के तहत राज्य सरकारों को वहां जारी गंदगी की भी सफाई के लिए कारगर कदम उठाने होंगे। इस दिशा में अब तक जो भी कदम उठाए गए, वे विफल ही रहे हैं। समय-समय पर अनेक राज्यों में सच्ची परीक्षा और सच्ची पढ़ाई की कोशिशें हुईं, लेकिन निहित स्वार्थी तत्वों ने उन्हें विफल कर दिया। वे तत्व आज भी कमजोर नहीं हुए हैं। सरकारें हर स्तर की परीक्षाओं को कदाचार से मुक्ति के लिए अपनी कठोर इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करें।

आम है स्कूली परीक्षाओं में नकल। फाइल

उत्तर भारत के कई राज्यों और खासकर बिहार की शिक्षा-परीक्षा में गिरावट की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन 1995 तक बिहार में उसकी हालत ऐसी दयनीय हो चुकी थी कि कई राज्य सरकारों ने बिहार इंटर काउंसिल द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को मानने से ही इन्कार कर दिया था। कई मामलों में जाली अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी जारी होने लगे थे। उस स्थिति से ऊबकर पटना हाई कोर्ट में लोकहित याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त कदाचारमुक्त परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके चलते 1996 में बिहार में मैट्रिक और इंटर की कदाचारमुक्त परीक्षाएं हुईं। 1996 की इंटर साइंस की परीक्षा में सिर्फ 15 प्रतिशत परीक्षार्थी ही उत्तीर्ण हो सके थे। पटना जिले में मैट्रिक परीक्षा में सिर्फ 16 प्रतिशत परीक्षार्थी ही सफल हो सके। कमोबेश ऐसा ही परिणाम अन्य जिलों में रहा। नतीजतन कालेजों में एडमिशन के लिए विद्यार्थियों का अकाल सा हो गया। शिक्षा माफिया के पांव उखाड़ना इतना आसान काम नहीं था। उन्हें शासन से अघोषित रूप से यह आश्वासन मिल गया कि अब आगे की परीक्षाओं में कड़ाई नहीं होगी। इस मोर्चे पर शिक्षा माफिया ही अंततः जीत गया और दोगुने उत्साह से परीक्षाओं में कदाचार करने लगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बिहार में शिक्षा-परीक्षा का हाल वैसा ही हो गया है, जैसा 1995 में था। होना तो यह चाहिए था कि परीक्षा में कड़ाई जारी रहती। शिक्षा-परीक्षा में सुधार के लिए यह जरूरी था, पर जिन्हें एक समय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा माफिया करार दिया था, उन्हीं लोगों ने ऐसी जुगत भिड़ाई कि दोबारा कदाचार शुरू हो गया। 1996 की कड़ाई के बाद के वर्षों में कदाचार की ऐसी छूट मिली कि एक दफा तो जो छात्र बिहार की बोर्ड परीक्षा में पूरे राज्य में प्रथम आया था, वह दिल्ली में ऊंची कक्षा में नामांकन के बाद एक सेमेस्टर भी पास तक नहीं कर सका।

देश भर में शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा 'उद्योग' बन गया है, जिसमें कोई घाटा नहीं होता। इस उद्योग में सिर्फ आधुनिक तकनीक के साथ-साथ उच्चस्तर के जनसंपर्क की आवश्यकता होती है। इस उद्योग से जुड़े एक 'कारखाने' का जिक्र अपनी पुस्तक 'इंटर काउंसिल एक हकीकत' में दिवंगत प्रोफेसर नागेश्वर प्रसाद शर्मा ने किया है। उस अल्पज्ञात कारखाने यानी कालेज के इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का जब एक खास साल का रिजल्ट देखा गया तो पता चला कि उसके कुल 477 में से 461 परीक्षार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की। जब इस मामले की जांच हुई तो पाया गया कि वास्तव में सिर्फ तीन छात्रों को ही प्रथम श्रेणी मिली थी। आज देश के तमाम शिक्षा संस्थान ऐसे हैं, जो मात्र शिक्षा के कारखाने बनकर रह गए हैं और जो 'घटिया माल' का ही अधिक उत्पादन करते हैं। अपवाद को छोड़कर इनके संचालकों को उन तमाम लोगों का प्रत्यक्ष और परोक्ष संरक्षण हासिल होता है, जिन पर कदाचारमुक्त शिक्षा और परीक्षा उपलब्ध कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मित्रता का आलोक

मित्रता का भाव मनुष्य के जीवन में उत्साह एवं उमंग का संचार करता है। मैत्री के लिए समर्पण का होना अत्यंत आवश्यक है। मित्र वही है जो हर सुख-दुख में प्रतिपल साथ निभाए। अच्छा मित्र मिलना सौभाग्य की बात है। एक सच्चा मित्र वह भी है जो हमें गलत मार्ग पर चलने से रोकता है। वह हमारा सच्चा हितैषी होता है। रक्त के संबंध के अतिरिक्त मित्रता ही वह संबंध होता जो अत्यंत विश्वसनीय होता है, जिसके लिए समपर्ण एवं मधुर भावनाओं के कपाट स्वतः खुलने लगते हैं।

भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता जगत प्रसिद्ध है। माता सीता की खोज में सुग्रीव एवं उनकी वानर सेना ने पूरे समर्पण के साथ कार्य किया। रावण से युद्ध किया। अपने प्राणों को संकट में डालकर प्रभु श्रीराम की सहायता की। प्रभु श्रीराम ने भी अपने मित्र सुग्रीव के लिए बाली से युद्ध कर बाली का वध किया। इसी तरह भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता को कौन नहीं जानता। वहां समपर्ण की पराकाष्ठा को देखा जा सकता है। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता भी सुप्रसिद्ध है कि कर्ण ने सत्य एवं धर्म की राह के बजाय मित्रता को वरीयता दी।

वर्तमान समय में मित्रता स्वार्थ की भेंट चढ़ती जा रही है। यह सर्वथा अनुचित है। मित्रता में वैचारिक साम्य देखा जाता है माया का आकर्षण नहीं। जो व्यक्ति सामने वाले के प्रभाव को देखकर उससे मित्रता की सोचते हैं, वे दीर्घकालिक, समर्पणयुक्त एवं स्नेहिल मित्रता के सुपात्र नहीं होते। न ही उन्हें यह सब कुछ प्राप्त हो पाता है। मित्रता में मधु सी मिठास होती है, जो दोनों ही ओर से प्रस्फुटित होती रहती है। मित्र कभी भी अपने साथी को अन्याय, असत्य एवं कुमार्ग पर चलने को विवश नहीं करता। और न ही वह अपने मित्र को इन मार्गों का पथिक बनने देता है। वह ऐसा होते देख तुरंत अपने मित्र को रोक देता है। उसे मार्ग बदलने की सलाह देने लगता है।

ललित शौर्य

मोइदम के संरक्षण की चुनौती

देवेंद्रराज सुथार

मोइदम न केवल अहोम राजवंश, बल्कि पूरे असम की संस्कृति और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं

हाल में असम के 'मोइदम' यानी अहोम राजवंश की टीला-दफन प्रणाली' को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह भारत की 43वीं संपत्ति है जिसे इसमें शामिल किया गया है। यह असम की तीसरी विश्व धरोहर संपत्ति है, इससे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरासत को सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक 59 स्थल इटली के हैं, इसके बाद 57 स्थलों के साथ चीन का स्थान है। भारत 43 स्थलों के साथ छठे स्थान पर है। मोइदम को पहचान मिलना न केवल असम के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। ध्यातव्य है कि पूर्वोत्तर भारत में अहोम साम्राज्य द्वारा निर्मित शाही टीला दफन स्थल मोइदम पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित हैं। इन दफन टीलों को अहोम द्वारा पवित्र माना जाता था और ये उनकी अनूठी अंत्येष्टि प्रथाओं को दर्शाते हैं। अहोम लोग 13वीं शताब्दी में असम पहुंचे और चराईदेव को अपना पहला शहर और शाही कब्रगाह का स्थल बनाया। 13वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी तक (600 वर्षों तक) अहोम ने पहाड़ियों, जंगलों और पानी जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके मोइदम या आत्मा के लिए घर का निर्माण किया। अपने राजाओं को दिव्य मानते हुए अहोम ने शाही दफन के लिए मोइदम बनाने की एक अलग अंत्येष्टि परंपरा विकसित की।

यूनेस्को द्वारा मोइदम को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देने के पीछे कई कारण हैं। इसकी वास्तुकला अपने आप में अनूठी है और यह दक्षिण-पूर्व एशियाई और भारतीय परंपराओं का एक अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करती है। ये स्थल अहोम राजवंश के 600 वर्षों के शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था। इस लंबे शासनकाल ने असम और पूरे उत्तर-पूर्वी भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। मोइदम न केवल अहोम राजवंश की, बल्कि पूरे असम की संस्कृति और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन स्थलों से जुड़ी तमाम परंपराएं अभी भी जीवित हैं।

मोइदम के संरक्षण में कई चुनौतियां हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन प्राचीन स्मारकों को लगातार मौसम के प्रभावों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी संरचना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा मानवीय गतिविधियां भी एक बड़ी चिंता का विषय हैं। अनियंत्रित पर्यटन और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से हो रहा शहरीकरण इन स्थलों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

आरक्षण का होगा विस्तार

'एससी-एसटी आरक्षण पर उचित फैसला' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उचित विश्लेषण किया है। वास्तव में सामाजिक न्याय के उपकरण माने जाने वाले आरक्षण का उद्देश्य ही यही है कि हाशिए पर रहने वाले वंचित लोगों को उचित अवसर दिला सके। हालांकि वर्तमान में जारी आरक्षण व्यवस्था यह कार्य कर पाने में असफल साबित हो रही है, क्योंकि आरक्षण से आच्छादित समाज भी दो वर्गों में विभाजित होता जा रहा है। एक वह वर्ग जो कई पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ लेकर पूर्ण सक्षम बन चुका है और आगे भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए अर्हता हासिल किए हुए है। दूसरी ओर वह वर्ग है, जो आरक्षण का अपेक्षित लाभ नहीं उठा पाया और विकास की मुख्यधारा से बाहर है। अब समय आ गया है कि इस विषय पर गंभीर मंथन किया जाए और सबको बराबरी का अवसर प्रदान करने की राह प्रशस्त की जाए। हालांकि वर्तमान राजनीति को देखते हुए इस समय ऐसा कर पाना संभव नहीं लग रहा। फिर भी समय की मांग है कि सभी राजनीतिक दल और नेता कोरी बयानबाजी छोड़कर वंचितों के वास्तविक हित से जुड़े इस मुद्दे पर गंभीरता से एक मंच पर खड़े हों, जिससे हर गरीब को समान अवसर मिल सके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो।

वेदप्रकाश पांडेय, अंबेडकर नगर (उप्र)

जातिवाद का दंश

संसद से लेकर अखबार की सुर्खियों तक आजकल जाति-जाति की रट ही सुनाई पड़ रही है। हर दल के बयानवीर इस विषय पर बहुत मुखर हो रहे हैं। इस बीच देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपजातियों को आरक्षण के पक्ष में निर्णय दिया है जिसे लेकर कोई दल अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। कारण, केवल और केवल वोट बैंक। जातिगत जनगणना के समर्थक भूल रहे हैं कि आज का समाज इन बातों से बहुत आगे निकल चुका है। लोग सच्चाई को जानते हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम आरक्षण की बात करते हैं और वह भी जाति के आधार पर। वसुधैव कुटुंबकम् की सनातन परंपरा वाले देश में हम मात्र वोट के लिए समाज को जाति-संप्रदाय के नाम पर बांटने के लिए तुले हैं। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं अवसरों की पर्याप्तता पर बात होनी चाहिए वहां हमारे राजनीतिक दल जाति-दंश से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ राजनीतिज्ञों का यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जो समाज को पंगु बनाता है। समाज का हर वर्ग सुशिक्षित, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो एवं उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर संपन्न हो, प्रयास इस दिशा में होने चाहिए। पर यह तो कठिन और लंबी डगर है जिसपर अधिकांश राजनीतिक दल बात नहीं करना चाहते। उन्हें तो बस सत्ता-सुख चाहिए जिसे पाने के लिए वे वोट बैंक की चाह में किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब हर वोटर राजनीतिक दलों से प्रश्न करेगा कि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उनकी कार्यनीति क्या है, शिक्षा, हेल्थ और सुरक्षा के लिए उनकी क्या विचारधारा है।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

मेलबाक्स

बंद हो आरक्षण पर राजनीति

'एसी-एसटी आरक्षण पर उचित फैसला' शीर्षक से युक्त लेख में संजय गुप्त का यह कथन गौरतलब है कि 'आरक्षण वोट बैंक की राजनीति का जरिया नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का माध्यम है'। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने गरीब और वंचित वर्ग में शुमार होने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था इसी सद्भाव के साथ लागू की थी। लेकिन कालांतर में विकृत जातिगत राजनीति ने इस आरक्षण व्यवस्था के संवैधानिक सद्भाव को गहरा आघात दिया। सामाजिक न्याय का भी यही तकाजा है कि जो वास्तव में अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के कारण समाज की मुख्यधारा से कटे हुए हैं उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, साधन सम्पन्न लोगों को नहीं।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़ (उप्र)

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

60 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी, जो राज्य की बदलती जनसांख्यिकी का प्रमाण है।

आजकल

सामाजिक न्याय को मिलेगा नया आयाम

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसने एक प्रकार से आरक्षण के भीतर आरक्षण पर मुहर लगा दी। साथ ही एससी-एसटी वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिह्नित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया। अब एससी-एसटी वर्ग की ज्यादा जरूरतमंद जातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य उनका उपवर्गीकरण कर सकते हैं। इससे एससी-एसटी वर्ग की जो जातियां अपने वर्ग में ज्यादा पिछड़ी रह गई हैं अब उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अधिक प्राथमिकता दी जा सकती है

डा. वरुण छाछर
एसोसिएट प्रोफेसर, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कोटे में कोटा यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण पर मुहर लगा दी। साथ ही एससी-एसटी वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिह्नित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया। सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से दिए फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के ही ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य उनका उपवर्गीकरण कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 20 वर्ष पुराने पांच जजों के ईवी चिनैया (2004) मामले में दी गई व्यवस्था को गलत ठहराया, जिसमें पांच जजों की पीठ ने कहा था कि अनुसूचित जाति वर्ग का उपवर्गीकरण नहीं हो सकता। मुख्य मामला अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 4(5) की वैधता से जुड़ा था, जिसमें एससी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए आरक्षित कर दी गई थीं। वर्ष 2010 में पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने ईवी चिनैया के निर्णय को स्वीकार करते हुए उस प्रविधान को निरस्त कर दिया। ईवी चिनैया मामले में न्यायाधीशों ने यह माना था कि संविधान के अनुच्छेद 341(1) के अनुसार, राष्ट्रपति के आदेश से निर्धारित सभी जातियां एक समान समूह का हिस्सा हैं और इन्हें आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 341(1) के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विशिष्ट समूहों को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित कर सकते हैं। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी। चिनैया मामले का फैसला पांच जजों का होने के कारण यह मामला सात जजों की पीठ को भेजा गया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह निकलता है कि एससी-एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में उसी वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए वर्गों को लाभ देने के लिए उपवर्गीकरण किया जा सकता है। यानी राज्य सरकारें एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े वर्गों की पहचान कर सकती हैं और उन्हें कोटा के अंदर विशेष कोटा प्रदान कर सकती हैं। उसने यह माना है कि राज्य सेवाओं में कुछ अनुसूचित जातियों का 'अपर्याप्त प्रतिनिधित्व' उनके भीतर 'पिछड़ापन' का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यानी एससी वर्ग की जो जातियां ज्यादा पिछड़ी रह गई हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, उनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हें उपवर्गीकरण के जरिये उसी कोटे में प्राथमिकता दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने और पिछड़ेपन का संकेत देने वाले आंकड़े एकत्र करने होंगे। फैसले का दूसरा पहलू क्रीमी लेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में एससी-एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान कर उसे आरक्षण के लाभ से बाहर करने की बात कही है। अभी क्रीमी लेयर का सिद्धांत सिर्फ ओबीसी आरक्षण में ही लागू है, लेकिन इस फैसले में एससी-एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर की पहचान कर उसे बाहर करने की बात कही गई है।

सात जजों की पीठ के समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा यही था कि क्या अनुसूचित जाति वर्ग का उपवर्गीकरण किया जा सकता है? क्या अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की कमी को प्रमाणित करना आवश्यक है? अब राज्य पिछड़ेपन को सिद्ध करते हुए एससी-एसटी वर्ग का उपवर्गीकरण कर सकते हैं। उपवर्गीकरण की यह अवधारणा अनुसूचित जातियों के भीतर मौजूद पदानुक्रम पर आधारित है, जहां कुछ जातियां अन्य की तुलना में अधिक पिछड़ी हुई हैं। उपवर्गीकरण करते समय राज्य किसी भी उपवर्ग के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण नहीं निर्धारित कर सकते। इसके अलावा राज्य को उपवर्गीकरण को उचित ठहराने के लिए उपवर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में अनुभवजन्य आंकड़ों का आधार लेना होगा। यानी एससी-एसटी वर्ग के भीतर पिछड़ापन के अंतर को दर्शाने के लिए डाटा इकट्ठा करना होगा। देखा जा रहा है कि एससी/एसटी वर्गों में से कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा पा रहे हैं। जमीनी सच्चाइयों को नकारा नहीं जा सकता और एससी/एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां मौजूद हैं जिन्होंने सदियों से अत्यधिक उत्पीड़न सहा है। ऐसे में राज्य को एससी/एसटी वर्गों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें सकारात्मक कार्रवाई से अलग करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। यही सच्ची समानता प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। इस संबंध में न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने सुझाव दिया कि आरक्षण को केवल एक पीढ़ी तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। यदि पहली पीढ़ी ने आरक्षण के जरिए उच्च पद हासिल कर लिया है, तो अगली पीढ़ी को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए।

वास्तव में एससी-एसटी के संदर्भ में जाति 'एकमात्र महत्वपूर्ण मानदंड' है, क्योंकि इन समुदायों की पहचान जाति के आधार पर होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के सबसे वंचित वर्गों में से हैं, उन्हें नौकरी मिल सकती है, परंतु उनकी सामाजिक मान्यता उनकी सामाजिक स्वीकृति पर निर्भर करती है, इसलिए जाति उनकी सामाजिक स्वीकृति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बनी रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी/एसटी की सामाजिक स्थिति की भी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सार्वजनिक रोजगार में एससी/एसटी के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के महत्व को स्पष्ट किया है। हाल के फैसले में क्रीमी लेयर का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर पर स्पष्ट चर्चा ने भविष्य की मुकदमेबाजी के लिए एक नया द्वार खोल दिया है, क्योंकि जब तक सरकारें एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक डाटा प्रस्तुत नहीं करतीं, तब तक इसमें क्रीमी लेयर उचित नहीं माना जा सकता।

आरक्षण को तर्कसंगत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया रास्ता। फाइल

पूरा होता आरक्षण का मूल उद्देश्य

कीर्तिदेव कारपेंटर

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण को संवैधानिक ठहराया है और राज्यों को इनमें उपवर्गीकरण करने का अधिकार प्रदान किया है। चूंकि आरक्षण के भीतर आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इस निर्णय के गहरे अर्थ को समझना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में उल्लिखित जातियों और जनजातियों की सूची में संशोधन का अधिकार केवल संसद के पास है। हालांकि इस निर्णय के बाद राज्य भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं कि कुछ जातियों को अधिक आरक्षण मिले, जबकि अन्य को कम। यह वर्गीकरण केवल उचित और तर्कसंगत आंकड़ों के आधार पर ही हो सकता है। यानी राज्य किसी जाति को राजनीतिक लाभ के लिए अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दे सकते और न ही किसी जाति को आरक्षण के लाभ से वंचित कर सकते हैं। एक अनुसूचित जाति या जनजाति के आइएएस अधिकारी के बेटे और एक गरीब अनुसूचित जाति या जनजाति के मजदूर के बेटे को समान लाभ कैसे दिया जा सकता है। एक सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न परिस्थितियों में पला-बढ़ा है और दूसरा सामाजिक विषमताओं का सीधा सामना कर रहा है।

जाहिर है बिना उपवर्गीकरण के सामाजिक समानता और सामाजिक लोकतंत्र को प्राप्त करना संभव नहीं होगा, जो कि आरक्षण के पीछे का मूल उद्देश्य था। यह इसलिए, क्योंकि वे जातियां जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत हो चुकी हैं और जिन्होंने पहले ही आरक्षण का लाभ उठा लिया है, अब उन्हें आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाना चाहिए। उपवर्गीकरण के बिना वे आरक्षण के लाभार्थी के रूप में बनी रहेंगी और अत्यंत पिछड़ी जातियों तक लाभ पहुंचाना कठिन हो जाएगा। यह सामाजीकरण के सामान्य सिद्धांत से भी समझा जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि अंततः सामाजिक समृद्धि की ओर ले जाती है, लेकिन यह सभी के लिए समानुपातिक रूप से नहीं होता। समय के साथ कई अनुसूचित जातियां और जनजातियां आरक्षण का लाभ उठाकर समृद्ध हो चुकी हैं और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इसका मतलब है कि सभी अनुसूचित जातियां या जनजातियां एक साथ समान अनुपात में समृद्धि प्राप्त नहीं करेंगी, बल्कि उनमें स्वतः असमानता हो गई है, जिसे आरक्षण के लाभों में वर्गीकरण के माध्यम से संतुलित करना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट के बहुमत से आया फैसला उपवर्गीकरण की आवश्यकता को सिद्धांत रूप में स्वीकारते हुए राज्यों को इसके लिए शक्तियां प्रदान करता है, परंतु यह उपवर्गीकरण जटिलताओं और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की चुनौतियों से भरा है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची विस्तृत है और क्षेत्रवार जातियों के पिछड़ेपन में अंतर है। इन जातियों के भीतर ऐसे समूह हैं जिनका सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन भिन्न-भिन्न है और सरकारें राजनीतिक निष्ठा और लाभ के लिए भ्रामक आंकड़ों के आधार पर सतही वर्गीकरण कर सकती हैं। इसलिए सामाजिक लोकतंत्र और वास्तविक समानता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें और सभी हितधारकों को समन्वय से काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इन चुनौतियों से अवगत है, इसलिए उपवर्गीकरण के आधार की न्यायिक समीक्षा का मार्ग खुला रखा है। यदि राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए बिना तर्कसंगत आंकड़ों के उपवर्गीकरण करती हैं, तो न्यायालय उनसे आंकड़ों और उपवर्गीकरण की तर्कसंगतता सिद्ध करने को कह सकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खरी-खरी

गड्ढों के साथ जीवन का सफर

धर्मेंद्र जोशी

बारिश में मेरे शहर की सड़कें बहुत ही सुहावनी प्रतीत हो रही हैं। बड़े-बड़े गड्ढे शहरवासियों को झील का आभास करा रहे हैं, जिसमें दोपहिया वाहन के चालक गिरते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चे मुफ्त में स्विमिंग पुल का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ कार चालकों तो गड्ढे भी एक्सप्रेसवे की तरह नजर आ रहे हैं।

शहर की सड़कों को ऐसा बनाने में नगर निगम का भी बहुत योगदान है। साल भर कुंभकर्णी नींद में सोने वाले निगम का अमला यकायक जागता है और आनन-फानन में बारिश के पहले अच्छी-भली सड़कों को मरम्मत के नाम पर गहराई तक खोद देता है। नाम मात्र की सीमेंट और खूब मिट्टी मिलाकर रात के अंधेरे में सड़क का कायाकल्प कर देता है, जो सुबह होते ही जगह-जगह उखड़ जाती है। यह दृश्य ऊपर से नीचे तक मिल-बांटकर खाने की कहानी को बयां करता है।

नगर निगम की आश्चर्यजनक तत्परता को देख जल विभाग भी मुस्तैदी दिखाने लगता है और वर्षों से लंबित कामों को निपटाने के लिए कमर कस लेता है। जो सड़क अभी-अभी बनी होती है, उसे दोबारा खोदाई करके नल की पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर देता है। यह एक बार प्रारंभ होता है और पूरे साल मंथर गति से चलता रहता है। उसके द्वारा खोदे गए गड्ढे वर्ष भर दुर्घटना को आमंत्रण देते हैं और हड्डी रोग चिकित्सकों की आमदनी बढ़ाने का बड़ा जरिया बन जाते हैं।

जब सड़कों पर गड्ढे की अधिकता खबर बन जाती है तो उनमें मिट्टी डालने का कार्य किया जाता है, जो या तो अधिक बारिश में बह जाती है और थोड़ी बहुत अगर रह जाती है, तो राजनीतिक दल एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने में उपयोग करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग मौन साध लेते हैं और प्रतिपक्ष के लोग मुखर हो मुद्दे को उठाते हैं। यह मुद्दा तब तक गर्म रहता है, जब तक कि वे सत्ता हासिल न कर लें। सत्ता पाते ही वे भी गड्ढों पर मिट्टी डालकर भूल जाते हैं। और शहर की जनता का गड्ढों के साथ सुहाना सफर जारी रहता है।

X पोस्ट

बांग्लादेश को लेकर भारत को अब क्या करना चाहिए? इसका जवाब है कि फिलहाल कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां नया घटनाक्रम अभी आकार ही ले रहा है। इसका भारत से कोई वास्ता भी नहीं और यह बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति का मसला है। उन्हें ही इससे निपटने दें।
हैप्पीमैन जैकब@HappymonJacob

यह समय बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सलामती के लिए प्रार्थना करने का है। हमें सीएए जैसा कानूनी आवरण चाहिए ही। इसके साथ ही हमें अपने यहां अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को उनके देश भेजने के उपाय भी करने चाहिए।
ईशकरण सिंह भंडारी@ishkarnBHANDARI

शेख हसीना भारत की दोस्त हैं। उनके रहते भारतीय हित सुरक्षित थे। उनके जाने से पाकिस्तान और चीन खुश होंगे। उनके पिता मुजीब की मूर्ति को जिस तरह तोड़ा गया, उससे साफ है कि जिस विचारधारा ने उनकी हत्या की थी, वही इस अराजकता में शामिल दिख रही है। यह छात्रों का आंदोलन तो कतई नहीं रहा।
अभिसार शर्मा@abhisar_sharma

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या आपको भरोसा है कि ओलिंपिक हाकी में गोल्ड मेडल का इंतजार खत्म होने वाला है?

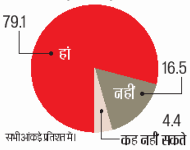

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या बांग्लादेश का घटनाक्रम भारत की चिंता बढ़ाने वाला है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

शेख हसीना मैम को मिला वतन निर्वास,
लंबी सत्ता बन गई आज गले की फांस।
आज गले की फांस लोग सड़कों पर आएं,
तो शासक गण भाग स्वयं की जान बचाएं।
उग्र हुए जब छात्र छूटने लगा पसीना,
तब अपना ही देश छोड़कर भगीं हसीना!
- ओमप्रकाश तिवारी

बंगाल डायरी

बदलती डेमोग्राफी पर अपने-अपने तर्क

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करीब दो माह पूर्व भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल के दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप इलाके में हुई एक जनसभा में कहा था कि 'बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ की वजह से जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) बदल रही है। घुसपैठिये स्थानीय युवाओं के लिए उपलब्ध अवसर छीन रहे हैं।' भाजपा ने डेमोग्राफी बदलाव का मुद्दा अब भी जिंदा रखा है और इसे संसद से लेकर सड़क तक उठा रही है। मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में डेमोग्राफी बदलने को लेकर झारखंड के एक भाजपा सांसद ने तो यहां तक मांग कर दी कि इन दोनों जिलों और बिहार के तीन जिलों को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री एवं बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की बातों का समर्थन करते हुए कहा था कि 'बंगाल में भी घुसपैठ कराकर डेमोग्राफी बदली गई है। इसकी साजिश देश के बाहर कहीं से हो रही है। अगर हम बंगाल की बात करें तो यहां आजादी के पहले और बाद में भी तीन जिले मुस्लिम बहुल थे, अब नौ जिले हो गए हैं। यह कहां से हो रहा है? कैसे हो रहा है? इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? जैविक तरीके से इस तरह जनसंख्या नहीं बढ़ सकती।'

इन सब बयानों के बीच पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि मालदा और मुर्शिदाबाद में डेमोग्राफी बदलने की वजह घुसपैठ नहीं, बल्कि मुस्लिम परिवारों में ऊंची जन्म दर है। मुर्शिदाबाद के भरतपुर क्षेत्र के विधायक कबीर ने कहा कि 'मुस्लिम परिवारों में किसी के चार, किसी के पांच और किसी के छह बच्चे होते हैं। 90 प्रतिशत मामलों में घर पर ही मुस्लिम महिलाएं बच्चे को जन्म दे रही हैं।' तृणमूल नेता हुमायूं कबीर के इस बयान से एक तरह से प्रमाणित होता है कि भाजपा नेताओं की ओर से बंगाल में डेमोग्राफी बदलने के जो दावे किए आ रहे हैं, उसे उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता अपने ही पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर के बयान को महत्व नहीं दे रहे हैं। तृणमूल के प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने कहा कि 'केंद्र सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में संस्थागत प्रसव दर 75 से बढ़कर 95 प्रतिशत से अधिक हो गई है। नतीजतन हुमायूं कबीर ने जो कहा, उसका वास्तविक तथ्यों से कोई मेल नहीं है।' बंगाल में डेमोग्राफी में बदलाव होने को लेकर भाजपा और तृणमूल नेताओं के अपने-अपने तर्क हो सकते हैं, पर इस सच्चाई को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि मुर्शिदाबादा, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 60 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है, जो बदलती जनसांख्यिकी का प्रमाण है।

बंगाल में तेजी से बढ़ रही मुस्लिमों की आबादी पर सवाल। प्रतीकात्मक

बंगाल और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम होने एवं डेमोग्राफी बदलाव को लेकर शोध करने वाले सेंटर फार रिसर्च इन इंडो-बांग्लादेश रिलेशंस के निदेशक बिमल प्रमाणिक ने गत दिनों दैनिक जागरण से कहा कि 'हमलोग 1991 से डेमोग्राफी बदलाव पर ब्लाक स्तर से शोध करते आ रहे हैं। बंगाल के कई जिलों में डेमोग्राफी बदल चुकी है और कई जिलों में तेजी से बदल रही है। मुर्शिदाबाद में 2011 की जनगणना में ही मुस्लिम आबादी 66 प्रतिशत पार कर गई थी और इस समय देखें तो यह 70 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। इसी तरह से मालदा में भी 60 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। उत्तर दिनाजपुर में भी मुस्लिम आबादी 60 प्रतिशत को पार कर गई है। डेमोग्राफी बदलाव के दो प्रमुख कारण हैं, पहला घुसपैठ तो दूसरा मुस्लिम जनसंख्या में जैविक वृद्धि। सिर्फ इन जिलों में ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना, नदिया के अलावा बीरभूम, हावड़ा और यहां तक कि कोलकाता में भी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। कोलकाता के राजाबाजार, मटियाबुर्ज, खिदिरपुर, गार्डेन रीच, मछुआ, बड़ाबाजार और यहां तक कि भवानीपुर एवं बालीगंज में भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है।'

कोलकाता के मटियाबुर्ज इलाके में मुस्लिम आबादी का अंदाजा तृणमूल कांग्रेस एक वरिष्ठ नेता एवं मंत्री फिरहाद हकीम के वर्ष 2016 में दिए उस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने गार्डेन रीच की तुलना 'मिनी पाकिस्तान' से कर दी थी, हालांकि बाद में विवाद होने पर उन्होंने अपने बयान से पल्ला झाड़ लिया था। बिमल प्रमाणिक ने कहा कि 'बंगाल में वर्ष 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 27 प्रतिशत थी। अब तो यह 30 प्रतिशत को पार कर चुकी है। राज्य के साथ कोलकाता में भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है और यहां भी 30 प्रतिशत के करीब पहुंच चुकी है। इसी तरह से और भी जिले हैं, जहां मुस्लिम आबादी कहीं 38 तो कहीं 40 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है।'

मंथन

रुचिकर बने विद्यालयी शिक्षा

शिक्षा इस तरह से दी जानी चाहिए कि उसके लिए किया गया परिश्रम बच्चों को परिश्रम नहीं, खेल लगे। बस्ता मुक्त दिवस की पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है

पीयूष कुमार दुबे
सहायक प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभाव में आने के बाद से प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक, हमारी शिक्षा प्रणाली में निरंतर नवाचार देखने को मिल रहे हैं। इस कड़ी में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूली बच्चों को वर्ष में दस दिन बिना बस्ते के विद्यालय आने की व्यवस्था की है। इससे संबंधित जारी दिशानिर्देश में कहा गया है कि कक्षा छह से आठ के बच्चों के लिए वर्ष में ऐसे दस दिन निर्धारित हों, जब वे बिना बस्ते के विद्यालय आ सकें। ये दस दिन विद्यालय वर्ष में पांच-पांच दिन के दो चरणों में रख सकते हैं। इस निर्णय के बाद अब विद्यालयों को अपने वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रमों में इन दस बस्ता मुक्त दिनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। बिना बस्ते वाले ये दिन, निष्क्रियता के दिन नहीं होंगे। शिक्षण-प्रशिक्षण की प्रक्रिया इस दौरान भी चलती रहेगी। अंतर बस इतना होगा कि इस अवधि में शिक्षण का स्वरूप कक्षा-आधारित पुस्तकीय ज्ञान से हटकर अनुभव आधारित ज्ञान पर केंद्रित रहेगा। विद्यालय में पढ़ाई को अधिक आनंदमय, अनुभवात्मक और तनावमुक्त बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा कुछ गतिविधियां भी निर्देशित की गई हैं, जिन्हें इस अवधि में विद्यालय कर सकते हैं। संदेह नहीं कि यदि धरातल पर विद्यालयों द्वारा शिक्षा मंत्रालय की इस घोषणा का ठीक से क्रियान्वयन किया जाता है, तो यह न केवल बस्ते के बोझ से दब रहे हमारे नौनिहालों के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा, बल्कि उनके व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होगा।

दरअसल भारतीय समाज में प्रायः आरंभ से ही बच्चों के मन में शिक्षा को एक ऐसे कार्य के रूप में स्थापित कर दिया जाता है, जिसमें परिश्रम के अतिरिक्त और किसी चीज के लिए कोई स्थान ही नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि परिश्रम के अतिरिक्त दबाव के कारण बच्चों के मन में प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा के प्रति अरुचि का भाव उत्पन्न हो जाता है। यह ठीक है कि शिक्षा के लिए परिश्रम आवश्यक है, किंतु यह इतना भी नहीं होना चाहिए कि आरंभिक स्तर से ही बच्चों को भार लगने लगे। परिश्रम का स्वरूप एकरस होने के बजाय यदि विविधतापूर्ण हो तो बच्चों के लिए शैक्षिक कार्य रुचिकर हो सकेंगे। 'बैगलेस डे' इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है।

बस्ते से मुक्त इन दस दिनों में बच्चों को सैन्य एवं पुलिस कार्यालयों का भ्रमण कराने, स्थानीय उद्योगों को दिखाने-समझाने, कौशल विकास से संबंधित गतिविधियों से जोड़ने, कोई ऐतिहासिक स्थल एवं वन्यजीव अभयारण्य घुमाने जैसी 33 गतिविधियों में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। बच्चों का मन कौतूहल और रोमांच प्रिय होता है, अतः नई चीजों को जानने और उनका हिस्सा बनने के प्रति वे सदैव उत्सुक रहते हैं। बस शर्त यह है कि वह नई चीज उन्हें रोचक ढंग से बताई जाए। इन गतिविधियों का स्वरूप पर्यटन-केंद्रित है, अतः इनमें बच्चों का मन रमना स्वाभाविक है। पुलिस कार्यालयों का भ्रमण कराते हुए उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली और सेवा-भावना से परिचित कराया जा सकता है। स्थानीय उद्योगों को दिखाते हुए भारत के कुटीर उद्योगों के महत्व एवं परंपरा का ज्ञान बच्चों तक संप्रेषित करना सहज ही संभव है। इतिहास बच्चों के लिए अक्सर एक उबाऊ विषय होता है, जिसकी तारीखों के जाल में उलझकर वे इसका वास्तविक रस अनुभव नहीं कर पाते। ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण से इतिहास को देखने की सुलझी हुई दृष्टि बच्चों में विकसित की जा सकती है। उन्हें समझाया जा सकता है कि इतिहास केवल तारीखों की तरतीब नहीं होता, अपितु उसमें संस्कृति के सूत्र भी छिपे होते हैं। कौशल विकास से संबंधित गतिविधियों को दिखाते हुए बच्चों में आरंभ से ही नए-नए हुनर सीखने के प्रति जिज्ञासा और प्रेरणा जगाई जा सकती है। इसके अलावा अपने आसपास सर्वेक्षण कर लोगों की रुचियों को सामने लाना, किसी बुजुर्ग या अपने अभिभावकों का साक्षात्कार करना आदि गतिविधियों का सुझाव भी मंत्रालय ने दिया है। यह गतिविधियां बच्चों की रचनात्मक क्षमता में वृद्धि करने में सहायक होंगी। स्पष्ट है कि ये सभी गतिविधियां बच्चों के लिए नई चीजें जानने-सीखने और समझने का अवसर भी निर्मित करेंगी।

वस्तुतः शिक्षा को सहज, आनंद से युक्त और रुचिकर होना चाहिए तथा वह इस तरह से दी जानी चाहिए कि उसके लिए किया गया परिश्रम बच्चों को परिश्रम नहीं, खेल लगे। विद्यालयी शिक्षा पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। बस्ता मुक्त दिवस का यह कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, बशर्ते कि विद्यालय इसके क्रियान्वयन के प्रति गंभीरता और समर्पण दिखाएं।

बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास में सहायक बने शिक्षा। फाइल

****

अदाणी एनर्जी साल्यूशंस ने 8,373 करोड़ जुटाए

नई दिल्ली : अदाणी समूह की कंपनी अदाणी एनर्जी साल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआइपी) के जरिये 8,373.10 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है। इस राशि का इस्तेमाल नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने में किया जाएगा। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड से अलग होने के बाद एईएसएल ने पहली बार इक्विटी के जरिये पैसा जुटाया है। (प्रेट्र)

हम नई शिपबिल्डिंग योजना पर काम कर रहे हैं। इस नई योजना में शामिल विभिन्न उपायों से भारतीय शिपयार्ड्स को 2035 तक प्रोत्साहन मिलेगा।

— टीके रामचंद्रन, सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

सेंसेक्स	78,759.40	▼ 2,222.55
निफ्टी	24,055.60	▼ 662.10
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 72,800	▲ ₹250
चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 84,200	▼ ₹1,300
डालर	₹ 84.09	▲ ₹0.37
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 75.33	

एक नजर में

7-7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी

नई दिल्ली : वित्तीय सेवाएं देने वाली फर्म डेलाइट इंडिया ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय आर्थिकी की वृद्धि दर 7-7.2 प्रतिशत रह सकती है। मजबूत आर्थिक बुनियाद और घरेलू नीतिगत सुधारों में निरंतरता का भारतीय आर्थिकी को लाभ मिलेगा। डेलाइट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि भारत दूसरी छमाही में मजबूत वृद्धि दर्ज करेगा। (प्रेट्र)

भारती एयरटेल का शुद्ध लाभ ढाई गुना बढ़ा

नई दिल्ली: चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल का शुद्ध लाभ ढाई गुना से ज्यादा बढ़कर 4,160 करोड़ रुपये रहा है। अप्रैल-जून 2023 में कंपनी को 1,612.5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। बीती तिमाही में कंपनी की कुल आय 2.8 प्रतिशत बढ़कर 38,506.4 करोड़ रुपये रही है। इस दौरान कंपनी का खर्च 23.44 प्रतिशत घटकर 8,007 करोड़ रुपये रहा है। (प्रेट्र)

उद्यम पोर्टल पर 4.77 करोड़ एमएसएमई का पंजीकरण

नई दिल्ली : सरकार की ओर से संचालित उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई के पंजीकरण में लगातार वृद्धि हो रही है। मंत्रालय के अनुसार, 31 जुलाई 2024 तक इस पोर्टल पर पंजीकृत पोर्टल पर एमएसएमई की संख्या 4.77 करोड़ हो गई है। बीते वित्त वर्ष 2023-24 में इस पोर्टल 2.49 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हुए थे। मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 63.41 लाख एमएसएमई का पंजीकरण हो चुका है। (एएनआइ)

सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में किया बदलाव

नई दिल्ली : कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को सिक्योरिटीज में फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग की पहचान करने व रोकने के लिए म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव किया है। इसके अलावा एएमसी को इस संबंध में एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है। साथ ही, एएमसी को व्हिसल-ब्लोअर तंत्र स्थापित का निर्देश दिया है। (प्रेट्र)

दो दिन में 19.76 लाख करोड़ रुपये घटी निवेशकों की संपत्ति

बीएसई का पूंजीकरण इस गिरावट के बाद 441.86 लाख करोड़ रुपये पर आया, कच्चा तेल आठ महीने के निचले स्तर पर

जेएनएन, नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजारों में बीते दो कारोबारी सत्रों से गिरावट का माहौल जारी है। दो दिनों की इस गिरावट से निवेशकों की संपत्ति में 19.76 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है। एक अगस्त को बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 461.62 लाख करोड़ रुपये था। दो अगस्त को सेंसेक्स में 885 अंकों की गिरावट रही थी। इससे बीएसई के पूंजीकरण में 4.4 लाख करोड़ रुपये की कमी आई थी। अब सोमवार को सेंसेक्स में 2,222 अंकों की गिरावट से बीएसई का पूंजीकरण एक ही दिन में 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा घटा है। अब बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटकर 441.86 लाख करोड़ रुपये या 5.27 ट्रिलियन डालर रह गया है। बीते दो कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स में तीन हजार अंक से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है।

सोमवार के कारोबार में बीएसई में 3,414 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं, 664 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। 111 शेयरों के मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ। बाजार के धराशायी होने के दो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण अमेरिका में नौकरी संबंधित रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में जुलाई की बेरोजगारी दर 4.3 प्रतिशत के साथ तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका में बेरोजगारी दर के बढ़ने से वहां मंदी की आशंका जाहिर की जाने लगी। इसे संभालने के लिए अमेरिकी फेडरल बैंक की तरफ से सितंबर में ब्याज दर में कटौती की प्रबल संभावना है। यूरोप व चीन में पहले से ही सुस्ती चल रही है। कच्चे तेल की कीमत पहले से आठ माह के न्यूनतम स्तर 75.8 डालर प्रति बैरल पर आ गया है। इन सबको देखते हुए वैश्विक स्तर पर मंदी की आहट देख दुनिया भर के बाजार में सोमवार को जबरदस्त बिकवाली की गई, जिससे भारतीय बाजार भी प्रभावित हुए।

दूसरा कारण पिछले सप्ताह जापान के सेंट्रल बैंक की ओर से ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना है। पिछले 15 साल से भी अधिक समय से जापान में ब्याज दर 0.0-0.1 प्रतिशत थी। लगभग शून्य ब्याज दर होने से वैश्विक निवेशक जापानी बैंक से पैसा उठाकर दुनिया के अन्य देशों में निवेश कर रहे थे। अब जापान सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज बढ़ाने से निवेशकों की लागत बढ़ेगी, जिससे बिकवाली को समर्थन मिला। दूसरी तरफ, जापानी सरकार के हस्तक्षेप से डालर के मुकाबले येन में मजबूती भी आ गई। पीएल कैपिटल के मार्केट एडवाइजरी हेड विक्रम कसाट के मुताबिक, इन दो कारणों के अलावा बाजार पर इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की आशंका का भी असर पड़ा है।

लंबे समय तक नहीं रहेगी गिरावट

विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि भारतीय बाजार अब विदेशी निवेशकों पर ज्यादा निर्भर नहीं है। आनंद राठी शेयर्स की बिजनेस हेड तन्वी कंचन के मुताबिक, भारतीय बाजार में शार्ट टर्म मुनाफे की बिकवाली से बाजार में जो घबराहट है, वह लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। पीएचडी चैंबर के कैपिटल मार्केट कमेटी के चेयरमैन बीके सभरवाल कहते हैं कि पहले एक डालर के बदले 162 येन मिल रहे थे, जो अब 145 येन हो गए हैं। मतलब सीधे-सीधे 13 प्रतिशत का नुकसान हो गया। इन वजहों से जापानी बैंक से जुड़े निवेशकों ने घाटे से बचने व उसे कम रखने के लिए जमकर बिकवाली की। सभरवाल ने बताया कि दो-तीन दिनों में बाजार सामान्य होने लगेगा, लेकिन मिड कैप व स्माल कैप को संभलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। चुनाव परिणाम वाले दिन भी बाजार में ऐसी ही गिरावट हुई थी।

3,414 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए बीएसई में

664 शेयर बढ़त के साथ बंद होने में सफल

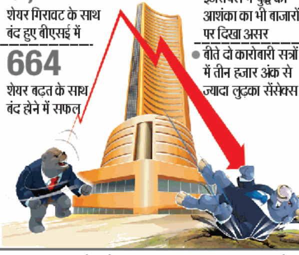

- विशेषज्ञ बोले- ईरान-इजरायल में युद्ध की आशंका का भी बाजारों पर दिखा असर
- बीते दो कारोबारी सत्रों में तीन हजार अंक से ज्यादा लुढ़का सेंसेक्स

अन्य एशियाई बाजारों का हाल

देश	सूचकांक	गिरावट (%में)
हांगकांग	हैंगशेंग	1.48
सिंगापुर	स्ट्रेट्स टाइम्स	4.25
द. कोरिया	कोस्पी	9.61
इंडोनेशिया	जकार्ता कंपोजिट	3.40
चीन	शंघाई कंपोजिट	1.54
थाईलैंड	सेट कंपोजिट	3.01

प्रमुख सूचकांकों में गिरावट (%में)

सेवा	4.56
यूटीलिटीज	4.30
रियल्टी	4.13
औद्योगिकी	4.08
बिजली	3.91
तेल व गैस	3.88
कमोडिटीज	3.82

चांदी में 1,300 रुपये की गिरावट : सिक्का निर्माताओं और औद्योगिक मांग में कमी के चलते चांदी की कीमतों में सोमवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज गई। आल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली में चांदी अब 1,300 रुपये टूटकर 84,200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। हालांकि, ज्वेलर्स की ओर से मांग आने के चलते सोने का मूल्य 250 रुपये बढ़कर 72,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

एलआइसी ने जून तिमाही के दौरान 17 हजार करोड़ रुपये के शेयर खरीदे

मुंबई, आइएएनएस: सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एलआइसी ने अप्रैल-जून 2024 तिमाही के दौरान शेयरों में 17 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। एलआइसी भारतीय शेयर बाजारों में बड़े संस्थागत निवेशकों में से एक है। एलआइसी ने इससे पहले जनवरी-मार्च 2024 के दौरान 44,500 करोड़ रुपये के शेयरों की खरीदारी की थी। डाटा के अनुसार, बीती तिमाही में एलआइसी ने 11 नई कंपनियों को अपने निवेश पोर्टफोलियो में शामिल किया है। साथ ही 89 मौजूदा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जून तिमाही के अंत में एलआइसी के पोर्टफोलियो में 321 कंपनियों के शेयर शामिल थे, जिनका संयुक्त मूल्य 15.71 लाख करोड़ रुपये था। अप्रैल-जून के दौरान म्यूचुअल फंड्स ने 1.1 लाख करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं।

चालू वित्त वर्ष में पांच प्रतिशत के करीब रहेगी महंगाई दर

नई दिल्ली, एएनआइ: चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सितंबर और अक्टूबर को छोड़कर खुदरा महंगाई पांच प्रतिशत के करीब या इससे नीचे बनी रहेगी। एसबीआइ ने एक रिसर्च रिपोर्ट में यह बात कही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महंगाई का परिदृश्य आरबीआइ के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष जून में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.08 प्रतिशत हो गई है, जो मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों की उच्च कीमतों के कारण है। रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य कीमतों को तय करने में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्यादा वर्षा से फसल का नुकसान हो सकता है, जिससे खाद्य महंगाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। महंगाई की अपेक्षाओं को प्रबंधित करने में आरबीआइ की क्षमता महत्वपूर्ण है।

इंडिगो की चुनिंदा उड़ानों में 14 नवंबर से बिजनेस क्लास सेवा

नई दिल्ली, प्रेट्र: किफायती विमान सेवाएं देने वाली विमानन कंपनी इंडिगो 14 नवंबर से 12 घरेलू मार्गों पर चुनिंदा उड़ानों में बिजनेस क्लास सेवा की शुरुआत करेगी। इसके अलावा कंपनी कारोबारी विस्तार के लिए ग्राहक लायल्टी कार्यक्रम भी शुरू करेगी।

12 घरेलू मार्गों से नई सेवा की शुरुआत करेगी कंपनी

18 हजार रुपये से शुरू होगा बिजनेस क्लास का किराया

कंपनी के 18 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने सोमवार को कहा कि बिजनेस क्लास की सीटों के लिए छह अगस्त से बुकिंग शुरू हो जाएगी। बिजनेस क्लास के यात्रियों को विशेष भोजन की पेशकश की जाएगी। ए321 नियो विमानों में बिजनेस क्लास की 12 सीटें होंगी। एल्बर्स ने कहा कि बिजनेस क्लास सीट के लिए एकतरफ का किराया 18,018 रुपये से शुरू होगा। यह सीटें सबसे व्यस्त और बिजनेस रूट पर उपलब्ध होंगी और इसकी शुरुआत दिल्ली-मुंबई उड़ानों से होगी। अभी टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा बिजनेस क्लास सीटें प्रदान करती हैं। इंडिगो चालू वित्त वर्ष में सात और अंतरराष्ट्रीय स्थानों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। कार्यक्रम में इंडिगो के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने कहा कि वह और इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज यहीं बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि हालिया हिस्सेदारी बिक्री का उद्देश्य व्यवसाय और सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए धन जुटाना था।

फार्च्यून ग्लोबल 500 में 86वें स्थान पर रही रिलायंस इंडस्ट्रीज

नई दिल्ली, प्रेट्र: तेल से लेकर दूरसंचार और खुदरा कारोबार करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फार्च्यून ग्लोबल 500 सूची में दो स्थानों की छलांग लगाई है और कंपनी इस वर्ष 86वें स्थान पर रही है। 2021 में कंपनी इस सूची में 155वें स्थान पर थी। बीते तीन वर्षों में इसकी रैंकिंग में 69 स्थान का उछाल आया है। अमेरिका की वालमार्ट लगातार 11वें वर्ष सूची में पहले स्थान पर रही है।

एलआइसी 12 स्थान की छलांग लगाकर इस सूची में 95वें नंबर पर रही है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन आयल कारपोरेशन (आइओसी) 22 पायदान नीचे गिरकर 116वें स्थान पर आ गई। एसबीआइ की रैंकिंग में 57 स्थान का उछाल आया है और अब यह 178वें नंबर पर पहुंच गया है। सूची में ओएनजीसी 180वें और भारत पेट्रोलियम 258वें स्थान पर रही हैं।

जुलाई में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में 10 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली, प्रेट्र: नई लांचिंग और ज्यादा छूट के चलते जुलाई में यात्री वाहनों की खुदरा में 10 प्रतिशत की वृद्धि रही है। फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के डाटा के अनुसार, पिछले महीने यात्री वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 3,20,129 इकाई रही है जो पिछले वर्ष समान अवधि में 2,90,564 इकाई रही थी।

3,20,129 यात्री वाहनों की बिक्री हुई पिछले महीने

14,43,463 दोपहिया की बिक्री हुई जुलाई 2024 के दौरान

फाडा के वाइस प्रेसिडेंट सीएस विग्नेश्वर का कहना है कि डीलरों ने उन्हें उत्पादों की अच्छी उपलब्धता, आकर्षक योजनाओं और उत्पादों की व्यापक रेंज से लाभ मिलने की बात कही है। विग्नेश्वर ने कहा कि भारी बारिश, उपभोक्ता भावना में कमी और तीव्र प्रतिस्पर्धा ने चुनौतियां पेश कीं, लेकिन डीलरों ने मजबूत प्रचार और वृद्धिशील छूट के माध्यम से बिक्री को बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है।

पिछले महीने दोपहिया की खुदरा बिक्री 14,43,463 इकाई रही है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 12,31,930 इकाई थी। हालांकि, इस दौरान ट्रैक्टर की बिक्री वार्षिक आधार पर 12 प्रतिशत घटकर 79,970 इकाई रही है। फाडा के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि बिक्री में वृद्धि के साथ इन्वेंट्री (स्टाक) का स्तर भी 67-72 दिनों के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो 73,000 करोड़ रुपये के बराबर है।

सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में मामूली गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र: जुलाई में देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में इसी वर्ष जून के मुकाबले मामूली गिरावट रही है। एचएसबीसी इंडिया के अनुसार, जुलाई में भारत सेवा पीएमआइ कारोबारी गतिविधि सूचकांक 60.3 रहा है जो जून में 60.5 था। खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआइ) की भाषा में 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम अंक का आशय संकुचन से होता है।

एचएसबीसी इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी का कहना है कि जुलाई में सेवा क्षेत्र की गतिविधि थोड़ी धीमी गति से बढ़ी, नए कारोबार में और वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से घरेलू मांग से प्रेरित रही। सेवा कंपनियां आने वाले वर्ष के लिए आशावादी हैं। सितंबर 2014 में इस सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से नए निर्यात ठेकों में तीसरी सबसे तेज वृद्धि हुई है, जिसका कारण दुनियाभर से भारतीय सेवाओं की मांग बढ़ी है।

द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने फिजी पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मु

फिजी के नाबी हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का उपप्रधानमंत्री विलीम गावोका और भारतीय उच्चायुक्त पीएस कार्तिकेयन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत स्वागत किया। एएनआइ

सुवा, प्रेट्र : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तीन देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में सोमवार को फिजी पहुंचीं। इस यात्रा के दौरान वह फिजी के राष्ट्रपति विलियम मैवालिली काटोनीवरे और प्रधानमंत्री सीटिवेनी राबुका के साथ मुलाकात करेंगी। इस यात्रा का मकसद भारत-फिजी के ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु फिजी के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पांच-सात अगस्त तक वहां रहेंगी। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस द्वीपीय देश की पहली यात्रा है।

राष्ट्रपति मुर्मु का हवाईअड्डे पर फिजी के उपप्रधानमंत्री, विलीम गावोका, फिजी में भारतीय उच्चायुक्त, पीएस कार्तिकेयन और फिजी के अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति फिजी की संसद को भी संबोधित करेंगी।

फिजी यात्रा के बाद मुर्मु न्यूजीलैंड और तिमोर-लेस्ते की यात्रा करेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अनुसार, उनकी छह दिवसीय तीन देशों की यात्रा का उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाना है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने कहा-दंगाइयों से सख्ती से निपटेंगे

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने देश के कई शहरों में हुए दंगों में शामिल दंगाइयों से सख्ती से निपटने का संकल्प लिया है। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ आपातकालीन बैठक के बाद उन्होंने दंगों को रोकने के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों को तैनात करने का निर्णय लिया।

कैबिनेट आफिस ब्रीफिंग रूम ए (कोबरा) की आपातकालीन बैठक में गृह मंत्री यवेटे कूपर और स्काटलैंड यार्ड के प्रमुख मार्क रोली की भी मौजूदगी रही। हिंसा रोकने के लिए कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी।

लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बैठक के बाद स्टार्मर ने कहा, सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संदिग्धों से निपटने के लिए त्वरित न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कानून उन इंटरनेट मीडिया यूजर्स पर भी समान रूप से लागू होगा जो आनलाइन नफरत फैला रहे हैं।

- स्टार्मर की मंत्रियों के संग आपातकालीन बैठक
- दंगा रोकने को अधिकारियों को किया जाएगा तैनात

मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए टाउनहाल के बाद जुटे लोग। एपी

उन्होंने कहा, अव्यवस्था से निपटने के लिए हमें जहां भी जरूरत होगी, वहां अधिकारी उपलब्ध होंगे। विशेषज्ञ अधिकारियों को लोगों की सहायता के लिए तैनात किया जाएगा। गृह कार्यालय ने मस्जिदों पर हमलों के खतरे से निपटने के लिए अधिक सुरक्षा की पेशकश की है। जो लोग इस अव्यवस्था में शामिल हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पिछले छह दिनों में देश में अराजकता फैल गई है, क्योंकि दक्षिणपंथी समूह डांस क्लास में बच्चियों पर हुई चाकूबाजी की घटना का जिक्र कर लोगों को भड़काने के लिए इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हमले में तीन बच्चियों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इसे लेकर इंटरनेट पर अफवाह फैलाई जा रही है कि आरोपित रवांडा का था और यहां शरण चाहता था।

यूक्रेन को अमेरिका से मिला 3.9 अरब डालर का और अनुदान

कीव, रायटर: रूस से जंग में यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे निपटने के लिए अमेरिका यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है। जरूरी सेवाओं को संचालित करने में मदद के लिए यूक्रेन को अमेरिका से विश्व बैंक के जरिये 3.9 अरब डालर का और अनुदान मिला है। यूक्रेन के पीएम डेनीज शमयाल ने सोमवार को कहा, अमेरिका की ओर से 2024 में यह सीधे बजट समर्थन की पहली किस्त है। इस वर्ष यूक्रेन को अमेरिका से कुल 7.8 अरब डालर की बजट सहायता मिलनी है।

यूक्रेन के वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, फंड का इस्तेमाल शिक्षकों, राज्य कर्मचारी सेवा व अन्य सार्वजनिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन में किया जाएगा। इसके अलावा विस्थापित परिवारों, गरीबों व विभिन्न तरह से अक्षम लोगों की मदद की जाएगी। वित्त मंत्री सेरहिय मार्चेंको ने कहा, इस अनुदान से यूक्रेन सरकार को कर्ज के भार के बिना सामाजिक

- शिक्षकों, आवश्यक सेवा के कर्मियों व मानवीय मदद में खर्च होगी धनराशि

और मानवीय मदद पहुंचाने में सहूलियत मिलेगी। मंत्रालय ने कहा ,फरवरी, 2022 में रूस के आक्रमण के बाद अमेरिका से सीधे बजट सहायता लगभग 27 अरब डालर पहुंच चुकी है। यह अनुदान 60 अरब डालर पैकेज का एक भाग है।

ईरान पहुंचे रूस के पूर्व रक्षा मंत्री शोइगू: रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू सोमवार को तेहरान पहुंच गए। रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव शोइगू ईरान के राष्ट्रपति व अन्य नेताओं से बातचीत करेंगे।

फर्जीवाड़े में रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारी गिरफ्तार: रूसी सेना के मुख्य कांग्रेस सेंटर के डायरेक्टर व रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी सोमवार को फर्जीवाड़ा में गिरफ्तार कर लिए गए। रक्षा मंत्रालय के उप प्रमुख व्लादिमीर शेस्टेरोव को भी हिरासत में लिया गया है।

पीटीआइ ने कहा, जेल में इमरान को दिया जा रहा है घटिया खाना

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) ने सोमवार को दावा किया कि पंजाब की मुख्यमंत्री मरयम नवाज के आदेश पर जेल में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को घटिया खाना दिया जा रहा है। पीटीआइ ने कहा कि इससे इमरान का स्वास्थ्य खराब हो गया है। पार्टी ने इमरान की अविलंब चिकित्सकीय जांच कराने की मांग की है। इमरान की गिरफ्तारी के एक वर्ष पूरे होने पर पीटीआइ ने सोमवार को काला दिवस मनाया। नेशनल अकाउंटेबलिटी ब्यूरो ने 19 करोड़ पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में एक वर्ष पहले 71 वर्षीय इमरान को गिरफ्तार किया था। पीटीआइ के वरिष्ठ नेता मूनिस इलाही और जुल्फी बुखारी ने कहा कि मरयम नवाज के आदेश पर जेल में पूर्व प्रधानमंत्री को घटिया खाना दिया जा रहा है और वह बीमार हो गए हैं। रविवार को इमरान ने पिछले वर्ष नौ मई को हुए दंगे के लिए क्षमा मांगने से मना कर दिया।

'बीजिंग ने पाक के लिए जो किया, वह अमेरिका कभी नहीं कर सका'

इस्लामाबाद, प्रेट्र : प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से अपने संबंध सुधारना चाहता है, पर चीन के साथ संबंधों की कीमत पर नहीं। कहा, बीजिंग ने पाकिस्तान के लिए जो किया है, वह अमेरिका कभी नहीं कर सका।

हाल ही में चीन की आधिकारिक यात्रा से लौटे पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के 72 वर्षीय नेता ने माडल टाउन स्थित अपने आवास पर पत्रकारों के एक समूह के साथ बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। शरीफ ने कहा, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीनी विशेषज्ञों की हालिया पाकिस्तान यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने में सकारात्मक प्रगति हुई है। उनसे जब पाक व अमेरिका के संबंधों के बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने कहा,पाकिस्तान वाशिंगटन के साथ संबंधों को सुधारना चाहता है। यह पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी भी है लेकिन यह चीन की कीमत

- हाल में चीन की आधिकारिक यात्रा से लौटे पाकिस्तानी पीएम ने दिया बयान

कहा, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण में काम तेजी से बढ़ रहा

पर नहीं होना चाहिए। पूर्व पीएम इमरान खान की ओर से उन्हें सत्ता से बेदखल करने के पीछे अमेरिकी हाथ होने का आरोप लगाने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई है।

शरीफ ने कर्ज चुकाने के लिए और समय देने के लिए बीजिंग को लिखे पत्र का भी जिक्र किया। कहा,अगर ऋण वापसी के लिए पांच-सात साल की मुहलत देने को चीन राजी हो जाए, तो देश में महंगाई और बढ़ते बिजली बिल पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है।

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाने के लिए इजरायल को देंगे सजा : ईरान

दुबई, रायटर: ईरान में हमास प्रमुख की हत्या और लेबनान में हिजबुल्ला के शीर्ष कमांडर के मारे जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच, ईरान ने कहा है कि वह क्षेत्र में तनाव नहीं चाहता है लेकिन यहां अस्थिरता के लिए जिम्मेदार इजरायल को जरूर दंडित करना चाहता है। तेहरान और बेरुत में हुई दोनों हत्याओं के लिए ईरान इजरायल को जिम्मेदार मानता है। दूसरी ओर, अमेरिका ने कहा है कि पश्चिम एशिया में अतिरिक्त सैन्य तैनाती का उद्देश्य क्षेत्र में तनाव को कम करना है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नसीर कनानी ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में स्थिरता के हिमायती हैं लेकिन यह तभी संभव है जब आक्रामकता बढ़ाने वाला दंडित हो। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को इजरायल का समर्थन न करने की अपील करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम बताया। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की 31 जुलाई को तेहरान में हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप इजरायल पर लगाया गया था, जबकि इजरायल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं, इजरायली मीडिया के अनुसार, इजरायल बड़े पैमाने पर ईरान के खतरे से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर सुरक्षा अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है।

- क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य तैनाती का उद्देश्य तनाव को कम करना : अमेरिका
- ईरान के खतरे से निपटने की बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है इजरायल

फलस्तीन, लेबनान और हिजबुल्लाह के झंडे के साथ बेरूत में इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त इमारत के बाहर प्रदर्शन करते लोग। रायटर

उधर, पेंटागन ने शुक्रवार को कहा था कि वह क्षेत्र में अतिरिक्त जेट और नौसैनिक पोतों की तैनाती कर रहा है। व्हाइट हाउस के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन फाइनर ने कहा कि कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य पश्चिम एशिया में तनाव को दूर करना है। अमेरिका ने ईरान की धमकी को देखते हुए भूमध्य सागर में समुद्री बेड़े को भेजा है, जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। इस बीच, इजरायल ने गाजा पट्टी में मारे गए 80 से अधिक फलस्तीनियों का शव वापस किया है।

हिजबुल्ला का इजरायल के सैन्य ठिकानों पर हमला: लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्ला ने कहा है कि उसने सोमवार को उत्तरी इजरायल स्थित सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। इजरायली सेना ने कहा कि इसमें दो इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। हिजबुल्ला ने कहा कि यह कार्रवाई दक्षिणी लेबनान के गांवों पर इजरायली हमले के जवाब में किया गया है। दूसरी ओर, अधिकारियों ने रविवार को कहा कि यमन के हाउती विद्रोहियों के एक मिसाइल हमले ने अदन की खाड़ी से यात्रा कर रहे लाइबेरिया के ध्वज वाले कंटेनर जहाज पर हमला किया है। यह इजरायली हवाई हमलों के बाद समूह द्वारा पहला हमला था।

हमास के मंत्री की हमले में मौत, इजरायल ने बताया आतंकी: इजरायल के रक्षा मंत्री ने सोमवार को इसकी पुष्टि की है एक दिन पहले गाजा पट्टी में हमास के आर्थिकी मंत्री आबेद-अल-जेरीई को एक दिन पहले हवाई हमले में मार गिराया गया है। कहा, वह हमास लड़ाकों को ईंधन, गैस और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता था। जरीई हमास की सैन्य शाखा के निर्माण विभाग को संचालित करता था। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आइडीएफ) ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जेरीई हमास का शीर्ष आतंकी था। वह गाजा के नागरिकों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचने देता था।

****

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हंगामे के बीच सोमवार को तख्तापलट के बाद उग्र प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए ● एएफपी

बांग्लादेश आंदोलन के पीछे विदेशी हाथ होने की आशंका : हर्षवर्धन श्रृंगला

नई दिल्ली, एएनआइ : बांग्लादेश के पूर्व भारतीय उच्चायुक्त और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कहा कि शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के पीछे विदेशी हाथ होने की आशंका है। बांग्लादेश में जो भी सत्ता व्यवस्था में है, भारत उसके बातचीत करेगा। दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत हैं।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में इस राजनीतिक संकट में आर्थिक कारकों और अवसरवादियों का योगदान है। एक अस्थिर बांग्लादेश हमारे देश के कुछ हिस्सों में अस्थिरता बढ़ा सकता है। एक शांतिपूर्ण, समृद्ध, स्थिर बांग्लादेश ही भारत के हित में है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ काम करें कि हमारे और बांग्लादेश के हित सुरक्षित रहें। भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि भारत ने बांग्लादेश की सहायता की है और बांग्लादेश ने भारत की। क्या शेख हसीना को भारत में आश्रय दिया जाएगा या वह अन्य देश जाएंगी, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रृंगला ने कहा कि भारत ने कभी भी अपने पड़ोस में रहने वालों को सुरक्षित आश्रय या शरण देने से इन्कार नहीं किया है।

बांग्लादेश से लगी सीमा पर जारी किया हाई अलर्ट

नई दिल्ली, जेएनएन: बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल ने सोमवार को 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिटों के लिए सोमवार को हाई अलर्ट जारी किया है। बिगड़ते हालात के बीच सुबह 10.30 बजे बीएसएफ के कार्यवाहक महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी दिल्ली से सीधे कोलकाता पहुंचे। वहां चौधरी ने पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक रवि गांधी और दक्षिण बंगाल के महानिरीक्षक मनिंदर प्रताप सिंह के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बीएसएफ प्रमुख के अगले कुछ दिनों तक इस क्षेत्र में रहने की उम्मीद है। बीएसएफ ने सभी फील्ड कमांडरों को निर्देश दिया गया है कि वह कर्मियों को सीमा पर तुरंत तैनात करें। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में व्यापक स्तर पर हो रहे प्रदर्शन के मद्देनजर पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पड़ोसी देश से लगी सीमा पर तैनात सभी कर्मियों की छुट्टियां रद कर दी गई थीं। अब सभी यूनिट को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा।

तख्तापलट के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास में घुसे प्रदर्शनकारी कुर्सियों पर बैठकर इस तरह से आराम करते दिखे ● एएफपी

बेटे ने कहा- राजनीति में वापसी नहीं करेंगी हसीना

लंदन, प्रेट्र : शेख हसीना के बेटे और पूर्व आधिकारिक सलाहकार सजीब वाजेद जाय ने सोमवार को यह दावा किया। सजीब वाजेद ने कहा कि उनकी मां हसीना ने परिवार के आग्रह पर अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ा है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पर न्यूजआवर को दिए साक्षात्कार में, जाय ने कहा कि उनकी मां शेख हसीना की कोई राजनीतिक वापसी नहीं होगी। हसीना रविवार से ही इस्तीफा देने पर विचार कर रही थीं। जाय ने कहा कि उनकी मां, जिन्होंने 15 साल तक बांग्लादेश पर शासन किया था, बहुत निराश थीं। जाय ने अपनी मां के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, जब हसीना ने देश की सत्ता संभाली तो बांग्लादेश गरीब देश हुआ करता था। आज इसे एशिया के उभरते देशों में से एक माना जाता है। प्रदर्शनकारियों से निपटने में सरकार द्वारा सख्ती बरतने के आरोपों को खारिज करते हुए जाय ने कहा, जब भीड़ लोगों को पीट-पीटकर मार रही हो, तो पुलिस से क्या उम्मीद करेंगे।

एक नजर में

एअर इंडिया, इंडिगो ने ढाका के लिए उड़ानें रद कीं

नई दिल्ली : बांग्लादेश के हालात को देखते हुए एअर इंडिया और इंडिगो ने सोमवार को तत्काल प्रभाव से ढाका से आने-जाने वाली उड़ानें रद कर दी हैं। वहीं, विस्तारा के एक अधिकारी ने कहा कि सोमवार को मुंबई से उड़ान संचालित की गई और मंगलवार को ढाका के लिए उड़ान संचालन को लेकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एअर इंडिया दिल्ली से ढाका के लिए दो दैनिक उड़ानें संचालित करती हैं, विस्तारा मुंबई से दैनिक उड़ानें और दिल्ली से बांग्लादेश की राजधानी के लिए तीन साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है। इंडिगो की दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से ढाका के लिए उड़ानें हैं। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, 'हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और ढाका से आने-जाने के लिए कन्फर्म बुकिंग वाले यात्रियों को यात्रा की रिशेड्यूलिंग और कैंसिलेशन शुल्क पर एक बार छूट दे रहे हैं।' वहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच सभी ट्रेन सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दी गई हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस ने जुलाई के मध्य में अपनी आखिरी यात्राएं संचालित की थीं, तब से हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण रद हैं।

दो महीने पहले ही बांग्लादेश के सेना प्रमुख बने वकार

ढाका, रायटर : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

वकार उज जमां

इसकी घोषणा सेना प्रमुख वकार-उज-जमां ने की। वह दो महीने पहले ही सेना प्रमुख बने हैं। 58 वर्षीय जमां ने 23 जून को तीन साल की अवधि के लिए सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। 1966 में ढाका में जन्मे वकार-उज-जमां की शादी जनरल मुहम्मद मुस्तफिजुर रहमान की बेटी सारानाज कमालिका जमां से हुई, जो 1997 से 2000 तक सेना प्रमुख थे। जमां के पास नेशनल यूनिवर्सिटी आफ बांग्लादेश से डिफेंस स्टडीज में मास्टर डिग्री और किंग्स कालेज लंदन से डिफेंस स्टडीज में मास्टर आफ आर्ट्स की डिग्री है। सेना प्रमुख बनने से पहले उन्होंने छह महीने से कुछ अधिक समय तक जनरल स्टाफ के प्रमुख के रूप में कार्य किया। इस दौरान सैन्य संचालन और खुफिया जानकारी, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में बांग्लादेश की भूमिका की देखरेख की।

हसीना का सत्ता से बेदखल होना भारत को बड़ा झटका

- पाक की मदद से चल रहीं भारत विरोधी कट्टरपंथियों की दुकानें करवाईं थीं बंद
- काक्सबाजार में छिपकर रह रहे असम के आतंकियों का भी कराया था सफाया
- दक्षिण एशिया में भारत की सबसे विश्वस्त सरकार की हो गई विदाई

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

नई दिल्ली : इस साल सात जनवरी को अवामी लीग ने जब लगातार चौथी बार बांग्लादेश चुनाव में विजय हासिल की तो इसकी मुखिया शेख हसीना ने सोचा नहीं होगा कि सिर्फ आठ महीनों में ही उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। रिजर्वेशन कोटा पर जून, 2024 में ढाका में शुरू हुए छात्र आंदोलन ने बीते रविवार (चार अगस्त) को हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद बांग्लादेश की सेना ने भी पीएम हसीना की मदद करने से इन्कार कर दिया। अंततः सोमवार को सेना के विमान से हसीना को ढाका से भारत लाया गया। माना जा रहा है कि कुछ दिनों तक यहां रहने के बाद वह लंदन जा सकती हैं। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में भारत की सबसे विश्वस्त सरकार की भी विदाई हो गई है। बांग्लादेश का भविष्य कैसा होगा, अभी यह अस्पष्ट है। वहां सैन्य शासन लंबा चलता है या जल्द ही चुनाव करवाए जाएंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कई वजह हैं जिसके कारण बांग्लादेश के हालात भारत के लिए चिंता का कारण हैं।

सबसे विश्वस्त वैश्विक साझेदार रही हैं हसीना : पूरी दुनिया में कोई एक वैश्विक नेता जिस पर भारत आंख मूंद कर भरोसा कर सकता था, वह बंग-बंधु शेख मुजीबुर्रहमान की पुत्री शेख हसीना थीं। चाहे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की यूपीए-दो का कार्यकाल हो या विगत 10 वर्षों से पीएम नरेन्द्र मोदी की सरकार हो, शेख हसीना ने हमेशा भारतीय हितों का खयाल रखा। उन्होंने पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आइएसआइ के नेटवर्क और पाक की मदद से फल-फूल रहे भारत विरोधी कट्टरपंथियों की दुकानें बंद करवाईं। वर्षों से ढाका व काक्सबाजार में छिपकर रहने वाले असम के आतंकियों का सफाया कराया। उन्होंने पाक समर्थित आतंकवाद के मुद्दे पर सार्क व दूसरे मंचों पर हमेशा भारत का साथ दिया। जाहिर है कि अब इस पड़ोसी देश में जो भी नई सरकार आएगी, उसके साथ भारत का पुराना भरोसा बनाने में समय लगेगा। भारत ने भी हसीना के हितों का खयाल रखा। कभी वहां के अंदरूनी हालात में दखल नहीं दी। 2015 में सीमा विवाद विधेयक पारित कराने के साथ ही 40 वर्ष पुराने विवाद का निपटारा किया। बांग्लादेश को कई सड़कों, रेल मार्गों, ऊर्जा परियोजनाओं का तोहफा दिया।

बीएनपी व कट्टरपंथियों का साथ यानी भारत के साथ विश्वासघात : पीएम हसीना की सरकार में रहे कट्टरपंथी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) अब वहां की राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। पूर्व में बीएनपी शासनकाल के दौरान पीएम खालिदा जिया ने भारत के बजाय हमेशा चीन व पाकिस्तान को मदद पहुंचाई है। जिया ने भारत के बार-बार आग्रह करने के बावजूद उल्फा आतंकियों पर लगाम नहीं लगाई। वर्ष 2001-2006 के दौरान जिया के दूसरे कार्यकाल में पूरा बांग्लादेश पाकिस्तानी एजेंसी आइएसआइ का सबसे बड़ा भारत विरोधी अड्डा बन गया था। हसीना के देश छोड़ने की खबर के बाद बंग-बंधु की मूर्तियों, भारत से संबंधित भवनों आदि को नुकसान पहुंचाया गया है, वह बताता है कि वहां जमाते-इस्लामी को खुली छूट मिल गई है। जमात बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान भी पाकिस्तान परस्त रहा था।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के त्यागपत्र पर सोमवार को ढाका में एक सैनिक को कंधे पर बैठाने के साथ खुशी मनाते प्रदर्शनकारी ● एपी

चीन व पाकिस्तान के प्रभाव पर रखनी होगी नजर

बांग्लादेश में नए हालात वहां पाकिस्तान और चीन का प्रभुत्व बढ़ा सकते हैं। ढाका के जरिये भारत को घाव देने के पाकिस्तान के मंसूबों पर शेख हसीना की सरकार ने पानी फेर दिया था। हाल ही में जब हसीना सरकार ने तीस्ता नदी की सफाई का काम भारतीय सहयोग से करवाने का फैसला किया तो यह चीन को नागवार गुजरा। इस विवाद की वजह से बांग्लादेशी पीएम हसीना को जुलाई, 2024 में अपनी बीजिंग यात्रा अधूरी ही छोड़कर स्वदेश लौटना पड़ा था, जबकि चीन बांग्लादेश के लिए अपनी झोली खोलने को तैयार था। अब भारत को बांग्लादेश में मालदीव जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है।

पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लिए भी चुनौती

बांग्लादेश के साथ रिश्तों का संबंध सीधे तौर पर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने बांग्लादेश के जरिये पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काफी जोर दिया है। अभी यह क्षेत्र सिलीगुड़ी मार्ग से ही शेष भारत से जुड़ा हुआ है। रणनीतिक विशेषज्ञ इसे भारतीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती मानते हैं क्योंकि चीन की इस पर नजर रहती है। इस मार्ग को तोड़कर पूर्वोत्तर भारत का शेष भारत से संपर्क काटा जा सकता है। अप्रैल, 2023 में हसीना सरकार ने चट्टोग्राम व मोंगला पोर्ट के इस्तेमाल की खुली छूट भारत को दी थी, जिसे भारत की एक बड़ी रणनीतिक जीत बताया गया था।

रिश्तों का दीर्घकालिक एजेंडा अधर में जाता दिख रहा

जून, 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी और हसीना ने दीर्घकालिक रिश्तों का एक एजेंडा जारी किया था, जिसमें कैसे द्विपक्षीय रिश्तों को सैन्य व आर्थिक क्षेत्र में आगे ले जाना है, इसका रोडमैप था। इसमें आपसी सहयोग से रक्षा उपकरण बनाने से लेकर मुक्त व्यापार समझौता करने का लक्ष्य था। अब देखना होगा कि नई सरकार इस एजेंडे पर क्या रुख अख्तियार करती है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज है।

लगातार चौथी जीत के बावजूद शेख हसीना को क्यों छोड़ना पड़ा देश

ढाका, एपी : बांग्लादेश में इस वर्ष जनवरी में हुए चुनाव में लगातार चौथी बार शेख हसीना ने जीत हासिल की थी। लेकिन छह महीने बाद ही उनके खिलाफ आक्रोश इतना उग्र हो गया कि उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा।

क्यों शुरू हुआ प्रदर्शन : सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जुलाई में शुरू हुआ। हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन 16 जुलाई को हिंसक हो गया, जब प्रदर्शनकारी छात्र सुरक्षा अधिकारियों और सरकार समर्थक कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। अधिकारियों को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, रबर की गोलियां चलानी पड़ीं और देखते ही गोली मारने के आदेश के साथ कर्फ्यू लगाना पड़ा।

इंटरनेट बंद करना पड़ा : हालात काबू करने के लिए इंटरनेट और मोबाइल डाटा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पिछले महीने हिंसा में 150 लोग मारे गए। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के स्वतंत्रता संग्राम मे लड़ने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए 30 प्रतिशत तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इससे अवामी लीग पार्टी के समर्थकों को फायदा हुआ।

शेख हसीना ●

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुधरे हालात

बांग्लादेश में 56 प्रतिशत आरक्षण से छात्र परेशान थे। खासकर 30 प्रतिशत आरक्षण बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों के स्वजन को दिया गया था। कुछ वर्ष पहले छात्रों के विरोध के बाद सरकार ने इस 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी। बाद में इसे हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया, जिससे छात्र गुस्से में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 56 प्रतिशत आरक्षण को कम कर सात प्रतिशत कर दिया। इसके बाद देश में हालात शांत हो गए थे।

जांच का किया था वादा

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंटरनेट बहाल कर दिया। उम्मीद थी कि स्थिति सामान्य हो जाएगी. लेकिन विरोध लगातार बढ़ता गया। शेख हसीना ने हिंसा को दबाने के दौरान अधिकारियों की ओर से की गई लापरवाही की जांच और कार्रवाई की भी बात कही थी। लेकिन छात्र नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया।

फिर बिगड़ी स्थिति

छात्रों की मांग थी कि शेख हसीना और उनका मंत्रिमंडल इस्तीफा दे। हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाकर फिर से इंटरनेट पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्र नहीं, बल्कि अपराधी हैं। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को ढाका के एक प्रमुख सार्वजनिक अस्पताल पर हमला किया और कई वाहनों के साथ-साथ सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों को आग लगा दी। 95 लोगों की मौत हो गई।

बांग्लादेश मामले में हम केंद्र के साथ : ममता

राज्य, जागरण ● कोलकाता : बांग्लादेश में जारी भारी हिंसा और शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के घटनाक्रम के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों से किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी के उकसावे में नहीं आने का भी आह्वान किया। विधानसभा स्थित अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बांग्लादेश के घटनाक्रम पर टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए कहा कि इस विषय पर विदेश मंत्रालय ही कोई प्रतिक्रिया देगा। यह दो देशों के बीच का मामला है। इस मुद्दे पर केंद्र जो भी फैसला लेगा, हम उसका समर्थन और निर्देशों का पालन करेंगे। ममता ने सभी दलों के नेताओं से भी अपील की कि वे भड़काऊ टिप्पणियां करने से बचें। बता दें कि इसके पहले बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर पिछले दिनों जब भारी हिंसा हो रही थी, तब ममता ने 21 कहा था कि वह पड़ोसी देश में संकट में फंसे लोगों के लिए बंगाल के दरवाजे खुले रखेंगी, कोई मदद मांगता है तो शरण देंगी।

भारत-बांग्लादेश व्यापार ठप हुआ

नई दिल्ली, जेएनएन: बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर भारत-बांग्लादेश व्यापार ठप हो गया है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल लैंड पोर्ट से माल की आवाजाही सोमवार को रुक गई। पेट्रापोल के क्लीयरिंग एजेंट्स स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव कार्तिक चक्रवर्ती ने बताया कि बांग्लादेश की ओर 250-300 भारतीय ट्रक फंसे हुए हैं। पेट्रापोल बांग्लादेश की सीमा पर भारतीय सीमा पर स्थित लैंड पोर्ट है। चक्रवर्ती ने कहा कि हम बांग्लादेश के नए प्रशासन से ट्रकों, माल और ड्राइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे। बता दें कि हर दिन औसतन 450-500 ट्रक भारत से दक्षिण एशिया के सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रापोल के माध्यम से बांग्लादेश जाते हैं। लगभग 150-200 ट्रक दूसरी तरफ से आते हैं। सालाना, लगभग 22 लाख लोग पेट्रापोल चेक प्वाइंट के माध्यम से सीमा पार करते हैं। पेट्रापोल बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में स्थित है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। यह कोलकाता से लगभग 80 किमी की दूरी पर है।

चीन, पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका भी हसीना से था नाराज

प्रथम पृष्ठ से आगे

विदेशी ताकतें कितनी जिम्मेदार : इस बारे में पुख्ता तौर पर ना तो भारतीय खुफिया एजेंसियों के लोग कुछ बोल रहे हैं और ना ही विदेश मंत्रालय के अधिकारी। लेकिन यह सच है कि शेख हसीना की सरकार से पाकिस्तान तो पहले से नाराज था, हाल के दिनों में चीन और अमेरिका भी नाराज हो गए थे। पाकिस्तान इसलिए नाराज था, क्योंकि हसीना ने उसके समर्थक कट्टरपंथियों व जमात के लोगों को सजा दिलाई और उसके भारत विरोधी गतिविधियों को बंद कराया। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है कि सेना की तरफ से हसीना का साथ नहीं देने के पीछे विदेशी ताकतों का दबाव भी हो सकता है। चीन की सरकार हसीना के भारत के साथ लगातार मजबूत होते रिश्तों से नाराज हो गई थी।

जुलाई, 2024 में बीजिंग दौरे से पहले जून, 2024 में हसीना के नई दिल्ली आने के बाद चीन की नाराजगी साफ सामने आ गई, जब हसीना से औपचारिक मुलाकात करने भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी नहीं आए। अमेरिका हाल के वर्षों में हसीना सरकार की तरफ से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ कदम उठाने व विपक्षी दलों को दबाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर नाराज हो चला था। जनवरी, 2024 के आम चुनाव से पहले अमेरिका की कोशिश थी कि ढाका में एक केयरटेकर सरकार बने, जिसके अधीन चुनाव हो। तब सिर्फ भारत ने हसीना की मदद की। यह भी अजीब संयोग है कि अमेरिका हसीना सरकार से इसलिए नाराज था कि वह चीन से सैन्य मदद हासिल कर रही थी, जबकि चीन हसीना को इसलिए नापसंद करता था कि वह भारत को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं।

एक दिन पहले सेना ने खड़े किए हाथ : विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि बांग्लादेश सरकार और सेना के बीच समन्वय पिछले साल से ही गड़बड़ाया हुआ था। नौकरियों में कोटा (आरक्षण) को लेकर विद्यार्थियों के विरोध को कुचलने में सेना ने वैसी तत्परता नहीं दिखाई जैसा कि हसीना सरकार उम्मीद कर रही थी। शनिवार व रविवार को राजधानी में छात्रों के साथ सभी विपक्षी दलों व जमाते-इस्लामी के लोगों के ढाका में एकत्रित होने के बाद सेना की तरफ से हसीना को बता दिया गया कि अब कोई विकल्प तलाशना होगा। पूर्व राजनयिक अजय बिसारिया इसकी एक वजह यह भी बताते हैं कि बांग्लादेश की सेना में भी कुछ अंतराल पर तख्ता पलट करने की आदत वैसी ही रही है जैसा कि पाकिस्तान की सेना करती रही है। यह कुछ वर्षों तक लोकतांत्रिक सरकार चलाने देते हैं और फिर उसे हटा देते हैं। लेकिन इनकी एक खासियत यह है कि कुछ अंतराल के बाद यह फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुने गए प्रतिनिधि को सत्ता सौंप देते हैं। हम वर्ष 2007 में ऐसा देख चुके हैं। ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ ने साफ तौर पर हसीना को बता दिया कि अब उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। एक अन्य वरिष्ठ रणनीतिकार ब्रह्मा चेलानी का कहना है कि पिछले पांच दशकों में दो दर्जन बार बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट की कोशिश हुई है। इनमें से कुछ सफल भी हुए हैं। जिस तरह से सेना प्रमुख ने हसीना के हटने की घोषणा की है वह भी बताता है कि यह सैन्य समर्थित निकासी ही है।

बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की रही है महत्वपूर्ण भूमिका

जेएनएन, नई दिल्ली

वर्ष 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का संघर्ष एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) और पश्चिमी पाकिस्तान (वर्तमान पाकिस्तान) के बीच उस वक्त राजनीतिक और सांस्कृतिक मतभेद गहराते जा रहे थे। इसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान की पहचान, भाषा (बांग्ला) और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण देश में काफी असंतोष बढ़ रहा था।

इसके परिणामस्वरूप सन् 1971 में, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की मांग ने गंभीर रूप ले लिया। इस संघर्ष में भारत ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में बढ़ते तनाव और मानवाधिकार के उल्लंघनों के कारण, शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखा गया और इसने राजनीतिक-मानवतावादी कारणों के चलते वहां पर हस्तक्षेप किया। वर्ष 1971 की शुरुआत में, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई। दिसंबर 1971 में भारतीय सेना द्वारा बांग्लादेश में घुसपैठ कर दी गई और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के समर्पण के साथ बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया।

ढाका में सोमवार को हिंसक प्रदर्शन के दौरान बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में आग लगा दी गई। इस दौरान बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान के पोर्ट्रेट पर प्रहार करता प्रदर्शनकारी ● एएफपी

स्वतंत्रता के बाद से बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास काफी उथल-पुथल से भरा रहा है। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान ने देश को एक नई शुरुआत दी और इसे एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की दिशा में ले जाने का प्रयास किया। हालांकि, अपने अस्तित्व में आने के चार साल के भीतर ही 1975 में हुए एक तख्तापलट में शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या कर दी गई और देश में सैन्य शासन की शुरुआत हो गई। तब से शुरू हुआ यह सिलसिला, अब तक नहीं रुका और बांग्लादेश में कई बार राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हुई और तख्तापलट हुए। इसके बाद 1980 और 1990 के दशक में, बांग्लादेश ने एक नए लोकतांत्रिक ढांचे की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाया। वर्ष 1991 में वहां पर बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी हुई और इसके साथ ही बांग्लादेश ने संवैधानिक लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ना शुरू किया।

बांग्लादेश के शासकों का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है और इसमें कई रंग देखने को मिलते हैं। जैसे, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के प्रमुख नेता और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान (1971-1975) ने सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर जोर दिया। लेकिन वह स्थिरता लाने में असफल रहे और उनके बाद तख्तापलट ने यहां की राजनीति को अस्थिर कर दिया।

इसके बाद एक सैन्य तानाशाह जनरल जिया उर रहमान (1975-1981) ने कब्जा जमाया और उन्होंने बांग्लादेश में सैन्य शासन चलाया। उन्हें राजनीतिक विपक्ष को कुचलने के लिए पहचाना गया।

****

आज पुरुषों की भालाफेंक क्वालीफिकेशन में उतरेंगे चोपड़ा और किशोर जेना

भारत को नीरज के चमकने का इंतजार

नीरज चोपड़ा ● एएनआइ

पेरिस, प्रेट्र : भारतीय एथलेटिक्स के लिए कई कीर्तिमान बना चुके नीरज चोपड़ा अपने दूसरे ओलिंपिक में एक बार फिर अपने भाले से इतिहास रचना चाहेंगे, चूंकि 140 करोड़ भारतीयों को उनसे एक बार फिर पीले तमगे की उम्मीद है। नीरज मंगलवार को किशोर जेना के साथ भालाफेंक क्वालीफिकेशन में उतरेंगे। उनकी अप्रतिम निरंतरता की एक बार फिर परीक्षा होगी क्योंकि पूरे सत्र में वह जांघ के भीतरी हिस्से की मांसपेशी में (एडक्टर) परेशानी से जूझते आए हैं।

चोपड़ा अगर स्वर्ण जीतते हैं तो ओलिंपिक के इतिहास में खिताब बरकरार रखने वाले पांचवें खिलाड़ी बन जाएंगे। इसके साथ ही ओलिंपिक व्यक्तिगत वर्ग में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बनेंगे। ओलंपिक की पुरुष भालाफेंक स्पर्धा में अभी तक एरिक लेमिंग (स्वीडन 1908 और 1912), जोन्नी माइरा (फिनलैंड 1920 और 1924), जान जेलेंजी (चेक गणराज्य 1992 और 1996) और आंद्रियास टी (नार्वे 2004 और 2008) की ओलिंपिक में भालाफेंक स्पर्धा में खिताब बरकरार रख सके हैं। इस साल चोपड़ा ने सिर्फ तीन स्पर्धाओ में भाग लिया लेकिन उनके बाकी प्रतिस्पर्धी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। हालांकि उनके कोच ने फिटनेस को लेकर चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि अब उनके एडक्टर में कोई परेशानी नहीं है और वह कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। भारत के किशोर जेना भी दौड़ में हैं जिन्होंने पिछले साल एशियाई खेलों में 87.54 मीटर का थ्रो फेंककर क्वालीफाई किया था लेकिन उसके बाद से 80 मीटर तक भी नहीं पहुंच पाए हैं।

जर्मनी को हराकर पदक पक्का करने उतरेगी हाकी टीम

« ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान भारतीय हाकी टीम के खिलाड़ी ● फाइल फोटो, एपी

- सेमीफाइनल में जीत से कम से कम रजत हो जाएगा पक्का
- पिछली बार भारत ने जीता था कांस्य

पेरिस, प्रेट्र : ओलिंपिक में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने की राह पर भारतीय हाकी टीम के सामने मंगलवार को सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन जर्मनी की चुनौती होगी और इस बाधा को पार करके टीम 'संकटमोचक' पीआर श्रीजेश को शानदार विदाई देने के अपने मिशन की अगला कदम रखेगी।

ब्रिटेन के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल में दस खिलाड़ियों तक सिमटने के बावजूद भारतीय टीम ने जिस साहस और कौशल का प्रदर्शन करके मुकाबला पेनाल्टी शूटआउट तक खिंचा, वह प्रशंसनीय है।

टोक्यो ओलिंपिक कांस्य पदक मैच में जर्मनी की पेनाल्टी बचाकर भारत को 41 साल बाद पदक दिलाने वाले नायक श्रीजेश एक बार फिर जीत के सूत्रधार बने थे। 36 वर्ष के श्रीजेश का यह आखिरी टूर्नामेंट है और उन्हें स्वर्ण पदक के साथ विदा करने का मिशन भारतीय टीम के लिए अतिरिक्त प्रेरणा बना है। भारत ने आठ ओलिंपिक स्वर्ण में से आखिरी 1980 में मास्को में जीता था और अब पेरिस में उसके पास 44 साल बाद इतिहास रचने का मौका है। सेमीफाइनल जीतने पर भारत का रजत तो पक्का हो जाएगा जो अंतिम बार उसने 1960 में रोम में जीता था।

अमित रोहिदास नहीं खेलेंगे: प्रमुख डिफेंडर अमित रोहिदास मंगलवार को होने वाले सेमीफाइनल मैच में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उन पर लगाए गए एक मैच के निलंबन के खिलाफ दायर की गई हाकी इंडिया की अपील को एफआइएच ने खारिज कर दिया है। रोहिदास को ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल मैच के रेड कार्ड मिला था जिसके कारण एफआइएच ने उन्हें एक मैच के लिए निलंबित कर दिया था। इसका मतलब है कि इस महत्वपूर्ण मैच के लिए भारत के केवल 15 खिलाड़ी ही उपलब्ध रहेंगे जो आठ बार के ओलिंपिक चैंपियन के लिए करारा झटका है।

आज उतरेंगी विनेश

नई दिल्ली : भारत की सबसे भरोसेमंद और पदक की प्रबल दावेदार विनेश फोगाट मंगलवार को महिला 50 किलोग्राम वर्ग में भारतीय चुनौती पेश करेंगी। फोगाट दो विश्व चैंपियन, तीन कामन वेल्थ और आठ एशियन चैंपियन पदक अपने नाम कर चुकी है, लेकिन पेरिस में पदक थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फोगाट को पहले ही दौर में टोक्यो ओलिंपिक की स्वर्ण पदक विजेता जापान की युई सुसाकी से भिड़ना है।

आज के कार्यक्रम

एथलेटिक्स : पुरुष भाला फेंक क्वालीफिकेशन ग्रुप ए, दोपहर 1:50 बजे (**किशोर जेना**), पुरुष भाला फेंक क्वालीफिकेशन ग्रुप बी, दोपहर 3:20 बजे (**नीरज चोपड़ा**), महिला 400 मीटर दौड़ रेपचेज, दोपहर 2:50 बजे (**किरन पहल**)

टेबल टेनिस : पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल, दोपहर 1:30 बजे (**भारत बनाम चीन**)

कुश्ती : 50 किग्रा राउंड आफ 16, दोपहर 2:30 बजे (**विनेश बनाम यूई सुसाकी**)

हाकी : सेमीफाइनल मुकाबला, रात 10:30 बजे (**भारत बनाम जर्मनी**)

तालिका

देश	सोना	चांदी	कांस्य	कुल
1 चीन	21	17	14	52
2 अमेरिका	19	29	27	75
3 आस्ट्रेलिया	13	11	8	32
4 फ्रांस	12	15	18	45
5 ग्रेट ब्रिटेन	11	13	17	41
6 द. कोरिया	11	8	7	26
7 जापान	10	5	11	26
8 इटली	9	10	6	25
9 जर्मनी	6	5	4	15
9 नीदरलैंड्स	6	5	4	15
59 भारत	0	0	3	3

पदक तालिका *रात 12:00 बजे तक

पांचवीं बार भारत के हाथ से फिसला कांस्य

पेरिस ओलिंपिक में सोमवार को बैडमिंटन और निशानेबाजी में भारत के हाथों से कांस्य पदक आते-आते फिसल गया। पहले स्कीट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में जहां अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान कांस्य पदक चूक गए तो बैडमिंटन में कांस्य पदक के मुकाबले में लक्ष्य सेन को भी मलेशियाई प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध हार मिली। ये पांचवां अवसर था, जब भारत पदक से चूका। इससे पहले, मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा अर्जुन बबूता चौथे स्थान पर रहे थे। वहीं तीरंदाजी में अंकिता भकत और धीरज बोम्मादेवरा कांस्य पदक का मुकाबला हार गए थे।

इतिहास रचने से चूक गए लक्ष्य सेन

मैच के दौरान लक्ष्य के हाथ में लगी चोट ● प्रेट्र

पेरिस, प्रेट्र: लक्ष्य सेन पहला गेम जीतने और दूसरे में बढ़त बनाने के बावजूद बैडमिंटन की पुरुष सिंगल्स स्पर्धा के कांस्य पदक के प्लेआफ मुकाबले में सोमवार को मलेशिया के ली जी जिया के विरुद्ध दो गेम में हारकर इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने से चूक गए। इस दौरान लक्ष्य के दाहिने हाथ की कोहनी पर लगी चोट से खून निकलने लगा, हालांकि मैच रोककर उनकी पट्टी की गई पर इससे वह बहुत परेशान दिख रहे थे। सेमीफाइनल की तरह कांस्य पदक के प्लेआफ में भी विश्व के 22वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य ने बढ़त गंवाई और उन्हें 71 मिनट चले मुकाबले में विश्व के सातवें नंबर के खिलाड़ी ली के विरुद्ध 21-13, 16-21, 11-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ लक्ष्य साइना नेहवाल और पीवी सिंधू के बाद ओलिंपिक पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का अवसर भी गंवा दिया। इससे पहले साइना ने 2012 लंदन ओलिंपिक में कांस्य और पीवी सिंधू ने 2016 रियो ओलिंपिक में रजत और टोक्यो ओलिंपिक में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य की ली के विरुद्ध छह मैचों में यह दूसरी हार है। लक्ष्य को रविवार को अंतिम चार के मुकाबले में स्वर्ण पदक विजेता एक्सेलसन के विरुद्ध हार मिली थी।

सिर्फ एक अंक से चूके अनंत और महेश्वरी

महेश्वरी चौहान ● रायटर

चेटेरोक्स, प्रेट्र : भारतीय निशानेबाज महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका पेरिस ओलिंपिक स्कीट मिक्स्ड टीम स्पर्धा के कांस्य पदक के मुकाबले में सोमवार को चीन की यितिंग जियांग और लियू जियानलिन की जोड़ी से सिर्फ एक अंक से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को 48 निशाने के फाइनल मैच में 44-43 से हार मिली। महेश्वरी अपने 24 निशाने में से तीन में चूक गई, जबकि नरूका दो निशाने चूके। वहीं लियू अपने चार निशाने चूक गई, लेकिन जियांग ने अपने 24 में से 24 शाट लगाकर इसकी भरपाई कर दी। भारतीय जोड़ी क्वालीफिकेशन के पहले चरण के बाद 49 अंक लेकर संयुक्त दूसरे स्थान पर थी। पहले दौर में नरूका ने 25 में से 25 और महेश्वरी ने 24 अंक बनाए। दूसरे दौर में महेश्वरी ने 25 अंक बनाए लेकिन नरूका दूसरी और पांचवीं सीरीज में चूककर 23 अंक ही बना सके।

मनिका ने भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया

जीत के बाद मनिका बत्रा ● एएफपी

पेरिस, प्रेट्र : स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा की अगुआई में भारत ने सोमवार को यहां पेरिस ओलंपिक की महिला टेबल टेनिस टीम स्पर्धा में अपने से ऊंची रैंकिंग वाले रोमानिया को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत 2-0 से आगे चल रहा था लेकिन रोमानिया ने वापसी करते हुए 2-2 से बराबरी प्राप्त कर ली लेकिन निर्णायक मैच में मनिका ने जीत दर्ज करने टीम को जीत दिला दी।

श्रीजा अकुला और अर्चना कामथ ने डबल्स मैच में एडिना डायकोनू और एलिजाबेटा समारा पर 11-9, 12-10, 11-7 से जीत दर्ज करके मुकाबले की शुरुआत की। मनिका ने बर्नाडेट जोक्स को 11-5, 11-7, 11-7 से हराया जिससे भारत ने अपने चौथे वरीयता प्राप्त प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध 2-0 की बढ़त हासिल की। दूसरे सिंगल्स में श्रीजा को समारा से 2-3 से हार मिली थी।

रेपचेज में उतरेंगी किरण

पेरिस: भारत की किरण पहल सोमवार को अपनी हीट रेस में सातवें स्थान पर रहने के बाद महिलाओं की 400 मीटर के सेमीफाइनल में जगह बनाने में असफल रहीं। अब वह रेपेचेज दौर में दौड़ेंगी। किरण ने 52.51 सेकेंड का समय लिया जो उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ से बहुत कम था।

चोट के बाद जीता हुआ मुकाबला हारीं निशा

पेरिस, प्रेट्र: भारतीय पहलवान निशा दहिया दाएं हाथ में चोट के कारण शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सकी और महिला 68 किग्रा कुश्ती मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में सोमवार को उत्तर कोरिया की पाक सोल गम से हार गईं। सोल गम ने निशा को 10-8 से शिकस्त दी। एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता पहलवान निशा ने उत्तर कोरिया की पहलवान के खिलाफ शुरुआती कुछ सेकेंड में ही 4-0 की बढ़त बना ली। उन्होंने इसके बाद तीन मिनट के शुरुआती पीरियड में रक्षात्मक रवैया अपनाकर उत्तर कोरिया की पहलवान को कोई मौका नहीं दिया।

निशा ने दो और अंक के साथ अपनी बढ़त मजबूत की लेकिन इस दौरान उनका दाहिना हाथ गंभीर रूप से चोटिल हो गया। उन्होंने इलाज के बाद खेल शुरू किया लेकिन उत्तर कोरिया की पहलवान को नहीं रोक सकीं।

हार के बाद दर्द से कराहतीं निशा ● एएफपी

अविनाश साबले ने फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास

अविनाश साबले ● रायटर

पेरिस, प्रेट्र: भारतीय धावक अविनाश साबले ने इतिहास रचते हुए सोमवार को पेरिस ओलिंपिक में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज (बाधा दौड़) के फाइनल में जगह बना ली। साबले ओलिंपिक की इस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं।

साबले हीट नंबर दो में 8:15.43 सेकेंड का समय लेकर पांचवें स्थान पर रहे और फाइनल में पहुंचे। इस स्पर्धा की तीन हीट से शीर्ष पांच एथलीट फाइनल में पहुंचते हैं। साबले की हीट में मोरक्को के मोहम्मद तिदोफ 8:10.62 सेकेंड का समय निकालकर शीर्ष स्थान पर रहे। यह मोरक्को के खिलाड़ी का निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। इस स्पर्धा का फाइनल मंगलवार को खेला जाएगा।

समापन समारोह में मनु भाकर होंगी ध्वजवाहक

मनु भाकर

पेरिस, प्रेट्र : पेरिस ओलिंपिक में दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली निशानेबाज मनु भाकर रविवार को होने वाले समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीत कर पेरिस ओलिंपिक में भारत का खाता खोला था। इस तरह से वह ओलिंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी थीं। इसके बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड टीम का कांस्य पदक भी जीता था। भारतीय ओलिंपिक संघ के एक अधिकारी ने कहा कि मनु को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। उन्होंने बेजोड़ प्रदर्शन किया और वह इसकी हकदार हैं।

100 मीटर दौड़ में आठ धावकों के बीच रहा 0.12 सेकेंड का अंतर

ओलिंपिक में विश्व

पुरुष 100 मीटर फर्राटा दौड़ के दौरान खिलाड़ी ● एएफपी

1988 में स्वर्ण विजेता कार्ल लुइस ने 9.925 सेकेंड में पूरी की थी 100 मीटर फर्राटा दौड़, अब 9.91 सेकेंड में दौड़ पूरी करने वाले सेविले भी आठवें स्थान पर रहे

अमेरिका के स्वर्ण विजेता नोआह लाइल्स ने 9.79 सेकेंड तो आठवें स्थान पर रहे सेविले ने 9.91 सेकेंड में पूरी की दौड़

फाइनल दौड़ का परिणाम

रैंक	धावक	देश	समय
1	लाइल्स	अमेरिका	9.79 (0.784)
2	थांपसन	जमैका	9.79 (0.789)
3	कर्ली	अमेरिका	9.81
4	सिंबिन	द. अफ्रीका	9.82
5	जैकब्स	इटली	9.85
6	टेबोगो	बोत्सवाना	9.86
7	केनेथ	अमेरिका	9.88
8	सेविले	जमैका	9.91

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: ओलिंपिक के सबसे रोमांचक 100 मीटर फर्राटा दौड़ में पेरिस में सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिला। धड़कनों को थाम देने वाले फाइनल में विश्व के शीर्ष आठ सबसे तेज धावकों का मुकाबला भी शीर्ष रहा। स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी धावक नोआह लाइल्स और आठवें स्थान पर रहे जमैका के ओब्लिक सेविले के बीच केवल 0.12 सेकेंड का अंतर था। यहां तक की शीर्ष दो धावकों लाइल्स और जमैका के थांपसन के बीच केवल 0.005 सेकेंड का अंतर था और कांस्य पदक जीतने वाले अमेरिकी धावक फ्रेड कर्ले भी उनसे केवल 0.02 सेकेंड ही पीछे थे।

सांसें रोक देने वाली फाइनल दौड़ में नोआह लाइल्स उम्मीदों पर खरे उतरे। रजत पदक जीतने वाले थांपसन ने दौड़ के बाद कहा, 'मैं थोड़ा निराश हूं, लेकिन साथ में खुश भी हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसके साथ ही अब जीने को तैयार हूं।' जब किसी ने उनसे पूछा कि अन्य खेलों की तरह क्या इसमें भी स्वर्ण पदक दो धावकों में बंटनी चाहिए क्योंकि दोनों धावकों के बीच अंतर सेकेंड के भी 1000वें हिस्से में था तो इस पर उन्होंने बड़ा रोचक जवाब दिया। थांपसन ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह खेल बहुत प्रतिस्पर्धी है। यह अन्य खेलों की तरह नहीं है। मुझे नहीं लगता हमें इसमें कभी स्वर्ण पदक बांटने पर विचार करना चाहिए।'

अगर फिनिश लाइन पर थांपसन थोड़ा और झुके होते तो शायद यह पदक उनके नाम होता या अंत में अगर थोड़ा और दम लगाते तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। उन्होंने आगे कहा, 'मैं जानता हूं जमैका को स्वर्ण पदक चाहिए था। हर कोई विजेता को पसंद करते हैं।' थांपसन लेन चार में थे, जबकि लाइल्स लेन सात में ऐसे में उन्हें पता नहीं लग सका कि फिनिश लाइन पर वह सबसे आगे होते हुए भी केवल सेकेंड के भी हजारवें हिस्से से पिछड़ जाएंगे। लाइल्स को भी लगा था कि थांपसन ही विजेता रहे। लाइल्स ने बताया, 'मुझे भी लगा था थांपसन दौड़ जीत गए हैं। मैंने उन्हें यह भी कहा था कि भाई आपने बाजी मार ली है। और फिर अचानक मेरा नाम स्क्रीन पर आया मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ।' कमाल की बात यह है कि नोआह लाइल्स का यह व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी था। साथ ही पिछली बार के स्वर्ण पदक विजेता इटली के मार्सेल जैकब्स ने भी सत्र का सर्वश्रेष्ठ 9.85 सेकेंड का समय निकाला पर फिर भी वह पांचवें स्थान पर रहे।

बांग्लादेश में महिला टी-20 विश्व कप होना मुश्किल

अभिषेक त्रिपाठी ● जागरण

- **पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश को तीन से 20 अक्टूबर तक महिला टी-20 विश्व कप की करनी है मेजबानी**
- **बांग्लादेश में हिंसा के बाद आइसीसी के सदस्य देश फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं**

ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP BANGLADESH 2024

नई दिल्ली: आइसीसी की आंतरिक सुरक्षा टीम बांग्लादेश में फैली अराजकता पर नजर बनाए हुए है क्योंकि इस देश में अक्टूबर में महिला टी20 विश्व कप का आयोजन होना है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश को तीन से 20 अक्टूबर तक महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी करनी है। सोमवार को बांग्लादेश में फैली हिंसा के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ा। आइसीसी बोर्ड के सदस्य अभी इसे लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, परंतु बोर्ड से जुड़े एक सूत्र ने दैनिक जागरण को बताया कि ऐसी परिस्थितियों के बीच अब बांग्लादेश में टी-20 विश्व कप का आयोजन मुश्किल है।

आइसीसी बोर्ड के एक सदस्य ने कहा, 'आइसीसी के पास अपने सभी सदस्य देशों में एक स्वतंत्र सुरक्षा निगरानी प्रणाली है। स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने में सात सप्ताह बाकी हैं। ऐसे में इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी कि टूर्नामेंट को बांग्लादेश से स्थानांतरित किया जाएगा या नहीं।'

बांग्लादेश में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। इसके तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रविधान किया गया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने देर शाम घोषणा की कि वे राजनीतिक अस्थिरता के कारण ए टीम के आगामी पाकिस्तान दौरे को दो दिनों के लिए स्थगित कर रहे हैं।

वहीं, आइसीसी सूत्र ने कहा कि मार्च 2022 में श्रीलंका में अशांति की ऐसी ही स्थिति थी जब प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया था। इस घटना के बाद आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने जून में द्विपक्षीय सीरीज के लिए वहां की यात्रा की थी। बांग्लादेश में विश्व कप ढाका और सिलहट में आयोजित होने वाला है। भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने 'अगली सूचना तक भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी है।' बीसीसीआइ इस तरह की स्थितियों में हमेशा सरकार की सलाह मानता है। आइसीसी के पास अपरिहार्य स्थितियों के लिए आकस्मिक योजनाएं हैं और इस मामले में श्रीलंका एक विकल्प हो सकता है। श्रीलंका ने 2012 का पुरुष टी20 विश्व कप सितंबर और अक्टूबर के बीच वहां आयोजित किया था। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सेना देश (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया) अपनी महिला टीमों को ऐसे देश में भेजते हैं जहां सुरक्षा स्थिति कमजोर रह सकती है।

कभी भी पलट सकता था पासा : नायर

कोलंबो, प्रेट्र : भारत के सहायक कोच अभिषेक नायर ने दूसरे वनडे में श्रीलंका से मिली अप्रत्याशित हार का ठीकरा पिच पर फोड़ते हुए कहा कि विकेट काफी स्पिन ले रहा था और ऐसे में मैच किसी भी तरफ पासा पलट सकता था। भारतीय बल्लेबाजों की स्पिन के विरुद्ध कमजोरी खुलकर सामने आई जब उसे दूसरे वनडे में 32 रन से हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की ओर से लेग स्पिनर जेफरी वेंडर्से ने छह विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया।

नायर ने मैच के बाद कहा, 'यह आश्चर्यजनक था लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह की परिस्थितियों में मैच का पासा किसी भी तरह पलट सकता था क्योंकि पिच से बहुत अधिक स्पिन मिल रही थी।' भारत के सामने 241 रन का लक्ष्य था लेकिन उसकी पूरी टीम 42.2 ओवर में 208 रन पर आउट हो गई।

वाशिंगटन माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में

क्रिकेट डायरी

दुबई, प्रेट्र: पिछले महीने जिंबाब्वे के विरुद्ध पांच मैचों की टी-20 सीरीज में मिली 4-1 की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले वाशिंगटन सुंदर आइसीसी द्वारा जुलाई के लिए प्लेयर आफ द मंथ की दौड़ में हैं। जिंबाब्वे के विरुद्ध सीरीज में गेंदबाजी से आठ विकेट लिए और प्लेयर आफ द सीरीज चुने गए थे। वहीं श्रीलंका के विरुद्ध भी वह प्लेयर आफ द मैच रहे, जहां उन्होंने सुपर ओवर में जीत दिलाई थी।

वहीं वाशिंगटन सुंदर के अलावा जेम्स एंडरसन के संन्यास के बाद उनकी जगह ले रहे युवा गस एटकिंसन भी इस दौड़ में हैं। एटकिंसन ने अपनी तेज गेंदबाजी से वेस्टइंडीज बल्लेबाजों को संभलने का का अवसर नहीं दिया और तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 22 विकेट लिए। स्काटलैंड के तेज गेंदबाज चार्ली कैसल भी इस दौड़ में हैं।

100 टेस्ट खेलने वाले इंग्लैंड के थोर्प का निधन

ग्राहम थोर्प ● फाइल फोटो, रायटर

लंदन, प्रेट्र: इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज और कोच ग्राहम थोर्प का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 55 वर्षीय थोर्प ने 100 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि थोर्प 2022 से बीमार थे और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालांकि उनके निधन का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है।

90 के दौर में इंग्लैंड के सबसे सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ के बल्लेबाज थोर्प ने 1993 से 2005 तक 100 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 16 शतक और 39 अर्धशतक की मदद से 44.66 की औसत से 6744 रन बनाए।

खुद से चल भी नहीं पा रहे विनोद कांबली

नई दिल्ली, जेएनएन : भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली 52 वर्ष की आयु में खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुत साझा किया जा रहा है जिसमें वह अपने पैरों पर चलने में नाकाम दिख रहे हैं और उन्हें लोग मदद कर रहे हैं। कांबली काफी लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रहे हैं और कुछ समय पहले उनके दिल का आपरेशन भी हुआ था।

****

चिंतन धरोहर

श्रीरामकिंकर जी महाराज

सब पर कृपा करते हैं भगवान

श्रीरामचरितमानस की शास्त्रसम्मत एवं सार्वभौम व्याख्या के लिए स्वनामधन्य रामकिंकर उपाध्याय जी का यह शताब्दी वर्ष है...

मानस में वर्णन किया गया है कि कैवल्य परमपद मुक्ति बड़ी दुर्लभ है। साधना के बाद यदि तत्वज्ञान की उपलब्धि हो तो यह स्वाभाविक है, पर जब हम पढ़ते हैं कि वह मुक्ति राक्षसों को भी मिल गई तो आश्चर्य होता है। लंकाकांड में वर्णन है कि जब युद्ध समाप्त हो गया तो देवराज इंद्र ने प्रभु से प्रार्थना की कि कृपया मेरे लिए कोई सेवा बताएं। प्रभु ने कहा कि जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं, उन्हें अमृतवर्षा से जीवित कर दो। इंद्र ने युद्ध-स्थल पर जाकर अमृत वर्षा की। वानर और रीछ जीवित हो गए। यह प्रभु की अद्भुत लीला है। भगवान राम का तात्पर्य है कि लंका में लड़ा जाने वाला युद्ध केवल भौतिक युद्ध नहीं, अपितु उसका आध्यात्मिक स्वरूप भी है। साधक के जीवन में भी यह युद्ध दिखाई देता है। गोस्वामीजी कहते हैं कि लंका के युद्ध में भगवान राम की ओर से लड़ने वाले बंदर और रीछ देवताओं के अंश से ही जन्म लेते हैं, वे सद्गुण और सद्विचारों के प्रतीक हैं। दूसरे पक्ष से लड़नेवाले राक्षस दुर्गुणों के प्रतीक हैं। भौतिक युद्ध में तो दोनों पक्षों के योद्धा मरेंगे, पर आध्यात्मिक युद्ध में एक भी सद्गुण नहीं मरता। क्योंकि साधना-क्रम में यदि एक भी सद्गुण मिट गया तो फिर चरम लक्ष्य की उपलब्धि में कहीं-न-कहीं कमी रह जाएगी। इसीलिए भगवान राम इंद्र से उन्हें जीवित करने के लिए कहते हैं। इंद्र के माध्यम से श्रीराम ने बंदर-भालुओं को जीवनदान दे दिया, पर आश्चर्य है कि बंदर-भालुओं और राक्षसों के शव पासपास ही थे, किंतु अमृत वर्षा से एक भी राक्षस जीवित नहीं हुआ। उन पर अमृत का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा?

गोस्वामीजी लिखते हैं कि ऐसा नहीं कि प्रभु ने बंदरों-भालुओं पर कृपा की और राक्षसों पर नहीं, सत्य तो यह है कि राक्षसों को भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी। कैवल्य का दुर्लभ पद, जो कठिन साधना से प्राप्त होता है, वह राक्षसों को सहजता से उपलब्ध हो गया। साधना से वैराग्य फिर वैराग्य से मुक्ति प्राप्त होती है, पर भगवान ने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। राक्षसों को प्रभु जब मुक्ति देते हैं तो इसकी व्याख्या साधनापरक न होकर कृपापरक ही हो सकती है। कृपा करने में प्रभु स्वतंत्र हैं, अतः व्यक्ति के लिए उचित यही है कि वह साधना अवश्य करे।

अगले मंगलवार को पढ़ें मोरारी बापू का चिंतन...

जीवन दर्शन

श्री श्री रविशंकर
आर्ट आफ लिविंग के प्रणेता आध्यात्मिक गुरु

कर्म बंधन से मुक्ति

संस्कृत में एक सूत्रवाक्य है, 'गहना कर्मणो गतिः' अर्थात कर्मों की गति अत्यंत गूढ़ और न्यारी है। इसे आप जितना अधिक समझते हैं, उतना ही आश्चर्यचकित होते हैं...

जब मन पर पड़ी हुई छाप मिट जाती है, तब आप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ● जागरण आर्काइव

सनातन दर्शन कर्म के सिद्धांत को मानता है। उसके अनुसार, हमारे पिछले जन्मों की क्रियाएं हमारे वर्तमान अनुभवों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए पिछले जन्म का कोई भी व्यक्ति इस जीवन में आपसे पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब लेने के लिए इस जन्म में आपका बेटा, बहू या सास बनकर आ सकता है। यह एक तरह से पुराने ऋण को चुकाने जैसा है। हमारे जीवन में संबंधी होते हैं। विवाह के द्वारा नए संबंध बनते हैं। कभी-कभी बिलगाव का सामना करते हैं। संसार में जो बाहर होता है, वह पहले से बनी हुई फिल्म की तरह है। असली खेल तो उसके पीछे हो रहा है, जिसे हम कर्म कहते हैं।

कर्म सिद्धांत के अनुसार, कुछ कर्मों को बदला जा सकता है, लेकिन कुछ कर्म नहीं बदले जा सकते। दूध से दही बनता है, उसे खट्टा या मीठा बनाया जा सकता है, लेकिन दही को वापस दूध में नहीं बदल सकते। जो कर्म प्रकट हो रहा है और जिसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया है, वह प्रारब्ध कर्म है। आप प्रारब्ध कर्म को बदल नहीं सकते, क्योंकि यह वर्तमान में घटित होने लगा है। संचित कर्म अतीत के कर्मों का परिणाम है। यह मन के भीतर अव्यक्त प्रवृत्तियों के रूप में बना रहता है। संचित कर्मों को आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा उनके अभिव्यक्त होने से पहले ही ठीक किया जा सकता है। हमारे द्वारा किए गए कृत्यों के भविष्य में होने वाले परिणाम आगामी कर्म कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपने कोई अपराध किया है, तो हो सकता है कि आप आज पकड़े न जाएं, लेकिन आप इसी आशंका के साथ जीते हैं कि किसी दिन आप पकड़े जा सकते हैं। जब मन पर पड़ी हुई छाप मिट जाती है, तब आप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। सत्संग, योग और ध्यान नकारात्मक कर्मों के बीज को अंकुरित होने से पहले ही जला देते हैं।

संस्कृत में एक सूत्रवाक्य है, 'गहना कर्मणो गतिः' अर्थात कर्मों की गति अत्यंत गूढ़ और न्यारी है। इसे आप जितना अधिक समझते हैं, उतना ही आप आश्चर्यचकित होते हैं। एक समझदार व्यक्ति कर्मों को अगले जीवन में टालने के बजाय इसी जीवन में ही इनका समाधान करने का निर्णय लेगा, क्योंकि उसे टालने से जटिलताएं और बढ़ सकती हैं। यदि आपको हमेशा प्रशंसा ही मिली है और कभी आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा है, तो आप अशक्त रह जाते हैं, क्योंकि बिना किसी स्पर्धा के केवल विस्तार, आपकी चेतना को कोमल और शक्तिहीन बना देता है। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है, तो आपको लगता है कि आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है, लेकिन जब कोई आपको अपमानित करता है, तो आप संकुचित हो जाते हैं। जिन्होंने आपके जीवन में चुनौतियां पैदा की हैं, वास्तव में आपको उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वे आपकी चेतना को शक्तिशाली बनाने में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, आप चाहते हैं कि आपके माता-पिता, पत्नी, पति या दोस्त एक विशेष प्रकार से व्यवहार करें, लेकिन वास्तविकता में वे लोग अपने स्वभाव और पिछले अनुभवों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार से परेशान होने के बजाय आपको यह समझना है कि आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। भले ही दूसरों का व्यवहार अभद्र हो, आप अपनी आंतरिक शांति को प्रभावित किए बिना इसे साक्षी भाव से देख सकते हैं। हां, यदि आवश्यकता हो तो आप नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों से दूरी बनाएं, लेकिन स्वयं को यह याद अवश्य दिलाएं कि आपकी चेतना बहुत शक्तिशाली है और वह बाहरी चुनौतियों से अप्रभावित रहती है। आपको अपनी आंतरिक शांति और आत्मा की दृढ़ता बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए।

कर्म ही ऐसा तत्व है, जो लोगों को जोड़ता भी है और वही उन्हें अलग भी करता है। यह कुछ लोगों को शक्तिशाली बनाता है और कुछ लोगों को दुर्बल। कर्म ही कुछ लोगों को धनवान बनाता है और कुछ लोगों को निर्धन। इस संसार के जितने भी संघर्ष हैं, वे सभी कर्मों के बंधन हैं। कर्म सभी तर्कों के परे है, यह समझ आपके उत्कर्ष में सहायक बनती है। यह समझ आपको घटनाओं या लोगों में उलझने नहीं देती। यह आपको अपने आत्मा की ओर यात्रा करने के प्रयास में मदद करती है।

केवल मानव जीवन में ही कर्मों के बंधन से मुक्त होने की क्षमता है और केवल कुछ ही लोग हैं, जो इससे मुक्त होने की आकांक्षा रखते हैं। कुछ करने से कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, केवल ईश्वर की कृपा द्वारा ही कर्म के बंधनों से मुक्ति मिल सकती है।

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

सनातन संस्कृति

डा. चिन्मय पण्ड्या
प्रतिकुलपति, देवसंस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार

सकारात्मकता का दृष्टिकोण...

हिंदू पंचांग के अनुसार, श्रावण मास का महत्वपूर्ण पर्व है नागपंचमी। भगवान शिव के प्रिय मास श्रावण में उनके गणों का पूजन भी महत्वपूर्ण है। इस बार **नागपंचमी (नौ अगस्त)** पर्व सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग के साथ आया है। मान्यता है कि नागपंचमी के दिन नागदेवता की पूजा करने से भक्त के सारे संकट दूर होते हैं।

हमारी पौराणिक कथाओं में सर्पों को भगवान शिव और विष्णु के सहयोगी के रूप में दर्शाया गया है और उन्हें शक्ति व ज्ञान के प्रतीक के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म में नागों को देवता भी कहा गया है। नागपंचमी के दिन आठ नागों-अनंत, वासुकि, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीक, कर्कट और शंख की पूजा-अर्चना की परंपरा है।

पौराणिक कथाओं में सर्प के सिर पर मणि होने का उल्लेख मिलता है। पाताल लोक मणियों की आभा से हर समय प्रकाशित रहता है। सभी तरह की मणियों पर सर्पराज का अधिकार है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, सर्प खेतों का रक्षण करते हैं, इसलिए उसका एक नाम क्षेत्रपाल भी है। वे जीव-जंतु, चूहे आदि जो किसान की फसलों को हानि पहुंचाने वाले तत्व हैं, उन्हें नष्ट कर किसानों के खेतों को हरा-भरा रखने में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहायता करते हैं। सर्प के गुण देखने की हमारे पास दृष्टि होनी चाहिए। बिना कारण नाग किसी को डसता नहीं है। नाग अपनी संचित शक्ति यानी विष को किसी को काटकर व्यर्थ खो देना नहीं चाहता। जैसे कोई मनुष्य अपनी वर्षों से उपार्जित शक्ति, तप की पूंजी अथवा धनधान्य को व्यर्थ ही खर्च नहीं करता। पौराणिक कथा के अनुसार, जब देव और दानवों द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब वासुकि नाग प्रभुकार्य में निमित्त बने थे। यह एक प्रकार से संदेश है कि यदि इस तरह के जीव भी सही मार्ग पर आ जाएं तो वे समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना बड़ा योगदान कर सकते हैं।

सप्ताह के व्रत त्योहार

6 अगस्त, मंगलवार : स्वामी करपात्री जी महाराज जयंती
7 अगस्त, बुधवार : मधुस्रवा तृतीया व्रत
8 अगस्त, गुरुवार : वरद चतुर्थी व्रत
9 अगस्त, शुक्रवार : नागपंचमी व्रत
10 अगस्त, शनिवार : कल्कि जयंती
11 अगस्त, रविवार : गोस्वामी श्री तुलसीदास जयंती

वर्ग पहेली- 2713

बाएं से दाएं
1. गरीब, अभावग्रस्त (3)।
5. क्रम या सिलसिला, जोड़-तोड़ (4)। 6. चमड़ा, त्वचा (2)।
7. हर महीने होने वाला (3)।
9. परेशान करना, इच्छा के अनुकूल काम कराना (2,3)। 11. आंख, चक्षु (3)। 14. ध्वनि निकलना (3)।
16. महान, वीर (5)।
18. अत्याचार, संकट, आपत्ति (3)।
19. दुनिया, संसार (2)।
20. जिसका नाम कोई न जानता हो (4)। 22. पृथक, भिन्न (3)।

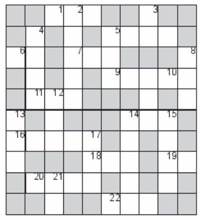

ऊपर से नीचे
2. साफ करने हेतु धोना, स्वच्छ करना (5)।
3. फसल उत्पन्न करने हेतु जमीन या क्षेत्र (2)।
4. शक्तिशाली (4)। 5. देखना (3)।
8. विध्वंस, ध्वस्त (3)। 10. मुसलमानों की ईश प्रार्थना की पद्धति (3)। 12. अनाथ, बिना मां-बाप का (3)। 13. आग की लौ (3)।
14. हर हालत में, किसी भी सूरत में (5)।
15. अप्रसन्नता (4)। 17. रुपया-पैसा (3)।
21. अंतःकरण, चालीस सेर की तौल (2)।

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

ख		प	न	घ	ट		श	र्मा	ना
रा		रि		ना			रा		
ब्र	ह्मा	ब			ह	ड़	ब	ड़ि	यां
		र्त			म				या
म		न	ज	रा	ना			श	ब
ज	ग			त	म	क	ना		र
ह				दि			ज		
ब	द	जु	बा	न			न	सी	ब
		र्मा			कौ		ख		स
सी	मा	ना		है	रा	भ	रा		पा

जागरण सुडोकू- 2713

		4		5		2		7
7			6		9			1
		2					8	
2			9		3	6		8
		3			6		9	
	6			1				4
4	1			3		9		
		8		9			1	
9			4		1			3

कल का हल

6	9	5	1	2	7	4	3	8
2	1	4	9	8	3	6	7	5
3	8	7	4	6	5	2	1	9
8	2	1	3	9	4	5	6	7
7	4	3	2	5	6	8	9	1
9	5	6	8	7	1	3	2	4
4	7	2	5	3	9	1	8	6
5	3	9	6	1	8	7	4	2
1	6	8	7	4	2	9	5	3

आज का भविष्यफल- 06 अगस्त, 2024 मंगलवार

के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वितीया। आज का राहुकाल : अपराह्न 03 बजे से 04 बजकर 30 मिनट तक। आज का दिशाशूल : उत्तर।
आज का पर्व एवं त्योहार : मंगलागौरी व्रत।

कल 07 अगस्त, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : उत्तर
कल का पर्व एवं त्योहार : हरियाली तीज
विक्रम संवत 2081 शके 1946 दक्षिणायण, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, 22 घंटे 07 मिनट तक, तत्पश्चात चतुर्थी पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र तत्पश्चात उत्तराफाल्गुनी, परिघ योग तत्पश्चात शिव योग, सिंह में चंद्रमा 27 घंटे 15 मिनट तक तत्पश्चात कन्या में।

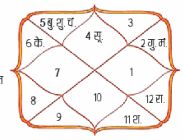

मेष : पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
वृष : अज्ञात भय अशांत रखेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।
मिथुन : आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
कर्क : राजनैतिक महत्वाकांक्षा पूरी होगी। शासनसत्ता का सहयोग।
सिंह : बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
कन्या : रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
तुला : सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।
वृश्चिक : महिला अधिकारी का सहयोग। दांपत्य जीवन में तनाव।
धनु : धर्मगुरु या पिता का सहयोग। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।
मकर : जीवनसाथी से मतभेद होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
कुंभ : जीवनसाथी का सहयोग। कुछ मामलों में तनाव मिल सकता है।
मीन : आर्थिक सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास सार्थक होगा।

राष्ट्रीय फलक

ज्ञानवापी : विवादित ढांचा के मुख्य गुंबद के नीचे जांच करे एएसआइ

विधि संवाददाता, जागरण, वाराणसी

- मुकदमे के वादमित्र ने अदालत से अतिरिक्त सर्वे की मांग की
- मुख्य गुंबद के नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग और अरघा होने का किया दावा

ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ का अधिकार देने को लेकर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से पं. सोमनाथ व्यास, डा. रामरंग शर्मा और पं. हरिहर नाथ पांडेय द्वारा 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई सोमवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) प्रशांत कुमार सिंह की अदालत में हुई। इसमें मुकदमे के वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने ज्ञानवापी में मौजूद विवादित ढांचा के मुख्य गुंबद के नीचे एएसआइ (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) सर्वे कराने की मांग की। वादमित्र की बहस पूरी नहीं होने पर अदालत ने इसे जारी रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख सात अगस्त तय की है।

वादमित्र ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआइ से अतिरिक्त सर्वे कराने के अपने प्रार्थना-पत्र पर अदालत में पक्ष रखा। उनके साथ ही राजेंद्र प्रताप पांडेय व अमरनाथ शर्मा की ओर से दिए गए प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित 18 बिंदुओ पर एएसआइ से अतिरिक्त रिपोर्ट मंगाने का निवेदन किया गया। वादमित्र ने कहा कि विवादित ढांचा के मुख्य गुंबद के नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर का 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग और अरघा मौजूद है। इसे चारों तरफ से ईंट-पत्थरों की दीवार उठाकर उसे मलबा व कंक्रीट, पत्थरों से पाट दिया गया है। ऊपर से भी मोटे-मोटे पत्थरों से ढक दिया गया है। उन्होंने मांग की कि ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए एएसआइ को सर्वे करने का निर्देश दिया जाए। ज्योतिर्लिंग व अरघा की स्थिति का पता इससे भी नहीं चलता तो चार फीट की सुंरग खोदकर जांच की जाए। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के नीचे और ऊपर के हिस्से की जांच की मांग भी की।

ज्ञानवापी। फाइल

मंदिर पक्ष ने कहा- शाही ईदगाह कमेटी को पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं

विधि संवाददाता, प्रयागराज

- आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के एएसआइ सर्वे की मांग पर हाई कोर्ट में सुनवाई
- एएसआइ को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए मिले सात दिन, अब सुनवाई 12 को

आगरा स्थित जामा मस्जिद की सीढ़ियों (जिसमें भगवान श्रीकृष्ण के विग्रह दबे होने का दावा है) का भारतीय पुरातत्व सर्वे (एएसआइ) से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर शाही ईदगाह कमेटी को पक्षकार बनाए जाने का विरोध किया गया है। मंदिर पक्ष की तरफ से आपत्ति दायर की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को मथुरा स्थित ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव व अन्य और भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सिविल वाद संख्या तीन व 10 की सुनवाई के दौरान यह आपत्ति की गई। अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को दोपहर दो बजे होगी।

पहले केस (वाद संख्या तीन) में शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंध समिति को पक्षकार बनाने की अर्जी पर वादी अधिवक्ता आरएस यादव व महेंद्र प्रताप सिंह ने आपत्ति दाखिल करने को समय मांगा। एएसआइ के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने जवाबी हलफनामा के लिए समय की मांग की। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इसके लिए सात दिन का समय दिया। वादी का दावा है कि 1670 में मथुरा में श्रीकृष्ण भगवान का मंदिर तोड़ने के बाद विग्रह आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफनाया गया है। वैज्ञानिक जांच से इसका पता चल सकेगा। वादी अधिवक्ताओं का कहना था कि शाही ईदगाह मस्जिद समिति का मामले से कोई सरोकार नहीं है। उसे पक्षकार बनाने का जरूरत नहीं है। वह (शाही ईदगाह समिति) केवल मामले को लटकाए रखने के लिए पक्षकार बनना चाहती है।

ताजमहल में महिला ने लहराया भगवा वस्त्र, चढ़ाया गंगाजल

जागरण संवाददाता, आगरा: ताजमहल में सावन के तीसरे सोमवार को मुख्य मकबरे पर अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला सभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने भगवा वस्त्र लहराया। सीआइएसएफ के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। इससे संबंधित वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने के बाद महासभा ने दावा किया कि ताजमहल में भगवा ध्वज लहराने के साथ बोतल में ले जाया गया गंगाजल चढ़ाया गया है।

दिनभर पूछताछ के बाद शाम को मीरा के पति से माफीनामा लिखवाने के बाद छोड़ दिया गया। महासभा ताजमहल को तेजोमहालय शिव मंदिर होने का दावा करती है। मीरा पिछले सोमवार को भी कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंची थीं। शनिवार को महासभा के दो पदाधिकारियों विनेश चौधरी और श्याम बाबू ने ताजमहल में गंगाजल चढ़ाया था। सीआइएसएफ की तहरीर पर दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था।

उधर, मीरा राठौर ने कहा कि ताजमहल में उन्होंने भगवा ध्वज लहराने के साथ गंगा जल चढ़ाया था। उन्होंने सीआइएसएफ को किसी तरह का माफीनामा लिखकर नहीं दिया है। मेरे पति से माफीनामा लेने का क्या मतलब होता है। एएसआइ के अधीक्षण पुरातत्वविद डा. राजकुमार पटेल ने बताया कि भगवा वस्त्र लहराने वाली महिला के विरुद्ध सीआइएसएफ की ओर से पुलिस को भी सूचना दी गई थी। स्मारक में इस तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। इन्हें रोकने के लिए व्यवस्था सख्त की जा रही है।

श्रद्धा का महासावन

श्रावण महीने में शीघ्र प्रसन्न होते हैं भगवान शिव

हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि पार्वती ने शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए इसी महीने तपस्या की थी। शिव के पूजन से लंबी आयु, सुख, समृद्धि और मनोवांछित जीवन साथी मिलता है। भगवान शिव श्रावण में ही शिवलिंग के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। शिव भारतीय संस्कृति को संजीवनी प्रदान करने वाले देव हैं। शिव को कल्याण का प्रतीक माना जाता है। शिव शब्द के उच्चारण एवं ध्यान मात्र से ही आनंद मिलता है। श्रावण में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। पुराणों के अनुसार इस माह रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। श्रावण में 11 रुद्र की 11 दिन पूजा करने से विशेष फल मिलता है। शिवलिंग का दूध, धतूरा, बिल्व पत्र व पांच फलों के रस से अभिषेक करना लाभ देता है। श्रावण में ज्योतिर्लिंग के दर्शन व पूजन से पाप कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण में चारों ओर हरियाली होती है। प्रकृति इस महीने नया शृंगार करती है। शिवालयों की घंटियों से वातावरण में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस महीने हम अंदर से खुद को और सशक्त एवं सक्षम कर सकते हैं।

श्रीश्री 1008 राघवानंद गिरी महाराज, पुजारी, महादेव मंदिर गसोता, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

जल्द 100 % एथनाल से चलने वाली कारें बनाएंगी भारतीय कंपनियां

नई दिल्ली, एएनआइ: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि कई भारतीय कंपनियां भारत में 100 प्रतिशत एथनाल से चलने वाली कारों और दोपहिया का उत्पादन करने के लिए संयंत्र स्थापित कर रही हैं।

टोयोटा की ओर से बनाई गई ऐसी ही गाड़ी में संसद पहुंचे गडकरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह दुनिया की पहली गाड़ी है जिसमें फ्लेक्स इंजन है। इसका कार्बन उत्सर्जन शून्य है और यह गन्ने के रस, गुड़ व मक्का से उत्पादित एथनाल पर चलती है। एक से ज्यादा ईंधन या मिश्रित ईंधन से चलने वाले इंजन को फ्लेक्स इंजन कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टोयोटा के अलावा टाटा और सुजुकी 100 प्रतिशत एथनाल या फ्लेक्स इंजन से चलने वाली कारों के उत्पादन पर काम कर रही हैं। दूसरी ओर, टीवीएस और हीरो फ्लेक्स इंजन वाले दोपहिया व स्कूटर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।

बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़े श्रद्धालु

पवित्र श्रावण मास के तीसरे सोमवार को देशभर में शिवालयों में भक्तों का तांता दिखा। इस दौरान झारखंड के देवघर जिले में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़े श्रद्धालु। प्रेट्र

नौ माह के बच्चे को मंदिर को किया दान, दो साल बाद मिलेगी महंत की पदवी

जागरण संवाददाता, बागपत

- नामकरण के बाद बालक को अब बाबा रामगोपाल गिरि नाम से पुकारा जाएगा
- दो साल तक बालक रहेगा मां के पास, इसके बाद आ जाएगा मंदिर में

बागपत में किशनपुर बराल गांव के बाबा महावीर गिरि गोपाल मंदिर में बच्चे को दान करने की प्रक्रिया पूर्ण करते स्वजन। जागरण

नौ माह के बच्चे को उसके माता-पिता ने एक मंदिर को दान कर दिया। मंदिर के महंत प्रयागराज गिरि ने बालक का नामकरण किया। अब बालक को बाबा रामगोपाल गिरि नाम से पुकारा जाएगा। बालक दो साल की आयु तक मां का दूध पीएगा, तब तक वह अपने माता-पिता के पास ही रहेगा। दो साल पूर्ण होने पर वह मंदिर में आ जाएगा। इस मौके पर मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया गया।

उत्तर प्रदेश में बागपत जिले के किशनपुर बराल स्थित बाबा महावीर गिरि गोपाल गिरि मंदिर के महंत ने बताया कि मीनाक्षी देवी ने मंदिर में मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने पर उन्होंने अपने नौ माह के पोते चेतन को धूना (स्थायी हवनकुंड) पर रखकर दान कर दिया। बच्चे के पिता मोनू कश्यप किराये की गाड़ी चलाते हैं। महंत प्रयागराज गिरि का कहना है कि इस गद्दी से लोगों की आस्था जुड़ी है। गद्दी को कोई वारिस नहीं मिल रहा था। बालक के आने से वारिस मिल सकेगा। स्वजन ने इच्छा से बच्चे को दान किया है। रमाला थाना प्रभारी महेंद्रपाल सिंह का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है।

बाल संरक्षण आयोग ले सकता है संज्ञान: तीन साल पूर्व हरियाणा के हिसार क्षेत्र में समाधा मंदिर में एक माह के मासूम बच्चे को दान करने के मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बैंदा ने मंदिर में बच्चों से जुड़ा रिकार्ड तलब किया था। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया। कार्रवाई की स्थिति देख परिवार ने बच्चे को वापस ले लिया था। कानून के जानकारों का कहना था कि ऐसा करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व चाइल्ड एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है। अगर किसी माता-पिता को अपना बच्चा छोड़ना है तो उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या जिला बाल संरक्षण यूनिट के समक्ष जाना होगा। माता-पिता की काउंसिलिंग होती है। परिवार को दो माह का समय दिया जाता है। इस अवधि में अगर मां-बाप का मन बदल जाता है तो वह बच्चा वापस ले सकते हैं।

****

अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर गिराया पहला परमाणु बम

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में आज ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। इसमें लगभग डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके तीन दिन बाद नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान से आत्मसमर्पण कर दिया।

इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनीं गर्ट्रूड

1926 में आज ही अमेरिकी ओलिंपिक तैराक गर्ट्रूड एडरले इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थीं। चैनल पार करने में उन्हें 14 घंटे, 34 मिनट लगे थे। गर्ट्रूड से पहले केवल पांच पुरुष इस चैनल को तैरकर पार कर पाए थे।

राजस्थान को सूखा मुक्त कराने में डा. राजेंद्र का अहम योगदान

पर्यावरणविद् डा. राजेंद्र सिंह का जन्म 1959 में आज ही उप्र के बागपत में हुआ था। 1980 में जयपुर शिक्षा विभाग में नौकरी से करियर शुरू किया। राजस्थान में पानी का संकट देख नौकरी छोड़ जल संरक्षण के प्रति खुद को समर्पित कर दिया। 1986 में गांवों में पैदल यात्रा कर लोगों को पुराने चेक बांधों के पुनर्निर्माण के लिए शिक्षित किया। अरावली, रूपारेल, सरसा व भगाणी जैसी कई नदियों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। राज्य में चार हजार से अधिक जोहड़ (वर्षा जल भंडारण) भी बनवाए।

सौर सक्रियता ने तोड़ा 23 वर्ष का रिकार्ड

नया जोखिम ▸ वर्ष 2001 की तरह ही अति सक्रिय है सूर्य, अगले साल अक्टूबर तक रहेगा चरम पर

रमेश चंद्रा ● जागरण

नैनीताल : 25वें सौर चक्र में सूरज की गतिविधियां उफान पर हैं। इस वर्तमान चक्र में सूर्य की सतह पर उठ रही सौर भभूकाएं (सनस्पाट) और विस्फोट पिछले 23 साल में सर्वाधिक हो चुके हैं। अक्टूबर 2025 तक यह चक्र चरम पर रहेगा। ऐसे में सनस्पाट के साथ जन्म लेने वाली ज्वालाएं पिछली सदी के भी रिकार्ड तोड़ सकती हैं।

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) नैनीताल के पूर्व कार्यवाहक निदेशक व सौर विज्ञानी डा. वहाबउद्दीन ने बताया कि वर्तमान 25वां सौर चक्र अपेक्षा से कहीं अधिक छलांग लगा रहा है। सूर्य की सतह पर आए दिन विस्फोट हो रहे हैं और जबर्दस्त ज्वालाएं भभक रही हैं। तीन-चार अगस्त को भी दो विस्फोट हुए। इनमें मध्यम (एम) श्रेणी की दो ज्वालाएं उठीं। आने वाले दिनों में भी विस्फोटों का दौर जारी रहने का अनुमान है।

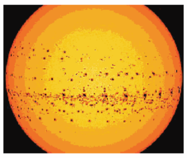

जुलाई में सूर्य पर बने सन स्पाट। सौ. वहाबउद्दीन

डा. वहाबउद्दीन के अनुसार, सनस्पाट की संख्या 23 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जिस तरह 2001 में सनस्पाट सक्रिय थे, उसी तरह 2024 में भी नजर आ रहे हैं। सूर्य पर नजर रखने वाली स्पेस एजेंसी रायल आब्जर्वेटरी आफ बेल्जियम के सोलर इन्फ्लुएंस डेटा एनालिसिस सेंटर के अनुसार इस बार जुलाई में औसत सनस्पाट की संख्या 196.5 दर्ज की गई। इसी तरह की स्थिति दिसंबर 2001 में देखी गई थी। वर्तमान सौर चक्र दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था और तब अनुमान लगाया गया था कि यह सौर चक्र 24वें चक्र की तरह कमजोर रहेगा। मगर पूर्वानुमान गलत साबित हुआ और 24वें सौर चक्र को पीछे छोड़ दिया है। अब 20वीं शताब्दी के शक्तिशाली चक्रों को टक्कर देने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस चक्र की तीव्रता से पिछले कुछ महीनों में दक्षिण प्रशांत, मध्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में अरोरा के साथ भू-चुंबकीय सौर तूफान दिखा है। इस सौर चक्र की चरमता अक्टूबर 2025 तक सक्रिय रहने की संभावना है।

सेटेलाइट व इलेक्ट्रिकल उपकरणों की इन ज्वालाओं से सुरक्षा जरूरी

डा. वहाबउद्दीन ने बताया कि शनिवार को सूर्य की सतह पर सनस्पाट संख्या से यह पता चलता है कि एआर 3775 से एम-7 श्रेणी की ज्वाला भभकी है। जबकि सूर्य के ठीक पीछे पूर्वी हिस्से पर अज्ञात सनस्पाट से एम 5.4 श्रेणी क्षमता वाले विस्फोट के साथ ज्वाला उठी है। भारतीय सोलर मिशन आदित्य एल-1 व नासा की सोलर डायनामिक आब्जर्वेटरी (एसडीओ) समेत दुनिया की तमाम सोलर वेधशालाएं सूर्य की निगरानी कर रही हैं। सूर्य की निगरानी का उद्देश्य पृथ्वी की ओर आने वाले सौर तूफानों से आसमान में हमारे सेटेलाइट्स को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही, धरती के इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रिकल उपकरणों का बचाव करना है

हिमयुग की समाप्ति के स्तर तक पहुंचे दक्षिण अमेरिका के एंडीज ग्लेशियर

नई दिल्ली, प्रेट्र : बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण तेजी से पिघलते ग्लेशियर दुनियाभर में चिंता के कारण बने हुए हैं। इस क्रम में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक नए शोध यह उजागर कर चिंता और बढ़ा दी है कि दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर 11,700 साल पुराने हिमयुग की समाप्ति होने के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर खिसक गए हैं। एंडीज दक्षिण अमेरिका में प्राथमिक पर्वत श्रृंखला होने के साथ ही दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। शोधकर्ताओं के अनुसार, निष्कर्षों से पता चलता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पहले से ही अपने होलोसीन रेंज के बाहर और एंथ्रोपोसीन में गर्म हो चुके हैं। ग्लेशियरों को अब होलोसीन काल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके बजाय, उन्हें एंथ्रोपोसीन काल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कि 'उनके अंत की कहानी' हो सकती है।

स्वाद ही नहीं रंग भी है तीखा

मिर्च के बिना भोजन का संपूर्ण स्वाद मिलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जहां तीखी मिर्च स्वाद देती है, इसका चटक रंग एक अलग अनुभूति देता दिखता है। दक्षिण-पश्चिम चीन के चोंगकिंग में मिर्च बिक्री केंद्र पर इसका रंग और तीखापन इसकी बिक्री का प्रमुख कारण है और इसके लिए कर्मचारी इसकी छंटाई में पीछे नहीं रहते। एएफपी

इधर-उधर की

पांच मिनट में पार्किंग टिकट न खरीदने पर देने पड़े 11 लाख रु.

इंटरनेट की वजह से टिकट नहीं खरीद पाईं हन्ना। इंटरनेट मीडिया

लंदन, एजेंसी : ब्रिटेन की हन्ना राबिंसन को अवैध कार पार्किंग के लिए जुर्माने के रूप में इतनी रकम भरनी पड़ी जितने में भारत में आप एक अच्छी नई कार खरीद लेंगे। हन्ना को पांच मिनट की पार्किंग के लिए 11 हजार पाउंड यानी लगभग 11 लाख रुपये देने पड़े। हन्ना ने बताया कि नए नियम में कहा गया है कि ग्राहकों को आगमन के पांच मिनट के भीतर अपना टिकट खरीदना होगा। फीथंस लीजर सेंटर में कार पार्क के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने से वह समय पर टिकट नहीं खरीद पाईं।

फेफड़े के वायरल संक्रमण के इलाज का मिला एक प्रभावी उपाय

नई दिल्ली, आइएएनएस : फेफड़े में वायरल संक्रमण के इलाज के लिए विज्ञानियों ने एक नए मैक्रोफेज की पहचान की है। यह फेफड़े के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यह महत्वपूर्ण खोज इम्यून रेस्पांस (प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया) के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है और नए पुनरुत्पादक उपचारों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। बता दें कि मैक्रोफेज एक विशिष्ट प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं को चारों तरफ से घेर कर उसे मार डालने के साथ ही मृत कोशिकाओं को हटाता और इम्यून सिस्टम की अन्य कोशिकाओं को सक्रिय होने के लिए उत्प्रेरित करता है।

▸ नए मैक्रोफेज की हुई पहचान, जो उपचार में ला सकता है क्रांतिकारी बदलाव

▸ यह वायुकोशीय मरम्मत के लिए एक नए तंत्र का विन्यास बनाने होता है सहायक

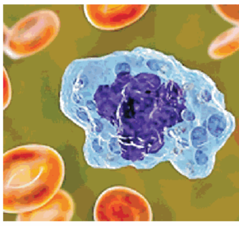

फेफड़े के संक्रमण के इलाज की दिखी नई उम्मीद। प्रतीकात्मक

वैसे तो श्वसन संबंधी वायरस अक्सर हल्के लक्षण पैदा करते हैं, लेकिन ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जैसा कि कोविड-19 महामारी में सामने आया है। इस तरह के संक्रमण फेफड़ों के बड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से एल्वियोली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो गैस विनिमय के लिए आवश्यक हैं। इन संरचनाओं की अप्रभावी मरम्मत के परिणामस्वरूप तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम (एआरडीएस) या फेफड़ों के कार्य में दीर्घकालिक कमी हो सकती है, जिससे लंबे समय तक थकान के साथ कामकाज की क्षमता कम हो सकती है।

रेस्पिरेटरी संक्रमण के तीव्र चरण के दौरान मैक्रोफेज की भूमिका स्थापित हो गई है, लेकिन उबरने के चरण में उसके कार्य को कम समझा जा सका है। जीआइजीए इंस्टीट्यूट के विज्ञानियों के अध्ययन से पता चलता है कि मैक्रोफेज का एक अलग समूह, जो अद्वितीय मार्करों की विशेषता वाला होता है और प्रारंभिक रिकवरी के दौरान क्षणिक रूप सक्रिय होता है, पल्मोनरी (फुफ्फुसीय) एल्वियोली के पुनर्जनन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

डा. कोरालिन रेडमेंकर और प्रो. थामस मैरीचल के नेतृत्व में हुए शोध में बताया गया है कि फ्लो साइटोमेट्री, प्रतिदीप्ति माइक्रोस्कोपी और एकल-कोशिका आरएनए अनुक्रमण सहित उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया। शोधकर्ताओं के मुताबिक, उनके निष्कर्ष इन असामान्य मैक्रोफेज को शामिल करते हुए वायुकोशीय मरम्मत के लिए एक नया तंत्र का विन्यास करते हैं।

वायुकोशीय कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में उनकी विशेषताओं, उत्पत्ति और भूमिका की पहचान की गई है। यह विशेष रूप से टाइप 2 वायुकोशीय एपिथेलियल (शरीर को अंदर-बाहर के ढकने वाली) कोशिकाओं को निशाना बनाते हैं। यह अध्ययन इस धारणा को चुनौती देता है कि संक्रमण के बाद के मैक्रोफेज पूरी तरह से रोगजनक होते हैं। इन मैक्रोफेज को बढ़ाने या उत्तेजित करने से फेफड़ों के पुनर्जनन में सुधार और गंभीर श्वसन संक्रमण से जटिलताओं के प्रबंधन के लिए नए उपचार हो सकते हैं। यह खोज श्वसन संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए नई संभावनाएं प्रदान करती है।

अपने उत्पत्ति स्थान पर अधिक संक्रामक होते हैं टीबी के रोगाणु

अनुसंधान

टीबी का कारगर इलाज होने के बावजूद दुनिया में अब भी हर वर्ष लाखों लोगों की इससे मौत हो रही है। शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में पाया है टीबी के रोगाणु खास भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कम या अधिक संक्रामक होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में टीबी के रोगाणु और मानव होस्ट सैकड़ों-हजारों वर्ष से एक साथ रह रहे होते हैं। इसलिए उनकी संक्रमण दर भी अलग होती है। टीबी मरीज के निकट संपर्क से संक्रमित होने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि मानव और टीबी रोगाणु एक ही स्थान साझा करते हैं या नहीं। इनका प्रभाव मूलनिवासियों पर अधिक प्रभावी पाया गया।

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए कुल 5,256 टीबी मरीजों और उनके निकट संपर्क में आए 28,889 लोगों को शामिल किया। शोध दल ने कहा कि उनके निष्कर्ष से टीबी के उपचार और उससे सुरक्षा में मदद मिलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया में हर वर्ष एक करोड़ से अधिक लोग टीबी से संक्रमित होते हैं और करीब 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। शोध दल ने मिश्रित आबादी में टीबी मरीजों के संपर्क में आए मौजूद टीबी के रोगाणुओं की खास क्षेत्र के रोगाणुओं से तुलना की।

विश्लेषण में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में विकसित टीबी के रोगाणुओं की संक्रमण दर एक व्यापक क्षेत्र में विकसित टीबी के रोगाणुओं की अपेक्षा 14 प्रतिशत कम पाई गई और सक्रिय टीबी दर भी 45 प्रतिशत कम रही। शोध दल ने कहा कि इस तरह टीबी उपचार भौगोलिक क्षेत्र में विकसित रोगाणुओं के अनुसार अधिक प्रभावी हो सकता है। (एएनआइ)

स्क्रीन शाट

...तो इन्हें अपने वश में करना चाहेंगी मोनालिसा

शमशान चंपा धारावाहिक में डायन के रोल में होंगी मोनालिसा। @aslimonalisa (इंस्टाग्राम)

इन दिनों कई सुपरनेचुरल शो छोटे पर्दे पर आ रहे हैं। इस कड़ी में धारावाहिक शमशान चंपा में मोनालिसा डायन के रोल में नजर आएंगी। 20 अगस्त से शेमारू उमंग पर आरंभ हो रहे इस शो में उनके पास किसी को भी वश में करने का सुपरपावर होगा। अगर मौका मिले किसी को वश में करने का तो आप किसे वश में करना चाहेंगे? इस बाबत मोनालिसा का कहना है कि वह अपने पति और अभिनेता विक्रांत सिंह राजपूत को वश में करेंगी। पति को वश में करने के कारणों का जिक्र करते हुए दैनिक जागरण से बातचीत में मोनालिसा कहती हैं, मैं अपने पति को वश में करना चाहूंगी, क्योंकि वह कलाकार हैं, कई अभिनेत्रियों के साथ काम करते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि सेट पर क्या चल रहा है। अब पत्नी हूं तो थोड़ी चिंता रहती ही है। हालांकि एक ही क्षेत्र में काम करने के अपने फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। आगे इस शो में डायन के रोल को लेकर मोनालिसा कहती हैं, मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा अच्छी लड़की की भूमिका निभाते आई हूं। मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि निगेटिव रोल कर पाऊंगी। जब नजर शो मिला था तो कंफर्ट जोन से बाहर निकली। क्या मोनालिसा ने भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बनाई है? इस पर वह कहती हैं कि दूरी नहीं बनाई है। वक्त मिलेगा तो वहां की फिल्में करूंगी।

घुसपैठिया में काम आई मुक्काबाज फिल्म की ट्रेनिंग

कहा जाता है कि अगर इंसान ने जिंदगी में कुछ सीखा है तो वह कभी बेकार नहीं जाता है। अभिनेता विनीत कुमार सिंह के लिए उनकी फिल्मों में पिछले प्रशिक्षण काम आए। विनीत नौ अगस्त को प्रदर्शित हो रही फिल्म घुसपैठिया में पुलिसकर्मी की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म के एक दृश्य में विनीत खलनायक की भूमिका निभा रहे अक्षय ओबेराय के चेहरे पर दनादन मुक्के मारते हैं। इस बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में फिल्म मुक्काबाज अभिनेता विनीत कहते हैं, 'फिल्म के एक्शन निर्देशक शिव आर्यन चाहते थे कि हमारी लड़ाई फिल्म में वास्तविकता के करीब दिखे। ऐसा नहीं कि एक मुक्का मारने पर सामने वाला दस फीट पीछे जा रहा है। पूरा पटका-पटकी, मारामारी दिखाना था। इस क्रम में जहां मेरा किरदार जीतता है, वहां एक मौके पर दनादन मुक्के मारता है। यह मेरा सिग्नेचर स्टाइल है। यहां मुझे मुक्काबाज फिल्म वाली ट्रेनिंग काम आई, वो तो मेरी नसों में है, जैसे ही मुक्केबाजी की बात आती है, तुरंत ही मेरे हाथ-पांव चलने लगते हैं।'

लालच से बचें: सुसी गणेशन निर्देशित फिल्म घुसपैठिया साइबर क्राइम के विषय पर आधारित है। साइबर क्राइम से बचाव पर विनीत कहते हैं, 'मैं साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए काम करने वाली कुछ संस्थाओं और कुछ पुलिसकर्मियों से भी मिला। मैंने जाना कि साइबर क्राइम से बचने का सबसे पहला तरीका है कि लालच से बचे, फिर वह पैसे, आनंद, फेम किसी भी किस्म का लालच हो। इसके बाद भी अगर आप फंसते हैं, तो आपको डरना नहीं है। अगर आप डरे तो सामने वाले को ताकत मिलती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले अपने स्वजनों को बताओ। अपने आस-पास के थाने में जाकर शिकायत दर्ज करें।'

फिल्म घुसपैठिया में पुलिसकर्मी की भूमिका में नजर आएंगे विनीत ● @vineet_ksofficial (इंस्टाग्राम)

स्क्रीन मिलने के मामले में संतुलन जरूरी

पिछले वर्ष अपनी फिल्म सिया के प्रदर्शन के समय विनीत ने उसे पर्याप्त स्क्रीन न मिलने की शिकायत की थी। वह कहते हैं, 'इस मामले में पश्चिमी देश हमसे बेहतर हैं। वहां बहुत तरीके की फिल्में बनती हैं, कमर्शियल सिनेमा के साथ-साथ विषय प्रधान समानांतर सिनेमा भी चलता है। वहां के सिनेमा में एक संतुलन है, हर तरीके के सिनेमा को जगह मिलती है। अगर यहां भी स्क्रीन मिलने के मामले में उस तरह का संतुलन हो तो अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि आप छोटी फिल्मों को स्क्रीन देंगे तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। सत्या, पान सिंह तोमर, मुक्काबाज तो ऐसी ही फिल्में थी।'

सामाजिक कार्यों से भी है जुड़ाव

सिनेमा के साथ-साथ विनीत अपने गृहनगर वाराणसी में होने वाले सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहते हैं। वह बताते हैं, 'वाराणसी मैं जाता रहता हूं। अभी एक एनजीओ से वृक्षारोपण से जुड़े अभियान का प्रस्ताव आया है, 10 अगस्त के बाद उसे करना है। इसे कुछ युवाओं ने मिलकर शुरू किया है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते। उनके साथ खड़े होना मेरा फर्ज है। हम लोग भी ऐसे ही थे। हर जगह हाथ-पांव मारते थे।'

बड़ी कतार

आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में विनीत बताते हैं, 'आगे एक वेब सीरीज रंगीन है, जिसे कबीर खान ने प्रोड्यूस किया है। इसके बाद एक फिल्म है मैच फिक्सिंग, जिसमें मैं केंद्रीय भूमिका में हूं। इसके अलावा विक्की कौशल अभिनीत फिल्म छावा में भी हूं। एक अन्य फिल्म सुपरहीरो आफ मालेगांव है। अनुराग कश्यप के साथ भी एक फिल्म कर रहा हूं, उसकी शूटिंग चल रही है। एक एंथोलाजी फिल्म भी है। इन फिल्मों में एक्सेल एंटरटेनमेंट और मैडाक फिल्मों जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस भी हैं।'

हाउसफुल 5 में हुई फरदीन की एंट्री, अक्षय के साथ होगी पांचवीं फिल्म

साल 2010 में प्रदर्शित फिल्म हाउसफुल से शुरू हुई हाउसफुल फ्रेंचाइजी अब पांचवीं फिल्म तक पहुंच चुकी है। अक्टूबर में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। इससे पहले फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला इसकी स्टारकास्ट को बड़ी और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार, चंकी पांडे और रितेश देशमुख के अलावा जहां इस फ्रेंचाइजी की अलग-अलग फिल्मों का हिस्सा रह चुके बाबी देओल और अभिषेक बच्चन की वापसी हो रही है। वहीं इस फिल्म में संजय दत्त और नाना पाटेकर जैसे कुछ नए चेहरे भी दिखेंगे। अब इस फिल्म में अभिनेता फरदीन खान के भी जुड़ने की खबरें हैं। फरदीन ने इससे पहले साल 2007 में प्रदर्शित फिल्म 'हे बेबी' में अक्षय के साथ काम किया था। अब दोनों एक साथ स्वतंत्रता दिवस पर प्रदर्शित होने जा रही फिल्म 'खेल खेल में' फिर साथ नजर आएंगे। हाउसफुल 5 फरदीन और अक्षय की एकसाथ पांचवीं फिल्म होगी। रिपोर्टों के अनुसार, फिल्म में फरदीन की भूमिका काफी मनोरंजक होगी। उन्होंने प्रस्ताव मिलने के तुरंत बाद ही इस भूमिका के लिए हां कर दी। इस भूमिका के लिए उनके साथ ही अभिनेता अर्जुन रामपाल से भी संपर्क किया गया था।

फिर साथ नजर आएंगे अक्षय व फरदीन। @fardeenfkhan (इंस्टाग्राम)

अलग-अलग भाषाओं में स्वयं को ढालना चुनौती मानती हैं जोया

वर्तमान में कई दक्षिण भारतीय निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों को हिंदी में भी डब करके पैन इंडिया स्तर पर प्रदर्शित कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा में पहले काम कर चुके कुछ कलाकार इसे सिनेमा इंडस्ट्री का अच्छा कदम मानते हैं। लाल कप्तान फिल्म की अभिनेत्री जोया हुसैन भी उन्हीं में से हैं। हिंदी के अलावा उन्होंने साल 2021 में प्रदर्शित तमिल फिल्म कादन (हिंदी में हाथी मेरे साथ और तेलुगु में अरण्य) में काम किया है। दैनिक जागरण से बातचीत में वह बताती हैं, 'मैंने मलयालम, तेलुगु, बांग्ला और तमिल फिल्में बहुत देखी हैं। पैन इंडिया फिल्मों में अलग-अलग इंडस्ट्री के कलाकारों को उनकी मातृभाषा या उनकी शैली में बातें करना देखना अच्छा लगता है। मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने ऐसी एक फिल्म की है, उम्मीद है कि मैं ऐसी और भी फिल्में करूंगी। अलग-अलग भाषाओं में स्वयं को ढालना और उसी भाषा के अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाना मुश्किल तो होता है, लेकिन उस चुनौती के भी अलग मजे होते हैं। मैंने ज्यादा भाषाएं अभी तक सीखी तो नहीं है, लेकिन अलग-अलग फिल्मों में मैंने तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, बुंदेलखंडी और भोजपुरी भाषाएं बोली है।' जोया आगामी दिनों में फिल्म ग्राउंड जीरो में नजर आएंगी।

फिल्म ग्राउंड जीरो में नजर आएंगी जोया। @zyhssn (इंस्टाग्राम)

करण को रोहित के साथ करना है काम। @karanveermehra (इंस्टाग्राम)

बिग बास से बड़ा खतरा कुछ नहीं : करण वीर

कलाकार जब अपने पात्रों का मुखौटा पहनकर दर्शकों के सामने आते हैं तो अक्सर उन्हें वही व्यक्ति समझ लिया जाता है। यही कारण है कि सितारे जब रियलिटी शो में आते हैं तो वह नर्वस होते हैं कि उनके प्रशंसक उन्हें कितना अपनाएंगे, क्योंकि वहां वास्तविक व्यक्तित्व सामने आता है। ऐसे ही परेशान अभिनेता करण वीर मेहता भी थे, जब उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 14 में भाग लिया। दैनिक जागरण से बातचीत में वह कहते हैं कि मैं नर्वस था। अब तक पात्रों के पीछे छुपता आया हूं, पहली बार दर्शकों को जानने को मिल रहा है कि मैं कैसा हूं। किन चीजों से डर लगता है, मैं मानसिक और शारीरिक तौर पर कितना मजबूत या कमजोर हूं, वह सब देख रहे हैं। क्या करण कभी बिग बास जाना चाहेंगे? इस पर वह कहते हैं कि वहां जाना ज्यादा खतरनाक होगा। उससे बड़ा खतरा कुछ नहीं है। मुझे तो उस शो से डर लगता है। लेकिन कहते हैं न कि ना नहीं कहना चाहिए, जब आफर आएगा तो सोचूंगा। क्या खतरों के खिलाड़ी 14 के मेजबान और फिल्ममेकर रोहित शेट्टी से करण ने काम मांगा? इस पर वह कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके साथ इस शो में शिष्य और गुरु वाला माहौल था। आगे कभी मौका मिलेगा तो कहना चाहूंगा कि कुछ काम हो तो दीजिएगा।

...तो सीरियल किलर बनेंगी माधुरी दीक्षित

डार्क भूमिका में नजर आ सकती हैं माधुरी ● जागरण आर्काइव »

वेब सीरीज द फेम गेम से डिजिटल प्लेटफार्म पर पदार्पण करने के बाद माधुरी अब एक और सीरीज करने की तैयारी में हैं। खबरों के मुताबिक वह साइकोलाजिकल थ्रिलर में सीरियल किलर की भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रही हैं। इस शो को नागेश कुकुनूर निर्देशित करेंगे। शो का शीर्षक मिसेज देशपांडे है। सूत्रों के मुताबिक शो की कहानी यूं है कि पुलिस किस तरह एक सीरियल किलर को काम पर रखती है और दूसरे सीरियल किलर के तौर-तरीकों को समझने और उसे पकड़ने के लिए उसके दिमाग का इस्तेमाल करती है। यह शो एक फ्रेंच सीरीज का रीमेक है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो शो की शूटिंग मानूसन के बाद आरंभ हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक शो के लिए कास्टिंग चल रही है। इस शो के अलावा नागेश ने राजीव गांधी हत्यांकाड़ की जांच पर आधारित शो का भी निर्देशन किया है।

पैसे देकर हीरो ने चलवाई फिल्म

जब बात हो तीखी प्रतिक्रिया देने की तो फिल्मकार राम गोपाल वर्मा का नाम शीर्ष पर आता है। अब उन्होंने एक तेलुगु स्टार को लेकर बात की है, जिसने खुद के पैसे लगाकर अपनी फिल्म थिएटर में चलवाई। एक साक्षात्कार के दौरान राम गोपाल ने कहा, 'तेलुगु इंडस्ट्री में स्वतंत्र निर्माता अब भी मौजूद हैं, क्योंकि अब भी तेलुगु इंडस्ट्री हीरो के अहंकार पर चलती है। वहां के हीरो को कार्पोरेट स्टूडियो पसंद नहीं हैं, क्योंकि कार्पोरेट वाले रोजगार देने वाले लोग होते हैं। वे केवल एंग्रीमेंट के अनुसार चलते हैं। उदाहरण के तौर पर बांबे (मुंबई) की एक कार्पोरेट कंपनी ने एक तेलुगु स्टार के साथ बड़ी फिल्म बनाई। घाटा होने के बाद फिल्म को कार्पोरेट कंपनी ने थिएटर से हटाना चाहा। फिर उस स्टार ने कार्पोरेट के प्रमुख को फोन किया और कहा कि मैं अपने पैसे लगाऊंगा, लेकिन आपको इसे इतने समय तक थिएटर में चलाना होगा। जब तक हीरो पैसा खर्च कर रहा है, कार्पोरेट के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। यह तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ही हो रहा है। ऐसा बालीवुड में कभी नहीं देखा गया।'

राम गोपाल वर्मा ने तेलुगु इंडस्ट्री पर साधा निशाना ● इंस्टाग्राम

****